SHORT DURATION DISCUSSION

Unprecedented price rise of commodities in the country

डॉ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सारा देश महंगाई से संत्रस्त है और आम आदमी का जीवन बिल्कुल नष्टप्राय: हो गया है। मुझे याद आता है हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उसका समारोप करते हुए यह कहा था कि "The four years to 2007-08 have been the best years so far, but, may I say with humility, that the best is yet to come." And this is the best what has come. If this is the best, then, I don't know what will be the worst. अगर इसे बैस्ट कहेंगे तो फिर वर्स्ट किसे कहेंगे? और यह हालात बजट पेश करने के कुछ दिन के अंदर ही पैदा हो गए। 29 फरवरी को बजट पेश किया गया था और आज अप्रैल की 16 तारीख है, इस डेढ़ महीने में इस देश की अर्थ व्यवस्था, इस देश के लोगों की अन्न सुरक्षा, इस देश के लोगों का जीवन और आगे देखें तो हमारी सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस डेढ़ महीने के अंदर ध्वस्त हो गई। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट के इतनी जल्दी बाद जो पहले हमें बहुत अच्छे गुलाबी आंकड़े बतलाए जा रहे थे,.....।

एक दृश्य दिखाया जा रहा था, वह एकदम बदल गया है। हम एकदम स्वर्ग से न केवल जमीन पर, बल्कि पाताल में पहुंच गये हैं। मुझे इसके साथ माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बयान याद आता है और बजट भाषण में जो कुछ हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था, वह मैं उन्हें थोड़ा-सा याद दिलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा था, "I think no Government in our country can be oblivious to the objectives of ensuring reasonable price stability without hurting the growth process." फिर वित्त मंत्री जी कहते हैं, "There can be no clearer enunciation of policy. However, since the downside risks have increased worldwide, we must be vigilant...." What vigilance does he mean? कितनी सतर्कता, कौन-सी सतर्कता, हमारी समझ में नहीं आती है और वह कहते हैं we must be vigilant. Was he vigilant? Is the Government vigilant? Then, he says "....and prepared to make swift adjustments in our policies to achieve the goal of growth with price stability." अभी हमारे मित्र यहां माननीय सिब्बल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि the Government has no magical wand. हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम इस स्थिति को ठीक कर दें। अरे, डेढ़ महीने पहले आप बोल रहे थे कि सब चीजें हम करेंगे। हम करने वाले हैं, हमारे बस में है, यह हमारी पॉलिसी है, यह हमारे प्रधान मंत्री जी का भाषण है, यह उनका नीति-निर्देश है। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई भी छड़ी नहीं है, अब तो जनता की छड़ी आपको मारेगी, इसके अलावा और कोई छड़ी इसका उपाय नहीं कर सकती है, इसके अलावा और कोई उपाय इसका नहीं है। फिर आप कहते हैं कि इस साल रिकार्ड उत्पादन होगा। मैं आपके वक्तव्य से ही बोल रहा हूं। "The Ministry of Agriculture has estimated that the total output of food grains in 2007-08 will be 219.32 million tonnes and that will be an all time record. In particular, production of rice is estimated at 94.08 million tonnes; maize at 16.78 million tonnes; soya bean at 9.45 million tonnes; and cotton at 23.38 million bales and each of these will be an all time record." अगर ऑल-टाइम रिकार्ड के बाद प्राइस राइज का भी आल-टाइम रिकार्ड होना है, तो कौन-सा यह अर्थ-व्यवस्था का सिद्धांत है। Is there a match or mismatch? मैच तो आजकल सिर्फ क्रिकेट का होता है। हमारे वित्त मंत्री एक बात कहते हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री कुछ दूसरी बात कहते हैं। हमने सुना है कि कल सीसीपी की मीटिंग इसीलिए स्थगित हो गयी कि दोनों में अन्तर्विरोध है। अब सरकार में अन्तर्विरोध है, तो इस सरकार को रहने की भी जरूरत है या नहीं। हमारे वामपंथी मित्र यहां पर बैठे हुए हैं। ये इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं इस बात पर अपना रुख साफ करते कि उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे या महंगाई का समर्थन करेंगे। केवल बाहरी धरना देकर रहेंगे या इस महंगाई के स्रोत को आप तत्काल उखाड़कर फैंकने के लिए तैयार होंगे, जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार होंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल): क्या आप महंगाई रोकेंगे? ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: हम तो उखाड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आइये। I invite you. आप आइये, आप आइये। ...(**व्यवधान**)... हम इसके लिए तैयार हैं। फिर वित्त मंत्री जी कहते हैं, "We have also witnessed capital inflows that are far in excess of the current account deficit and it is our responsibility to manage the flows more actively. The Government will, in consultation with the RBI, continue to monitor the situation closely." क्या मॉनिटरिंग हो रही है? क्या मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म से आप इसको हल कर सकते हैं? आप ही ने बार-बार कहा है, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इनफ्लेशन ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट अर्थात् महंगाई मुद्रा विस्तार, आर्थिक विकास और निवेश, इन तीनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, वह कहां है? हम तो बहुत देर से देख रहे थे कि कहीं मिलेगा, लेकिन वह तो मिला नहीं। इसमें टोटल मिस-मैच है। इन तीनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है और इसलिए इस देश की महंगाई ही नहीं, बल्कि सारी अर्थ-व्यवस्था पर आज काले बादल मंडरा रहे हैं। उपसभापति जी, मुझे एक बात और इस सदन को स्मरण दिलानी है कि महंगाई कांग्रेस की पहचान है। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब-तब महंगाई आती है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 1967 के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और कभी किसी एक रास्ते से, कभी दूसरे रास्ते से, जब भी सरकार चुनाव के बाद आई, तो उसके बाद महंगाई लाई। मैं आज उस विषय में विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन अर्थशास्त्र के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कांग्रेस का आना और महंगाई का आना, दोनों साथ-साथ हैं। इनमें चोली-दामन का साथ है। महंगाई के बिना कांग्रेस नहीं रह सकती और कांग्रेस के बिना ...(**व्यवधान**)...

श्री आर॰के॰ धवन (बिहार): 78 में क्या हुआ था?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको बता रहा हूं कि 78 में सारे लोग राशन कार्ड को भूल गए थे। 78 के अंदर सारे लोग ...(**व्यवधान**)... मैं आपको बता रहा हूं ...(**व्यवधान**)... 78 में लाइनें खत्म हो गई थीं। ...(**व्यवधान**)... 78 में यही हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग क्यों उठ रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री आर॰के॰ धवन: 79 में आपकी सरकार चली गई थी। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: माफ कीजिए मंहगाई की वजह से नहीं ...(**व्यवधान**)... 78 से ...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... धवन साहब, आप इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... जब आपकी टर्न आएगी, तब आप जवाब दे दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... जोशी जी, आप बोलिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: अगर 1967 के बाद इस देश के अंदर पहली बार लाइनें खत्म हुईं, राशन कार्ड घर में चले गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: धवन साहब, आप बोलने दीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बाजार सामानों से भरा हुआ था, वह जब था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और कांग्रेस सत्ता से च्युत हुई थी। उसके बाद जब-जब जनता पार्टी की सरकार हटी और फिर से कांग्रेस की सरकार आई, तो महंगाई आसमान छूने लगी। मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी NDA की सरकार थी, मैं उस जमाने की बात भी आपको बताता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। देखिए, 'Month-wise Point-to-Point Rate of Inflation for the year 1994 to 2005.' अब आप इसमें देखें, हमारा कार्यकाल था और हम आपको 98 से बताते हैं। उस समय ...(**व्यवधान**)... मैं आपको बता रहा हूं ...(**व्यवधान**)... 98 में 15.3 दिसम्बर में था और this was the inflation for the year. जब हम छोड़कर आए 2004 में तो यह घटकर, 3.8 और 4.2 आ गया था। आपको जो महंगाई का रेट मिला था, वह 4.2 मिला था। अब आप कहां हैं, अब आप 7.0 पर हैं।

आप 7.0 तो उन आंकड़ों की बदौलत हैं, जो आप देश को दिखा रहे हैं। ...(व्यवधान)... देखिए, देखिए 7.4 जो आप दिखाते हैं, वह तो छोटे आंकड़ों के बल पर दिखाते हैं। आप CPI और WPI का खेल क्यों खेलते हैं। Wholesale Price Index or Consumer Price Index के बीच में आपने जो लोगों को भरमाने का तरीका अपना रखा है, मैं उस पर यह साफ कहना चाहता हूं कि किन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ी है। आज अखबारों में सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि किस चीज़ की महंगाई बढ़ी है और किस की नहीं बढ़ी है। देखिए, इसमें electrical appliances, जिनका weightage 1.82 है और इनमें last change हुआ था, 11 अगस्त, 1960 को। इसी तरह से tractors, जिनका weightage है .73, उनमें महंगाई नहीं बढ़ी, 17 नवम्बर, 07 के बाद। इसी तरह से plastic products में, 29 दिसॅम्बर के बाद नहीं बढ़ी, और tyres में 15 दिसम्बर, के बाद नहीं बढ़ी, polyester yarn में 11 अगस्त के बाद नहीं बढ़ी, fertiliser and pesticides में 5 जनवरी के बाद नहीं बढ़ी, लेकिन foodgrains में, बाकी चीजों में, cement में, steel में, इसका क्या हाल है! यह महंगाई कहां से बढ़ गई! Edible oils के दाम बराबर बढ़ रहे हैं। आम आदमी के बजट में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे सामने अखबार की खबरें हैं, जो दिल दहलाने वाली खबरें हैं कि किस तरह से इन चीजों के दाम बढ़ने से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया। उनका खाने का खर्च 50 फीसदी बढ़ गया और मध्यमवर्गीय परिवार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। 'महंगाई ने किया थाली में छेद' ये सब खबरें हैं। नाश्ते की प्लेट से दूध, फल, मक्खन और दही गायब हो गए, nutrition affected हो गया। खाने में से सलाद, नीम्बू और दालें घट गईं लोग सिर्फ आलू खाकर जिंदा रहे हैं। खाने पर महीने भर का खर्च औसतन 30 फीसदी बढ़ा। यह तो मैं जो आम आदमी थोड़ा सा कमाता है, उसकी बात कह रहा हूं। रेलवे स्टेशन के सामने एक गरीब आदमी बयान दे रहा है कि भोजनालय में हफ्ते भर पहले जो थाली 15 रुपए की थी, अब वह 20-25 रुपए की हो गई है। इस थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी और अचार दिया जाता है। एक गरीब मजदूर ने कहा कि अगर मैं रोज 100 रुपया भी कमाऊं, तो मेरे 50 रुपए दो बार के खाने पर खर्च हो जाएंगे बाकी पचास रुपए में क्या करूं? यह तो वह है जो सौ रुपए कमा रहा है, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो नौ रुपए से लेकर दस या बीस रुपए तक रोज के कमा रहे हैं। उनका क्या हाल होगा? वे कहां से खाना खाएंगे? उनकी रोटी, दाल, सब्जी का क्या होगा? सभापति जी, इस देश के बारे में यह गहरा सवाल है। यह मामूली सवाल नहीं है। ये कैसे हो गया? आप कहते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तब ये चीजें कहां गई? अगर आपको दाल इम्पोर्ट करनी थी, माना आपने दाल का जिक्र नहीं किया था कि रिकार्ड प्रोडक्शन होगा, लेकिन गेहूं, चावल, सोयाबीन, इन सबके लिए तो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। यह कहां गया? मुझे हंसी आती है जब सदन के सम्मानित सदस्यों द्वारा यह कहा जाता है कि यह इसलिए गड़बड़ हो गई क्योंकि दक्षिण वाले गेहूं ज्यादा खाने लगे और उत्तर वाले चावल ज्यादा खाने लगे। मैंने कहा कि राशन की मात्रा तो उतनी ही खाते हैं। ...(व्यवधान)... डेढ़ महीने में ही यह हालत हो गई। ये किस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि हमारे पास न जादू की छड़ी है, न हम ये कर सकते हैं। आप बयान देते हैं कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे, best is yet to come. अगर अभी से ये हालात हैं तो 2009 आते-आते यह बेस्ट हमें कहां ले जाएगा, मैं नहीं कह सकता हूं। मुझे यह देखकर सिहरन होती है। आप देखिए, आम आदमी, जो बेचारा मजदूर खाना खाता है, वह यह कहता है कि महीने भर में चाय तीन रुपए से चार रुपए हो गई। साधारण चाय, जो ठेले वाला बेचता है, होटल की चाय की बात नहीं कर रहा हूं, उसके दाम नहीं बढ़े हैं। दाम किसके नहीं बढ़े हैं, दाम ज्यादातर उन चीजों के नहीं बढ़े, जिसे अमीर आदमी या उच्च मध्यम वर्ग के लोग खरीदते हैं। दाम उन चीजों के नहीं बढ़े हैं, जिन्हें आप लग्जरी गुड्स कहते हैं, दाम उन चीजों के बढ़े हैं, जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं, जो उसके बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचा रही है। मेरे सामने ऐसी भी खबरे हैं, जो ये कहते हैं कि खाने पर खर्च करें या बच्चों की पढ़ाई और दवाई पर खर्च करें। खाना जीवन की स्थिरता, जीवन को बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए खाना तो खाना ही है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है। ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं कि अब हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें किसी सस्ते स्कूल में डालना होगा या बच्चों की पढ़ाई बंद करनी होगी। पहले हम सुना करते थे कि बाप अगर शराब पीता हैं या कुछ इसी प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है तो वह घर के खर्चे कम करता था और अपने दुर्व्यसनों के लिए खर्चे बढ़ाता था, लेकिन अब हम यह देख रहे हैं कि मां-बाप बच्चों के खाने, अपने परिवार के खाने के कारण से सामान्य दाल रोटी खाने के कारण से अपने बच्चों की पढ़ाई बंद कर रहे हैं। हमने यह देखा है। हम वित्त मंत्री जी से यह सवाल जानना चाहेंगे कि क्या वे सदन और देश के सामने सही आंकड़े रखेंगे? डब्ल्यू॰पी॰आई॰ और सी॰पी॰आई॰ के जो बेसेज हैं, क्या उन्हें बदलेंगे और सही रेश्नलाइज करेंगे? उनको किसी एक

तरीके पर लाएंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज जिसे वे 7.4 परसेंट यहां कहते हैं, वह मैदान में जाकर 10, 11 परसेंट दिखाई दे रहा है और गरीब, गांव के आदमी के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 13 या 14 परसेंट पर यहां से पहुंचेगा। मैं नहीं समझ पाता हूं कि महंगाई के इस तरह के गलत आंकड़े देकर देश को भ्रमित करने की क्या जरूरत है? आप देखिए दाम किस तरह से बढ़े हैं। उड़द की दाल, जो सन 2004 में 20 रुपए से 22 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वह आज 48 रुपए प्रति किलोग्राम जून में हो गई थी, इसी तरह से आप देखिए मूंग 21, 22 रुपए किलोग्राम थी, यह 44, 45 रुपए किलोग्राम जून 2006 में थी, अब बढ़ते-बढ़ते 48 या 50 रुपए किलोग्राम हो गई होगी या इससे ज्यादा हो गई होगी, चना 35 रुपए किलो से 40 रुपए किलो तक, मसूर 30 से 35 तक हो गई। पहले कहा जाता था यह मुंह और मसूर की दाल, अब तो कहेगा, हां साहब, यह मुंह और मसूर की दाल। ये जो हालात है, इनको आप देखें कि यह क्या हो रहा है और दाम कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं, हफ्ते-हफ्ते बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दो या तीन साल में बढ़ रहे हैं, ये वीकली बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें डेली बढ़ रही हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जब जर्मनी में इनफ्लेशन हुआ था तो एक साहब सिगरेट खरीदने गए। उन्होंने दुकान पर सिगरेट का दाम पूछा, उसने दाम बता दिया। कहने लगे कि शाम में आया था, तब तो ये दाम थे, अब ये है, उसने कहा कि साहब, शाम तो निकल गई है, इस वक्त यही दाम है। उन्होंने सिगरेट वहां से नहीं खरीदी। अगली दुकान पर यह सोचकर चले गए कि सस्ती मिलेगी, वहां पहुंचे तो उसने और पैसा बढ़ाकर बताया, वापस लौटकर फिर उसी दुकान पर आए तब तक उसके यहां भी पैसे बढ़ गये और नतीजा यह हुआ कि वे सिगरेट नहीं खरीद पाए। यह कहा जाता था कि जर्मनी में हालत यह हो गई थी कि आदमी कुर्सी के पीछे की एक छोटी सी लकड़ी बेच कर किराया और कर्ज अदा कर देता था। Prices had gone up so much. बजाय कुर्सी बेचने के थोड़ी सी लकड़ी बेच दी और फर्नीचर का पैसा अदा कर दिया। यह तो inflation है, अगर इस तरह से बढ़ेगा, तो हालात क्या होंगे, किस तरह से लोग जिन्दा रहेंगे, हम किधर जाएंगे? उसी तरह के trend मुझे नजर आ रहे हैं। उपसभापति जी, जब ये trends होते हैं, तो मुझे बड़े दुख के साथ और बड़ी चिन्ता के साथ कहना पड़ता है कि तब राजनीतिक अस्थिरता आती है। जर्मनी में जो कुछ हुआ था, वहां हिटलर का उदय, फासिज्म का उदय, उसका एक कारण बढ़ता हुआ inflation था। मुझे बहुत चिन्ता है कि अगर inflation को नहीं रोका गया, तो इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था पूरे तौर पर ध्वस्त हो जाएगी और इसके स्थान पर यहां कैसे elements आएंगे, उसको हम आज बयान नहीं कर सकते। हम केवल उसकी कल्पना करके सिहरते हैं। यह जनतंत्र के लिए आवश्यक है, देश के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा जाए और इसको किसी भी हालत में बढ़ने न दिया जाए।

फिर सरकार कहती है कि इसके लिए हम करेंगे क्या? मेरे सामने एक अखबार है, जिसमें कहा गया है कि केन्द्र राजस्व की कुर्बानी को तैयार है। वित्त मंत्रालय का यह दावा है कि रबी की फसल के बाद कीमतों में कमी आएगी। इस बात का क्या मतलब है? कीमतों में कमी आएगी! यह बड़ी ही क्यों है, सवाल यह है। सवाल यह नहीं है कि कीमतों में कमी आएगी या नहीं आएगी। वह जब आएगी, तब आएगी। ये हमें क्या भरोसा दे रहे हैं! अगर record production होने वाला था, तो कीमतें बढ़ने क्यों दी गईं? यह जो आपने forward trading वालों को इजाजत दे रखी है और उसने जो तबाही पैदा की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस चीज को आप कब तक नियंत्रित करेंगे? यह सोचने की बात है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने कहा है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, तो सरकार खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुधारने के लिए कई और कठोर उपाय करेगी और अगर इन क्षेत्रों ने गैर-जिम्मेदारी से बर्ताव किया, तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनको गैर-जिम्मेदाराना कदम उठाने क्यों दिया गया, किसलिए उठाने दिया गया? क्या सरकार की इनसे पहले सांठ-गांठ नहीं थी? आप गैर-जिम्मेदाराना कदम उठाओ, लूट लो, जितना लूट सको, बाद में हम देख लेंगे। लोगों को समझा देंगे, भरमा देंगे, कोई थोड़े-बहुत छापे मार देंगे और उससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं। यह छापों से नहीं होने वाला है। आपकी अर्थव्यवस्था के बुनियादी, fundamentals गलत हैं। सवाल वहां आता है। आपने उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। जब तक आप उस पर गौर नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि आप इन चीजों पर काबू पा सकेंगे और नियंत्रित कर सकेंगे। कोई कहता है कि मई के महीने तक कीमत तय होगी, कोई कहता है कि कुछ होगा। वह तो मैं बता ही चुका हूं कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कहते हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपके पास वह छड़ी नहीं है, मगर जनता के पास जो छड़ी है, वह बड़ी खतरनाक होती है। आप उससे संभल कर रहिएगा।

मैंने महंगाई के आंकड़े दिए थे कि यह एक हफ्ते में कैसे बढ़ी। मूंग की दाल 44 से 48 रुपया हो गई, बेसन 46 से 48 रुपया हो गया, सब्जियां औसतन 16-20 रुपए हो गईं। अब सिवाय आलू के और कोई सब्जी नहीं है। मिर्ची तक के दाम बढ़ गए, नमक के दाम बढ़ गए। पहले लोग कहते थे कि रोटी और नमक खा लेंगे। रोटी का दाम तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन नमक का दाम भी बढ़ गया। उपसभापति जी, मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था कि हालात ऐसे हैं कि दुनिया में ऐसे देश हैं, जहां आज लोग मिट्टी के बिस्किट बना कर खा रहे हैं। अगर यह अभाव की नीति इसी प्रकार चलती रही, तो मुझे खतरा है कि देश में ऐसे स्थान हैं, जहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। मरता क्या न करता, तो क्या खाएंगे, आप उन्हें खिलाने के लिए क्या दे सकते हैं, आपके पास क्या है? मैंने यह भी देखा है कि आपका प्लानिंग कमीशन भी आपसे कुछ यह कह रहा है कि आपका जो delivery system है, वह बेकार हो गया है, आप उसमें कुछ कर नहीं पाए हैं। बार-बार वह आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अपना delivery system ठीक कीजिए। आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि आप delivery system को कब तक ठीक करेंगे? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यह delivery system आपकी तरफ से ही चलाया जाता है, हममें से तो कोई और इसे चलाता नहीं है। लेकिन हम अपने वक्त में हर जगह अनाज दे रहे थे। गरीब आदमियों को, पावर्टी लाइन से नीचे के लोगों को, बहुत सस्ता अनाज मिलता था। कुछ जगह, जो डेस्टीट्यूट्स थे, उनको तो हम मुफ्त अनाज दे रहे थे, लेकिन कभी बाजार में अनाज के दाम नहीं बढ़े। दाम तब क्यों नहीं बढ़े, साहब, और इन तीन चार सालों में ऐसा क्या हो गया? आज गरीब आदमी के लिए आपने यह कैसे हालात पैदा कर दिए हैं कि भूखे मरने के अलावा आज उसके पास किसी प्रकार का कोई और रास्ता भी नहीं बचा है।

आपका प्लानिंग कमीशन ही बोलता है कि आपका डिलिवरी सिस्टम ठीक नहीं है। उनका पैनल यह बात कह रहा है। जो योजनाएं आपने चलाई थीं, उनमें से कोई योजना ठीक से काम नहीं कर रही है और कहीं-पर 3.5% डिलिवरी हुई है, कहीं पर 30% हुई है। तो कहीं पर 20% है। इस तरह से जितनी ये सभी केन्द्रीय योजनाएं हैं, उनके खस्ताहाल हैं। ये कहां गईं? ये भ्रष्टाचार में चली गईं, इनऐफिशिएंसी में चली गईं। आप कहते हैं कि कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों अखबार में देख रहा था कि आपके स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में ही स्कैम है। दालों और जिन चीजों को आयात किया गया है, उसमें जो छापे पड़े हैं, उसमें से एक बड़ा और मोटा मगरमच्छ आपका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ही है, जिसने गलत ढंग से टैंडर्स दिए, जितनी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा दाम पर टैंडर्स दिए। मैं चाहूंगा कि आप इन सब बातों की जांच करवाएं और ऐसे लोगों को दंडित करें। यह सरकारी भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? व्यापारी के लिए तो आप कह सकते हैं कि वह भ्रष्टाचार करता रहा है, लेकिन जो यह सरकारी कर्मचारी और आपके वाणिज्य मंत्रालय के अन्दर काम करने वाले लोग हैं, यह इस तरह से क्यों कर रहे हैं? यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक आप इन चीजों पर चौतरफा ध्यान नहीं देंगे, आप इसे ठीक नहीं कर सकेंगे। आपके लिए यह संभव नहीं है। मैं आपकी जो अर्थनीतियां देख रहा हूं, वह इस समय बिल्कुल भी देश-हित में नहीं जा रही है। जिन चीजों को आप इम्पोर्ट कर रहे थे, उनमें आपने क्या किया ऐडिबल ऑयल्स के ऊपर से इम्पोर्ट डयूटी हटा दी थी, बासमती राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था और मक्का के इम्पोर्ट पर डयूटी घटा दी थी। उसके बाद आपने दालों और ऐसी चीजों के एक्सपोर्ट पर एक साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया था और खाद्य तेलों के एक्सपोर्ट को बंद किया था, लेकिन इनमें से एक भी कदम कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्या यही आपके कड़े कदम हैं, जो आपने लिए हैं? लेकिन इनका कोई असर हमें दिखाई नहीं दिया।

असली बात तो यह है कि एक बड़ा तमाशा और सामने है कि प्राइस मंडी से चीज़ों की जो होलसेल निकलती है, उसमें और रिटेल प्राइस में बड़ा गैप है। इसे आपने क्यों नहीं रोका है? होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 15%-20%से ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आज लोग उसमें 40%-50% मुनाफा ले रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस मुनाफाखोरी को क्यों नहीं रोका है?

आप जिस कृषि की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट घटा है। अगर हम पिछले चार सालों में देखें तो पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर को मिला कर यह 2002-03 में 9.0% था, 2005-06 में घट कर 7.7% रह गया और इस साल शायद कुछ और घटा है। सवाल यह है कि क्या इस बारे में आपने कोई मेज़र्स लिए हैं? आपको पता था कि देश के सामने यह समस्या आने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बेखबर थे और ऐसा

भी नहीं है कि अचानक यह आ गई। आप बार-बार कहते हैं कि यह वैश्विक परिदृश्य के साथ जुड़ी हुई है, यह वर्ल्ड फिनॉमिना है और हम दुनिया से इन्फ्लेशन इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी चीजें होती हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। इसको सब जानते हैं, मैं भी इसका विरोधी नहीं हूं। जब आपने अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ लिया है, तो दुनिया में जो कुछ होता है, उसका असर हम पर पड़ता है, लेकिन ऐसा तो न हो कि बारिश कहीं और हो और छाता आप यहां निकाल लें।

पहले हम सुना करते थे कि जब बारिश रूस में होती है तो हमारे वामपंथी छाता हिन्दुस्तान में निकाल लेते थे, अब शायद ऐसा है कि अगर बारिश किसी और देश में होती है, तो छाता हमारी सरकार निकाल कर खड़ी हो जाती है, ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरी: बारिश से भीगने वाले तो आप ही हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: अरे साहब, गरीब आदमी तो भीगता ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। गरीब आदमी तो भीगता ही है और उस बेचारे की तो नियति ही भीगना है। मैं यही कह रहा हूं, चाहे आपको मानें या उनको मानें, लेकिन भीगते तो हम ही हैं। आपने बिल्कुल ठीक बयान किया, हम तो भीग ही रहे हैं और भीगने के बाद उसके जो परिणाम होते हैं साहब, हमारे पास तो सुखाने के लिए कपड़ा भी नहीं बचा है। दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं कि अगर हम बीमार हो जाएं तो उससे बच सकें। दवाइयों के दाम तो बिल्कुल आसमान पर चले गए हैं ...(**व्यवधान**)...

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): यह गलत है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यह गलत नहीं है, सही है। यह सही है। आप यहां गलत कह रहे हैं, लेकिन बाजार आपको गलत कह रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान: आपने दवाइयों के दाम के बारे में कहा है, तो ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं yield नहीं कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान: दवाई एक ऐसी चीज़ है, जिस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99 परसेंट दवाइयों का दाम पिछले एक साल में एक नया पैसा तक नहीं बढ़ा है। एक परसेंट का दाम थोड़ा बढ़ा है या थोड़ा घटा है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं yield नहीं कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने दवाइयों के दाम, उसकी एक युनिट का दाम एक-एक लाख रुपए रखा हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं! सरकार उनसे मुकद्दमा लड़ रही है और उनका दाम घटाने के लिए, पेटेंट कानून के मुताबिक आप की ही सरकार उनसे मुकद्दमा लड़ रही है। आप क्या बात कर रहे हैं! कैंसर की दवाइयां आज एक-एक लाख रुपए महीने में आ रही हैं ...(**समय की घंटी**)... डेढ़-डेढ़ लाख रुपए महीने में आ रही हैं।

श्री उपसभापति: डा॰ साहब, अभी आपकी पार्टी से दो मैम्बर्स बोलने वाले हैं, उनमें से एक नये मैम्बर भी बोलने वाले हैं। उनके लिए भी कुछ समय चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जरूर समय रखेंगे, पूरा समय रखेंगे। लोगों में घबराहट क्यों हो रही है? चिंता की बात यह है कि कोई सैक्शन ऐसा नहीं है, जहां दाम न बढ़े हों। मैं एक बुनियादी बात कह रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपके fundamentals गलत हैं। आपने सारी अर्थव्यवस्था को विदेशों पर आधारित रखा है। आपने डोमेस्टिक मार्केट की चिंता नहीं की, सिर्फ-एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। भारत का इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, अगर आपने इसकी चिंता की होती, यहां के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई होती, यहां प्रोडक्शन बढ़ाया होता, तो आज यह दिन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर कृषि में गिरावट आई, तो आपने कहा कि हम इम्पोर्ट कर लेंगे, दुनिया में हो रहा है, कोई चिन्ता नहीं है, डब्ल्यु॰टी॰ओ॰ सामने है, हम इम्पोर्ट कर लेंगे। अगर दवाइयों की कमी हुई, तो हम इम्पोर्ट कर लेंगे, लेकिन हिन्दुस्तान में क्या करेंगे, इसका आपके

सामने कोई साफ विज़न नहीं है और अगर आज हिन्दुस्तान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इसीलिए बचा हुआ है कि हमारे जैसे लोगों ने पिछले 20 सालों से बराबर यह कहा कि हिन्दुस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी पर आप ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक सेक्टर पर ध्यान दीजिए, यहां की रिसोर्सेज़ पर और यहां के लोगों की टैलेंट पर यहां ही काम करा कर आप अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कीजिए, यह नहीं कि दुनिया में विस्तार होने वाली अर्थव्यवस्था के आप appendices बन कर चले जाएं और वहां ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो तो आप यहां बीमार हो जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी cushioning हो, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी मजबूती हो और वह मजबूती हो सकती है। आप ही ने अपने बयान में लिया है, अपने भाषण में कहा है कि एक वक्त वह था जब कि हिन्दुस्तान और चीन मिलकर दुनिया के 50 फीसदी बाजार के हिस्सेदार थे और आज एक परसेंट के भी नहीं है और आपने कहा है कि हम इसे करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? सिर्फ दुनिया के बाजारों में जुड़ कर करेंगे या हिन्दुस्तान के बाजार को और हिन्दुस्तान की खेती को तथा हिन्दुस्तान के रोजगार को बढ़ा कर करेंगे? आप अपने fundamentals को सुधारिए। आपके fundamentals गलत हैं। अर्थव्यवस्था की आपकी बुनियाद गलत है। आप सिर्फ Bretton Wood Institutions के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे इस देश की तरक्की संभव नहीं है। Globalisation is not working for the poor, it is not working for the poor in a country and it is not working for the agricultural sector anywhere. मैं आपको बता देता हूं। उसे बताकर मैं समाप्त करूंगा।

अभी जो डिबेट दुनिया में चल रही है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको आप पढ़ें। 1967 में पहली बार "Limits to Growth" के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट्स तथा साइंटिस्ट्स ने मिल कर प्रकाशित किया था। उस "Limits to Growth" पर 1967 से लेकर 1972 तक बहस हुई। उस बहस से ये नतीजे निकले कि दुनिया में आज जो trends हैं, उसमें 100 सालों के अन्दर हालात ऐसे आएंगे कि लोगों के सामने अनाज की दिक्कत होगी, लोगों के सामने पर्यावरण की दिक्कत होगी, इंडस्ट्रियल मैटीरियल की दिक्कत होगी, पॉल्यूशन की दिक्कत होगी और हैल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे। ये बातें थीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको देख कर कहा कि इस पर और बहस होनी चाहिए तब MIT की तरफ से एक "Global 2000 Report" आई, जो प्रेसिडेंट को दी गई। उसने इनमें से बहुत सी बातों की गहराई से छानबीन की और कहा कि हां इसमें दम है और इस पर विचार होना चाहिए और आज अब नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये लोग कह रहे हैं। अभी मेरे सामने एक पुस्तक है- 'From Resource Scarcity to Ecological Security', edited by Dennis Pirages and Ken Cousins. यह 2008 में छपी है। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से कहा है कि "The Global 2000 Report considered the future of the world food supply to be a significant concern, even though it projected a steady increase of 2.2 percent yearly in food production over the 1970—2000 period. Worldwide, per capita consumption was also to increase by 15 per cent over the same period. But most of this increase was projected to take place in the wealthier countries, not in the developing countries." यह बात कर रहे हैं कि सन् 2000 में क्या होगा? इसी का वह जिक्र कर रहे हैं और फिर आगे लिखते हैं, "The people in many of the world's poorest countries could expect to see only modest improvements in per capita food availability.

इतिफाक से हिंदुस्तान में वह मोडेस्ट इम्प्रूवमेंट भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये वे सवाल हैं, जिन पर आपको गौर करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के देश इस पर गौर कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि अनाज का क्या होगा, इंडस्ट्रियल मैटेरियल का क्या होगा। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ग्रोथ के, डवलपमेंट के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो मोडल्स हैं, उन मोडल्स को रिविजिट किया जाना चाहिए, उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो कुछ आज तक हुआ है अच्छा और बुरा, उसको मिलाकर हमें सोचना है। जो अच्छा है, उसको स्वीकार करें और जो बुरा है, उसको नकारें। हमारी दिक्कत यह है कि हम इस देश में देख रहे हैं कि हमारे देश के हिसाब से दुनिया में जो कुछ गलत हो रहा है, यह सरकार उसे स्वीकार करती है और जो कुछ अच्छा होना चाहिए, उससे इंकार करती है। यही वजह है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बिल्कुल गलत हैं, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, वितरण व्यवस्था ये सब की सब धाराशायी हो गई हैं। इनका न तो इनफ्लेशन पर कंट्रोल है, न इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल है और न ही ग्रोथ पर कंट्रोल है।

महोदय, डेढ़ महीने के अंदर कोई सरकार इस तरह से उल्टी हो जाए, यह आज पहली बार हमने देखा है। मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सिब्बल साहब चले गए, कि वह बराए-मेहरबानी अब जादू की छड़ी का जिक्र न करें। जनता की जादू की छड़ी बड़ी खतरनाक होती है, वह बड़े-बड़े जिन्नों को बोतल में बंद कर देती है और समुद्र में फेंक देती है। मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता को ऐसी छड़ी चलने की नौबत न आए और आप लोग जितने भी दिन मौजूद हैं ...(व्यवधान)... जी, समुद्र में फेंक देती है, लेकिन इतने हद तक वह जरूर आए कि आप उस वोट को सहलाते रहें और सहलाते-सहलाते हिंदुस्तान की सड़कों पर घूमते रहें। यह मैं जरूर चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Thank you very much Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. First of all I welcome this discussion. Instead of making noise and creating acrimonious scenes, we are discussing important issues in the House and different viewpoints are expressed here so that we can arrive at some solution. It is a very good step. I gladly welcome this discussion. I also thank Dr. Murli Manohar Joshi who is a very senior Member of this House and a very good friend of mine. He is also a professor of Physics. I was listening to him with rapt attention. He very well narrated the difficulties of the people and even item-by-item he told about the increase in price. But, I was eagerly waiting to hear some suggestions from him, some positive suggestions from him in addition to criticism. Criticism is always welcome. It is the duty of an Opposition party. But, there should also be some concrete suggestions as to what to do, what is to be done in this situation because this is not just the duty of the Government. Yes it is the Primary duty of the Government is to contain prices to ensure that, at least, essential commodities are available to the common man at moderate and reasonable prices. But, we should not forget the fact that some time or the other every party, every section of this House, was either in the Government or supporting the Government. We should also not forget the fact that every section of this House is sharing power in the States, whether it is BJP or other parties or even the supporting parties like CPM. They are all in power in some States. Controlling the prices is not the responsibility of only the Union Government. It is equally the responsibility of the State Governments. These cannot certainly say that these are not responsible. Sir, with regard to decline in production, agricultural production, the Union Government alone cannot produce much. Yes, the Union Government can do its best and it is doing its best. But, everybody knows the role of the State Governments. *(Interruptions)* Likewise, Murli Manohar Joshiji said that the Government should take action against the hoarders, etc. But, who is to implement the Essential Commodities Act, 1955? It's the States. It is with the States and if I am correct, the Union Government has empowered the State Governments, by recent notification, by order, that they can take whatever steps they want, to tackle black-marketeers, profiteers, hoarders, etc. Are the State Governments doing their duty. I am not saying that all the State Governments are not doing. My point, Sir, is that every section in this society, in this House, has a responsibility. There is no point in blaming only the Union Government and washing off our hands. That's all I have to say about this.

Sir, Murliji is a very senior leader. He said whenever there is a Congress Government, price rise is a speciality. Sir, I hope, he will look at the statistics and records. What he said is not in conformity with the facts. Being a scientist, I hope, he should have, maybe, he used some politics to suppress the facts. In fact, the records and data with me show that during the period 1978-1981, the inflation was above 15 per cent. Sir, again, between 1989-1991, inflation was above 13 per cent and we were not in power at that time. Sir, again, I would like to show that even in 2004, if you take that particular year, inflation was near seven per cent. It was near seven per cent in 2004. Yes, if you take the average of four years, then, it is

less. I am speaking about the particular year 2004. So, it is not that this year is the only year when inflation has crossed seven per cent. There were other periods when inflation had crossed seven per cent and even gone above ten per cent. Sir, is it not a fact? Sir, Murliji said that we will blame the globalisation and global increase in prices. But, is it not a fact that global price rise will have an impact on our prices? Is it not a fact? Everybody knows the impact of crude oil price increase. Sir, crude oil price was ruling at 30 dollars per barrel five years back. Today, it is more than 100 dollars per barrel. That means, an increase of more than 300 per cent. Thanks to the Government that it has not passed on all the increase to the customers. Had it been passed on to them, what would have been their plight? I think the Government has taken whatever measures it could to contain prices. This crude oil price alone is an example. The price has increased by nearly 300 per cent in the international market. We have to buy at that price. Our consumers are burdened by an increase of only eight per cent. Sir, likewise, global price of all commodities have gone up. I have the list here. I have already mentioned the crude oil. Sir, the increase in palm oil prices, when compared with 2005, is 100 per cent. Sir, take, for example, rice. Again, when compared with 2005, increase in the world price is 76 per cent. Take for example, wheat. The increase in the price of wheat is alarming, 161 per cent. Likewise, urea, there is a steep rise in the price of urea. Then in respect of vegetables, take for instance, *desi chana*. The increase in its price is nearly 75 per cent. Take for instance, red lentils. The increase in its price is more than hundred per cent. I am speaking about the world price. I am not speaking about the Indian price. I am referring to the increase in the world price. So, I am saying that with regard to every item, the price has gone up. There is no item with regard to which you can show that its price has come down in the world market. So, when in the world market, the price has increased more than hundred per cent in respect of every item, to say that it will not have any impact on our domestic price is, I think, a very innocent answer, and only a political novice can say that. It is impossible, and especially, when we import 70 per cent of our crude oil, our energy requirement, when 70 per cent is imported. When the crude oil prices are rising so high, ruling so high, how can we get away from the impact of the huge increase in prices? this is what I want to bring to your kind notice. But, however, I would like to say that this Government, in spite of the global increase in prices, have taken many concrete steps to control the prices. Here I would also like to say for the benefit of my Left friends, they are my very good friends that inflation in China...*(Interruptions)*...

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): That is why you have cut the supplies to Kerala.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): They are really your very good friends!

PROF. P.J. KURIEN: Yes, they are my very good friends as you are my very good friend. Sir, for the benefit of my Left friends, I would say that according to an answer given in this House by the Finance Minister, Inflation in China, as on today, is higher than that in India. This is an answer which I got from the Finance Minister in this House...*(Interruptions)*... I am only trying to bring home the point that inflation is a global phenomenon. Madhuji, I am only trying to bring home the point that inflation is a global phenomenon, and China, is no exception. That is all what I am saying. Further, due to high rise in prices, there were food riots in Mexico, in Egypt and in Morocco. That is the situation, in spite of all these, I would say, when you consider this global increase in prices, any sensible man will give creditable plus marks to this Government because ...*(Interruptions)*... I agree there is price rise. I am not disputing that. Certainly, there is a price rise. We should all try to bring it down. The

Government should do its best. I fully agree with you. But I am saying that you should see the world scenario. If you look at this background and judge the action taken by this Government, then you will come to know about the ground reality. What are the actions taken by this Government? If you say that no action is taken, and that you are looking yourself. We have taken concrete action. I would like to mention some of the steps taken by the Government to control the prices because Dr. Murli Manohar Joshi was speaking as if no action had been taken. I would like to refer to one or two steps taken by the Government in this respect. Murliji knows all these, but the only thing is that he is not accepting it! Murliji, 5.5 million tonnes of wheat were imported. So, the Government resorted to import. Again, in order to procure more quantities of wheat and rice, the MSP for wheat and rice was increased. The import duty on edible oil, wheat and pulses was reduced to zero. It is not that only the private parties can import, the Government agencies are also importing. They are importing.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I have also mentioned this. The Government has taken steps, but they have given no results; I have said this. ...(*Interruptions*)... I have said it in the opening remakrs of my speech that the Government has taken these steps, which you are narrating, but they all have become infructuous; no result has been found after the steps are taken. Today, the situation remains as grim as it was earlier. That was the point.

PROF. P.J. KURIEN: Oh, that is the point! Then, I would like to answer that being a* you can imagine. You imagine what would have been the prices if the Government had not taken these steps; I agree that the prices are comparatively higher and the people are facing difficulties; especially the people living below the poverty line are having genuine difficulties; But had the Government not taken these measures, what would have been the situation should also be seen. I have no doubt that, then, there would have been starvation deaths and the prices of all these essential commodities would have been much more. Therefore, you should also appreciate the steps taken by the Government while criticising the Government. You should also give your suggestions as to what else should be done, which, unfortunately, did not come from you.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: We would give our suggestions afterwards.

PROF. P.J. KURIEN: Okay. No quarrel between us!

Likewise, in the Budget also, very concrete steps have been taken. The most important one, according to me, is that the fiscal deficit is contained at 2.5 per cent. You know that inflation is the greatest tax on the common men. Whatever steps the Government takes to control inflation are to be welcomed by all. And the fiscal deficit is to be controlled. It is contained at 2.5 per cent. And again, CENVAT was reduced on all commodities.

Then, the import duty was brought down to zero in respect of wheat, rice, pulses and edible oil. And see the export restrictions also. Basmati rice export is restricted. We, in Kerala, are also suffering because Coconut oil export is restricted. We can export coconut oil only through Cochin. Our Coconut farmers are not getting adequate prices. So, this Government has done, whatever it could, to reduce the prices; I have no doubt about that. Then, the most important one, as you said, is that; the CRR was increased eight times to reach 7.5 per cent on November 10. Eight times the CRR was incrased. Therefore, the liquidity was tightened. ...(*Interruptions*)...

*Expunged as ordered by the Chair.

1.00 P.M.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That will adeversely affect the growth. That will affect the growth.

THE FINANCE MINISTER (SHRI P. CHIDAMBARAM): You cannot have both. ...(*Interruptions*)...

PROF. P.J. KURIEN: The Finance Minister will reply to you! Otherwise, Mr. Deputy Chairman will cut my time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please continue.

PROF. P.J. KURIEN: So, the steps were taken, i.e. the increase in CRR. Sir, that will definitely have a salutary effect, and that is having. Otherwise, the liquidity would have been more; the prices would have been much higher. That is what I am saying. Therefore, you should kindly appreciate the steps taken by the Government. And, again, I would say, those who speak should certainly consider that this is a problem that we all are facing. I have already said that it is not that only the Congress Party is in Power. Other parties are also in power, in some States or the other. They are all suffering because of price-rise. So, each State should take action.

There should be concrete suggestions as to what action should be taken. Therefore, I would say that the State Government also has a responsibility in this matter, not the Central Government alone. I have narrated some of the actions taken by the Central Government. More actions need to be taken. The actions need to be taken will be explained by the hon. Minister. But I would like to know what the State Governments have done. Some of the State Governments are run by the BJP and some others are run by the Left parties. You were saying that black-marketing and hoarding should be checked. Who has to do that? It should be done by the State Government. Now you mentioned about the public distribution system and strengthening the PDS. But the PDS is actually being implemented by the State Government. Yes, allocation of rice or wheat or foodgrains to the PDS is the responsibility of the Central Government. It is the responsibility of the State Government to ensure that the rice allocated to the State is distributed properly to the people below the poverty line. Are they really doing it sincerely? Let me ask: Are they doing it sincerely? Sir, a portion of this rice or wheat allocated by the Union Government—I am not mentioning any particular State—goes into the hands of the black-marketeers. This is really happening. So, whether it is the Congress Government or the BJP Government or the Left Government, it is the responsibility of the State Governments to ensure that these allocated food materials really reach the poor. Are they doing it?

Secondly, under the Essential Commodities Act, who should take action? The action needs to be taken by the State Government. Are they doing it properly? I don't think. The other day I read in the newspaper that there was a raid in Delhi and, I think, two lakh quintals of rice were seized from a trader who is naturally a hoarder. It is happening not in Delhi along. It is happening everywhere. Everwhere hoarders are doing the same business. But where is the action? Which State Government is taking action? What happens is that when there is a trend of price rise, when there is an increase in price, the psychology is that there is a price increase. At least, some traders—I am not saying every trader—will try to buy, stock and hoard more. This is happening in every State. I don't see in the newspapers that the State Governments are acting. So, it is equally the responsibility of the State Government to act. But they are not acting.

Another point which I would like to mention is crude oil import. I have already mentioned about the increase in the price of crude oil. Whenever the price of petroleum products is increased, the States are also getting increased revenue through sales tax. All State Governments are getting it. Then, is it not their duty to reduce the sales-tax? Yes, the Central Government has, at least, tried to reduce it. But has any State Government tried to reduce the sales-tax component so that the impact of the price rise, which is due to international price rise and not our fault, is not passed on to the consumer? At least, its impact on the consumer or the customer should have lessened. Was it done? I would like to say something now. In my State, when our Government was there, when Mr. Ommen Chandy was the Chief Minister, there was an increase in petroleum price. The prices of petroleum and diesel were increased. At that time, our Government in the State of Kerala decided that there would be no corresponding increase in the sales-tax and the Government did not collect increased sales-tax so that petrol was sold at 75 paise less per litre and diesel was sold at 50 paise less per litre. Even though it is a very small amount, but this shows the approach of the Government. I am not criticising anybody. There are so many States which are run by the BJP and the Left Parties. Has any of your States showed this kind of an approach? That has not been done. So the State Governments also should do whatever they can do. But this is not being done. What is going on is only blame game and passing the buck. It is very important and crucial issue. What is beign done is not enough. Now I want to say something about my State, which is connected with this issue of price rise. There was unprecedented summer rain. Nobody had expected it. When paddy crop was about to be harvested, there was torrential, continuous and relentless rain. All the crops were totally destroyed. We could not do anything. Sir, before the rain started, the farmers in the State wanted to use harvesting machines to harvest the crops. Unfortunately, the workers of one political party opposed it tooth and nail. I do not know whether it is a policy of that political party to oppose the use of any harvesting machine or any mechanisation. The followers of that political party and labour unions opposed it tooth and nail and created problems and the harvest could not take place.

SHRI PENUMALLI MADHU: Sir, the subject is price rise.

PROF. P. J. KURIEN: Now people can know which is that party. Sir, five farmers have committed suicide. The Chief Minister of Kerala, along with an all-party delegation, met the Prime Minister and also the Agriculture Minister. Our total loss comes to more than Rs. 1,400 crores. We have asked for an ad hoc assistance of Rs. 150 crores imediately. I would request the Finance Minister to sanction that amount. I believe he would certainly do this because I am supporting him. Naturally, he will do that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Support has a price!

PROF. P. J. KURIEN: Support has no price, but for the sake of farmers I have no problem in requesting him to do that. What is the real cause of price rise? The real cause is, as the hon. Finance Minister has said in a reply to the question, that here is a mismatch between supply and demand. What has happened to agricultural production? I am not blaming anybody. In fact, agricultural production has come down. We had a Green Revolution. In the Green Revolution , our agricultural productivity increased by 100 per cent. But we have still scope for increasing our productivity. Dr. Swaminathan is here. I am sure he will agree with me that we are not at the peak of our productivity. We can double our productivity. If we compare our productivity with China, it is 50 per cent less than China. If we compare it with Asian average we are still behind. It is not that we have reached a plateau. So far as agricultural products, foodgrains, etc. are concerned, we have to go a long way. We should try for another

Green Revolution, which is possible. The hon. Member, Dr. Swaminathan, visited my place, Kuttanad in Kerala. He has submitted a report, and the Report is with the Government. What he has stated is that by administrative measures, by policy measures and by giving financial assistance, the production and productivity can be increased. Now, if China can have such a vast production,—their productivity is 100% more than ours—then, why cannot we have it? I am sure we can achieve it. The emphasis should be on increasing the production. That is the first suggestion which I would like to make. It is not a short-term measure. Various short-term measures have been undertaken by the Government, and I have already mentioned them. But I am talking about long-term measures whereby production and productivity can be increased. Sir, there is the Coconut Research Institute at Kayankulam in Kerala. There, I found that the coconut trees have been affected by root (wilt). The yield from the coconut trees are quite high, but the same yield is not available for the farmers. The reason is that the technology is not really transferred to the field. Sir, our scientists are doing very good work, and I have no doubt that in their standards, in their abilities, in every respect, they are equal to or better than the scientists in China or any other country. But the fact is that something is lacking somewhere. There is a gap between the technological accomplishment of our scientists and the transfer of that accomplishment to the field. The Government should appoint a committee to study this aspect and find out in which areas the real transfer of technology has not taken place. If we take the use of bio-technology, the tissue culture, a lot of work has been done. But this is not seen in the field. In practice, a majority of our agriculturists adopt the same old methods in every respect. They may be using chemical fertilisers these days; but scientific knowledge is lacking. The Government should, certainly, take steps in transferring this technology to the common farmers.

Then, I congratulate the Finance Minister on the bold steps that he has taken in the matter of waiving of loans. In fact, I should also congratulate and thank the Prime Minister and especially, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, I know that it is under her guidance that such a bold step had been taken. This is a bold initiative. But I have to say a few things. As far as this waiver is concerned, the effect of that waiver should reach the farmers within a stipulated time. The Finance Minister has given a time-frame. He says that it will be implemented by 30th June. I am grateful to him for that. But it should not only be applicable to agricultural loan *per se*; it should applied to the allied loans as well. What happens is that when you approach a co-operative bank for loan, for convenience sake, they write the purpose of loan as 'education of children', or sometimes 'for buying a buffalo', etc. In Kerala, they also write as 'sending the boy for employment'. But all these loans have been taken by small and marginal farmers. Therefore, I request him to be a little liberal while considering the applications. Otherwise, this sanctioned amount of Rs. 60,000 crores will not be utilised. You should be a little liberal so that all allied loans are also waived. I wish to add one point more here. The emphasis should be on increasing the productivity and production I am on that subject. If the production has to be increased, then, the farmers should be able to invest more money. They can invest only if they get new loans. Now, the rate of interest on the loan is 7 per cent. But later on, if he defaults, then, there will be added penal interest. I would request the hon. Finance Minister that, hereafter, agricultural loan to small and marginal farmers, with a holding of up to two hectares of land, as you have already fixed, should be provided at an interest rate of four per cent. Can that be done? Otherwise, the benefit of this loan-waiver will not be reflected in production. That should be reflected in production. If that is to happens, the next loan that is being given should be at 4 % interest...(*Time bell*)

I will conclude, Sir. I did not take much time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken half-an-hour.

PROF. P. J. KURIEN: But my Party has more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Party has one hour but there are five speakers.

PROF. P. J. KURIEN: Sorry, Sir. I will conclude then.

So, I would suggest, if you want to translate the benefits of this loan-waiver to the production side, new agricultural loans should carry a lower rate of interest, a rate of 4 per cent. Othwerwise, these farmers, who had once suffered because of loans, will not so for new loans and there will be a danger of a great exodus of people from the rural areas to the urban areas. I know, in Kerala, those who have one, two or three acres of land, are already leaving the agriculture. They do not want to continue with agriculture. They are leaving for the urban areas. They are prepared to work as even peons in the Gulf or other places. Many of them have come to Delhi; you can see them in Noida also. The result is that agriculture is suffering. The agricultural production will decline. That is happening. Therefore, those who are already in agriculture should be encouraged to stick to agriculture. That can be possible only if agriculture is made a viable proposition. Agriculture should be made a viable business. It can be made viable, firstly, by giving loans at lower rates of interest; secondly, by giving subsidies on fertilisers—some people want subsidies on fertiliser to go. I do not agree with them; if possible, there should be more subsidies—thirdly, by ensuring remunerative prices to farmers. I thank the Government that the MSP has been increased in the case of wheat and rice considerably. When you compare it with the MSP that had been fixed by the NDA in their five years, what we have done is higher. The NDA had given only a miniscule increase. Here, it is a considerable increase. But I do not want to waste the time by giving all the data. Sir, there should be a genuine and real study by experts, including an agriculturist, about the viability of agriculture today. The viability of agriculture is declining. That is why our agricultural production is coming down. If our agricultural production does not go up, if we do not have another Green Revolution, these spiralling and skyrocketing prices, which is due to the global impact also, will never come down, whether there is this Government or any other Government. Everybody will face the same *tamasha.* Therefore, I would request the hon. Finance Minister and the Government of India to take drastic long-term measures so that we have a long-term remedy. There should be a concerted effort on the part of all of us. Not only the Union Government, but the State Governments also should cooperate in full so that we are able to provide two square meals a day to the *amm aadmi,* the common man living below the poverty line and so that he may also live happily like the rest of the fifty per cent who are above the poverty line and for whom this price rise does not pose any problem. It is the poor who are badly affected.

I do not want to take more time, Sir. I congratulate the Government for having taken some strong measures. But I do expect more measures from the Government. I would also request the Government to consider my suggestions positively.

With these words, I thank you very much, Sir, and conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch
at twenty minutes past one of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at twenty-two minutes past
two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): जनाब शुक्रिया। मैं थोड़ा धीरे-धीरे बोलूंगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उपसभापति जी, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बात छूटने लगे तो मेरा समय थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। महंगाई पर चर्चा हो रही है। हम डॉक्टर जोशी को तो नहीं सुन पाए, लेकिन कुरियन साहब को ध्यान से सुन रहे थे। जब च हो रही थी या नहीं भी हो रही थी, हल्ला हो रहा था कि चर्चा हो, तो उस समय भी हम यह जानते थे कि इस सदन में बहस करने से महंगाई में कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोग केवल बहस ही करते हैं, असली खेल तो नंबर पर होता है। जिनका नंबर ज्यादा है, उन्हीं की मर्जी से जो कुछ भी होगा, होगा, हम लोग केवल अपने सुझाव दे सकते हैं। यह संकट सुझाव देने का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई को सरकारी पार्टी ले रही है, वह थोड़ा चिंतनीय भी है और हास्यास्पद भी है। एक हफ्ते से लगातार अखबार से यह प्रचार चल रहा था, सरकार की तरफ से कोई न कोई बयान देता था कि महंगाई दूर करने के लिए सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह अखबारों ने बहुत छापा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आपके पास जादुई छड़ी है। किसी विरोधी ने नहीं कहा था, जनता बोल रही थी कि महंगाई है, इसे दूर करो, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आपके पास जादुई छड़ी है, हिला दीजिए। आज का जमाना जादुई छड़ी का जमाना नहीं है यह हम जानते हैं, लेकिन अपनी तरफ से यह कहना कि जादुई छड़ी नहीं है कि हम महंगाई दूर कर देंगे, इस समय जो लोग सत्ता में हैं, इनके पुरखे भी जब सत्ता में थे तो इसी तरह के तर्क दिया करते थे। पानी नहीं बरसने पर सूखा होता था तो बोल देते थे कि आसमान में पानी नहीं है तो क्या हम बांस लगाकर पानी निकाल देंगे, कहां से पानी लाएं। इससे देश की भ्रम में पड़ी जनता भटक जाती है। यह जवाब नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक चेतावनी देकर कि जो हुकूमत करता है, देश की जनता के तकलीफ के सवाल पर अगर उसे दूर करने की करिश्माई ताकत उसके पास नहीं है, तो उसे गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। कोई न कोई ताकत होनी चाहिए। जादुई छड़ी, जादुई छड़ी एक हफ्ता चली। हमने सोचा कि मांग कौन रहा है। चिदम्बरम साहब, यह महंगाई आपकी सरकार के लिए महंगी पड़ेगी। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें आपका विरोध करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके हटने के बाद जो लोग कुर्सी पर बैठेंगे, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन आप इस समय फेल कर गए हैं। वैसे हैं तो आप विद्वान, माना जाता है कि अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो लगता है कि कहीं अंग्रेजी के प्रोफेसर होने लायक हैं, अर्थशास्त्र के विद्वान नहीं हैं। आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल कर हिन्दुस्तान की महंगाई को दूर करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता है। वह तो हिन्दुस्तानियों की बोली में ही, चाहे वह तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, उसमें निकालना पड़ेगा। अंग्रेजी बोल कर थोड़ा सा कम पढ़ेलिखे, कम समझदार लोगों पर एक रोआब तो दिया जा सकता है, लेकिन समस्या का निदान नहीं निकाला जा सकता है। हम लोग पहले अपने घर पर पिंजड़े में एक तोता पालते थे। उससे कहलवाते थे कि बोलो सीताराम सीताराम, तो तोता सीताराम सीताराम कहता। जब अंग्रेजों के जमाने में उन लोगों की हुकूमत थी, तो पिंजड़े में पाल कर हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया। बोलो सीताराम सीताराम। हम लोगों को लगता कि तोता हमारी बोली बोल रहा है। यह तोता रटन्त बोली देश की महंगाई की समस्या को हल नहीं करेगी, जो बहुत भयानक है। आप कोई नीतिगत तर्क ही नहीं दे रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक माननीय मैम्बर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें हमारी मदद करें, केवल केन्द्र अकेले नहीं करेगा। जब असेम्बली में यह सवाल पूछा जाएगा, तो राज्य सरकारें बोलेंगी कि यह केवल केन्द्र सरकार के हाथ में है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार, लखनऊ, पटना और दिल्ली स्टेट की तरफ इशारा कर देगी। यह खेल-खिलवाड़ दो सरकारों के बीच में संघीय ढांचे के नाम पर इंसान के पेट के साथ नहीं हो सकता। पेट में आग लगी हुई है। उपसभापति महोदय, कड़ुवा तेल नहीं मिलता है। हमारे-आपके बच्चों को तो मिल जाएगा, लेकिन वह गरीब आदमी, जो कड़ुवा तेल खरीदता है, जब बच्चा पेट से निकलता है, तो यहां पर एक गड्ढा जैसा होता है, उसकी दादी और उसकी मां उस पर कड़ुवा तेल रख कर हौले-हौले करती है, ताकि खोपड़ी मजबूत हो जाए और फिर उस पर कितनी भी कीमती किस्म की आफत आए, बर्दाश्त करने की ताकत आ जाए। आज उन बच्चों के मूंह उदास हैं। कोई भी दादी हौले-हौले करके 80 रुपए किलो सरसों का तेल नहीं खरीद पाएगी। कल को वही तो हिन्दुस्तान के मालिक बनेंगे और जिनकी खोपड़ी में दम नहीं रहेगा, वह देश का मालिक बन कर क्या करेगा। इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मैं मोटर वगैरह, पेट्रोल, इस पर नहीं जा रहा हूं। हमारी बुनियादी जरूरत, हमारे जिस्म की बुनियादी जरूरत है, आज वह बाजार से गायब है। आम तौर से जो चर्चा होती है, यह जो किसान पैदा करता है, उसकी पैदावार

बढ़ें अबकी बार थोड़ा बहुत महंगा हो गया है, पहले के मुकाबले एक-दो रुपया बढ़ा है। इस पर हल्ला मचा है। महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। हम जानते हैं कि किसान की पैदावार सबकी जिन्दगी की हिफाजत करती है। अगर किसान पैदावार नहीं करेगा, तो यहां का आदमी भूखों मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। दिल्ली के सब लोग मरने लगेंगे, यहां खेती नहीं है। शहर के बाबू मर जाएंगे। यह जरूरी काम है, उसको ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, लेकिन समाज में उसका सम्मान कम है। वह जो पैदा करता है, जितने में पैदा करता है, सरकार उसका मूल्य कम में निर्धारण करती है। मान लो कि उसका गेहूं 1,200 रुपए क्विंटल में तैयार होता है, तो सरकार उसको 900 रुपए, 850 रुपए देती है वह घाटे का सौदा करता है। वही सरकार विदेश से गेहूं मंगाना चाहती है, तो 1,800 रुपए क्विंटल, 2,000 रुपए क्विंटल मंगाती है। अब गेहूं पैदा करने में किसानों की हिम्मत छूट रही है। कई लोगों ने तर्क दिया कि किसान पैदावार ठीक नहीं कर रहा है, इसे हिम्मत बंधाओं। भई, हिम्मत कौन बंधाएगा? उसको दाम देकर ही हिम्मत बढ़ाई जाएगी। अब किसान अनाज पैदा करने के बजाए कैश क्रॉप पैदा कर रहा है। वह भाग रहा है तमाखू की तरफ, कपास की तरफ, दाल की तरफ और तिलहन की तरफ। वह सोचता है कि इसमें आमदनी नहीं है और हमारी पैदावार से ज्यादा कीमती वहां की पैदावार है। एक तो कभी न कभी हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के किसान को मुनाफे का मूल्य दिया जाएगा या नहीं? आज भी उसे मुनाफे का मूल्य नहीं दिया जा रहा है और मैं जानता हूं कि जिस किसी दिन मुनाफे का मूल्य देने की बात चलेगी, ये दफ्तर के बाबू लोग कहेंगे कि यह महंगाई फैला रहा है। मैं यह नहीं कहता कि महंगाई फैलाओ, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसा फंड हो कि उपभोक्ता को सस्ते रेट पर सामान मिले और किसान को देने में उसका जितना खर्चा पड़ता हो वह सरकारी खजाना दे। इस तरह कई तरीके निकाले जा सकते हैं।

उपसभापति महोदय, पलटन के जवान की कुर्बानी जरूरी मानी जाती है, तो उसके लिए पलटन के इलाके में कई जगहों पर सस्ते रेट की दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन किसान जब कपड़ा खरीदने जाए, किसान जब ट्रैक्टर खरीदने जाए, किसान जब पेट्रोमेक्स खरीदने जाए, उसके लिए भी सस्ते रेट की दुकान कर दो। किसान का बेटा भी बुनियादी तौर पर केवल किसान है और उसका बेटा जब स्कूल में जाता है, तो उसकी किताब-कॉपी सस्ती कर दो और उसकी पढ़ाई सस्ती कर दो। उसका गेहूं आप सस्ते में खाओगे और उसके बच्चे की पढ़ाई सस्ती नहीं करोगे? उसको ट्रैक्टर चाहिए या उसके घर में कोई टेलिविज़न बजाना चाहे, तो वह उसे सस्ते में नहीं दोगे? यदि ऐसा करोगे तो वह गेहूं बोना छोड़ करके कपास बोएगा, तमाखू बोएगा और तब आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा।

मैं जानता हूं कि मंहगाई के कारण दुनिया में आज तक कोई बगावत नहीं हुई है, केवल आदमी का पेट जलता है। पांच दिन न खाने के बाद अगर छठवें दिन भी उसे खाने को मिल जाता है, आदमी बड़ा ही सब्र वाला जानवर है, छठवें दिन खाने के बाद फिर से वह सात दिनों के लिए जी जाता है। बगावत तो किसी आफत के ऊपर आती है, जिसमें जज्बात जुड़े रहते हैं। किसी अर्थशास्त्र के सवाल पर जल्दी बगावत नहीं आती है। मैं जानता हूं कि यह बगावत का मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से गांव के लोग, गरीब लोग गरमा रहे हैं, उस गर्मी को यह सरकार झेल नहीं पाएगी। उसके लिए मैं अभी से आपको चेतावनी दूंगा। यह सही है कि कई तरह के दाव-पेंच चलते हैं, पूरे बिहार से ले करके उत्तर प्रदेश में आलू इस समय एक रुपया, डेढ़ रुपया किलो बिक रहा है और हम यहां पर महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहां आलू एक रुपया किलो है। आम तौर से जो दुकानदार लेकर यहां घूमते है, आपके बाजार में आलू आठ रुपये या दस रुपये किलो है। आजादपुर मंडी में वह साढ़े तीन या चार रुपये किलो होगा।

माननीय सदस्य: मुम्बई में तीस रुपये किलो है।

श्री जनेश्वर मिश्र: जी हां, मुम्बई में तीस रुपये किलो है। क्या दिल्ली की सरकार लालू प्रसाद के मंत्रालय से यह नहीं कह सकती कि कुछ माल गाड़ियां जल्दी दो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का सारा आलू इकट्ठा करके कुछ महाराष्ट्र में भेज दिया जाए, कुछ दिल्ली भेज दिया जाए और कुछ गुवाहाटी भेज दिया जाए। सब्जी में अगर एक बार आलू सस्ता हो गया तो सारी सब्जियां घुटने टेक देंगी, क्योंकि महंगाई का एक यह भी नियम है कि एक ईंट खिसका दो तो बाकी ईंटे भड़भड़ गिरने लगती हैं। इसलिए कहीं कोई चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। इस सरकार को सलाह देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम इसकी आलोचना करना है, क्योंकि मैं विरोधी हूं, लेकिन लोगों की तकलीफ देख करके मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो गेहूं होता है, दुनिया में ऐसा गेहूं कहीं भी नहीं मिलता है। वह गेहूं ऐसा है, जिसमें लसाड़ बहुत होता है। वह उसे सानते समय तो नहीं आएगा, लेकिन पकने के बाद उसको खींचिए तो दूर तक तार आएगा। वह गेहूं केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। दुनिया में ऐसा गेहूं और कहीं भी नहीं होता है, न ही हिन्दुस्तान में किसी और स्थान पर होता है। ये पीज़ा बनाने वाली, डबलरोटी बनाने वाली और बर्गर बनाने वाली जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के यहां आजकल पीज़ा बड़ा गजब का हो गया है। पहले एक टोबैको बनाने वाली कंपनी थी, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन....(व्यवधान)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): पहले इम्पीरियल थी लेकिन अब इंडियन है।

श्री जनेश्वर मिश्र: उसको इस समय किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है और वहां पर तमाखू के साथ-साथ पीज़ा भी बनता है, बर्गर भी बनता है, डबलरोटी भी बनती है। वहां यह सब बनने लगा है। खैर, कोई कहीं पर कोई भी चीज़ बनाए, उस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वह जो गेहूं है, उसको यह सारी कंपनियां खलिहान से जा करके 1200 रुपये क्विंटल के भाव से खरीद लेती हैं। किसान सोचता है कि कौन ढोकर के ले जाए, इसे यहीं बेच दो। किसान भी काम करते-करते थोड़ा थक जाता है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि कुछ भाई लोग हारवेस्टर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस महंगाई के विषय में वह नहीं आता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खेती को मशीनों की तरफ बहुत मत फेंको। एक जमाने में खेती को ट्रैक्टर की तरफ फेंक दिया, हम लोगों के दरवाजे पर जो बैल बँधे रहते थे, जिनकी घंटी टुन-टुन बजती थी, वे सब बिहार के रास्ते कोलकाता चले गए, गोश्त के लिए कटने। हिन्दुस्तान में कम-से-कम 6 करोड़ लोग हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं और उन्हें 4 महीने का खाना मिलता है। आप हारवेस्टर मंगा दोगे, तो बैल तो आपने कटवा दिया गोश्त के लिए, अब आदमी की गर्दन भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं काम नहीं पाएँगे। खेती को कम से कम मशीन की तरफ बहुत मत फेंको। यह वामपंथी और दक्षिणपंथी सोच का सवाल नहीं है। कुछ चीजें तो अपने आप करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह कुदरत पर ज्यादा मुनस्सर करती है, वह केवल आपकी मशीन पर नहीं चलती है। लेकिन एक मित्र ने बोला था, इसलिए उसका जवाब दे देना जरूरी था।

सर, महंगाई चरम सीमा पर है। इसके लिए वित्त मंत्री जी भी थोड़ा-बहुत दोषी हैं और इनकी सरकार भी दोषी है। पे कमिशन की रिपोर्ट इन्होंने यहाँ रख दी। उसके बाद यह महंगाई बढ़ गई। उसे दो महीने बाद ही रखते, क्या जल्दी पड़ी थी। याद रखिएगा महंगाई में जब कभी भी इंसान की आमदनी में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, किसी भी कमिशन की रिपोर्ट क्यों न हो, उसके बाद बाजार तरतराता है। उसके बाद वह किधर को जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह 90 हजार रुपए कर दी गई, बाकी सेक्रेटरीज़ की तनख्वाह 80 हजार रुपए कर दी गई है। कल्पना कीजिए, सर। अभी किसी को एक धेला नहीं मिला है, आपने केवल रिपोर्ट रखी है, तब तक बाजार गड़बड़ाने लगा है। बाजार गड़बड़ा रहा है, तब आप कहते हैं कि कोई जादुई छड़ी नहीं है। जादुई छड़ी नहीं है तो क्या है? कौन हल करेगा? जो जादुई छड़ी नहीं रखेगा, वह सरकार भी नहीं चला पाएगा। श्री मोरारजी का, 1977 का जमाना याद कीजिए। आप लोगों के जाने के पहले जो बाजार भाव था, मोरारजी के पास जादुई छड़ी थी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक मामूली कदम से उस बाज़ार भाव को चौथाई पर ला कर के रोका था। यह सब लोग जानते हैं। वह जनता पार्टी का जमाना था। अब भी वह गीत गाते हैं। कोई-न-कोई जादुई करिश्मा दिखाना पड़ेगा। यह सोचना आपका काम है, मेरा नहीं है। आपने इधर कई तरह के बाजार बना दिए हैं। यह जो आपका वायदा कारोबार का बाजार बना है, यह तो डाकुओं का अड्डा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, वे सामान नहीं खरीदते, बात खरीद लेते हैं, बात की तिजारत होती है, टेलिफोन से तिजारत होती है और हजारों करोड़, लाखों करोड़ का सामान मंडी में पड़ा है और टेलिफोन पर उनका सौदा हो गया और जब चाहें उसका भाव बढ़ा दें। उनकी इन हरकतों पर निगरानी रखने के लिए कोई पारदर्शिता नहीं है। शुरू के दिनों में तेल, दाल, गेहूँ, चावल, ये सब चीजें उसमें नहीं आती थीं, बाद में उन्हें भी आने दिया गया। अमेरिका का कोई बहुत बड़ा वायदा कारोबारी है, यानी हिन्दुस्तान में वायदा कारोबार में जितनी पूँजी लगी है, उतनी पूँजी उसने सारी दुनिया में लगाई है, वह इतना बड़ा आदमी है। हिन्दुस्तान की सरकार ने उसको वीज़ा दे दिया कि आओ, तुम भी काम करो। हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? जब मैं पिज्ज़ा की बात कर रहा था, तो हम हिन्दुस्तानी पिज्ज़ा तो खाते नहीं हैं, हमारे देश में यह पहले नहीं बनता था। हाँ, चिदम्बरम साहब, आपकी नेता जिस देश से आती हैं, वहाँ पिज्ज़ा

जरूर खाया जाता है। ठीक है, पिज्ज़ा खाइए, लेकिन अमेरिका के उस कारोबारी का नाम सभी लोग जानते हैं। उसका नाम वॉल मार्ट है। ...(व्यवधान)...सर, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। एक बार हमारे किसी मैम्बर को चिदम्बरम साहब ने कहा था कि मैं अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं पाओगे। तो माननीय सदस्य को खड़े होकर थोड़ा अंग्रेजी बोलनी पड़ी थी। हमको हंसी आती है। उस दिन हम नहीं थे, वरना हम कह देते कि हमारे यहां यह अंग्रेजी बोलना कोई शान की चीज नहीं है। हम अपने लोगों की आम जनता की खिदमत कैसे करते हैं, सियासत में वह शान की चीज है। सियासी आदमी के लिए भाषा की शान, बालों की रंगाई की शान, कपड़े-लत्ते की शान का कोई महत्व नहीं होता। इन्होंने कह दिया था, तो हमने गलती मान ली कि हम अंग्रेजी में वॉल मार्ट नहीं कह पाते। तो आपने उस तक को बुला लिया और बुलाने के बाद किस तरह से इन्होंने बाजार पर कब्जा किया? अब सुना है कि गेहूं, चावल वगैरह पर से इन लोगों ने जो पहले बैन हटा लिया था, उस पर फिर रोक लगा दी है। वह लगाई है या नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि बाजार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बाजार हिल नहीं रहा है। इस समय यह बिगड़ा हुआ बाजार हो गया है।

उपसभापति महोदय, कहीं-कहीं मुम्बई वगैरह में कुछ छापे पड़े हैं और बड़े-बड़े लोगों पर छापे पड़ने के बाद गल्ला थोड़ा पकड़ में आया है। हमारा ख्याल है कि यह कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति है। मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम साहब और शरद पवार जी के बीच में जो चलता रहता है, तो लगा कि उस राजनीति का थोड़ा मुम्बई में खेल दिखा दो और थोड़ा यहां भी दिखा देना जरूरी है, क्योंकि एक लड़का प्रधान मंत्री के लिए नया उम्मीदवार उभर रहा था। तो यह चल रहा था कि अब मनमोहन सिंह जी का पत्ता गोल होगा, थोड़ा यह हुआ कि महंगाई बढ़ा दो, तो इससे इनको उतरने में आसानी हो जाएगी। कितनी राजनीति होती है? हमारे पेट की आग में इतनी राजनीति जलाई जाएगी और हम भूखों मरते रहेंगे, हमारे बच्चे भूखों मरते रहेंगे, यह हम नहीं सह सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि 15 दिन का समय लो, 10 दिन का समय लो और अगर आप महंगाई नहीं रोक पाते हो, तो इस देश को छुट्टी दो। कोई न कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि इस देश का आदमी अपनी जिंदगी खुद जीता है, किसी सरकार की मदद से नहीं जीता। गांव के खेत में अगर किसान वहां हल चलाता है, तो यह मत मानिए गृह मंत्री जी, कि उनके बिना हल चल ही नहीं सकता। गांव के स्कूल में अगर मास्टर अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो यह न मानिए शिक्षा मंत्री जी, कि उनके बिना मास्टर पढ़ा ही नहीं सकता। इस देश का हर आदमी अपने जीने के लिए काम कर रहा है। उसकी जिंदगी को दूभर करना और दूभर करने पर जब हम फरियाद करने आएं, तो आप इशारा कर दो कि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, यह नहीं चलेगा।

उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि एक तर्क दिया जा रहा है कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, दुनिया के बाजार में महंगाई आ गई है। यह महंगाई कितने प्रतिशत, कितनी जगह बढ़ी है, इस बारे में एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि तीन-चार देश हैं, जहां बढ़ी है, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है और कोई एक और देश है, यह महंगाई ज्यादा श्रीलंका में बढ़ी है, चीन में बढ़ी है। तो कुरियन साहब जब उसका जवाब दे रहे थे, तो थोड़ा सा हमारे वामपंथी मित्रों की तरफ देखकर मुस्करा रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि चीन वालों ने अपने आदमी की हिफाजत के लिए कितना प्रबंध किया है? आदमी की जिंदगी की हिफाजत का पूरा प्रबंध करने के बाद अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ जाती है, तो चिदम्बरम साहब, हम आपको माफ कर देते। आदमी की जिंदगी की हिफाज़त और पूरी हिफाज़त जरूरी है, इसलिए वह शोक मत दिखाइएगा। थोड़ा खर्च कम करना पड़ेगा, खर्चे कुछ ज्यादा हो रहे हैं, फिजूलखर्ची ज्यादा हो रही है । खाली खर्चे इस तरह के नहीं होते कि आपने किसकी कितनी तनख्वाह बढ़ा दी है, खर्चे कई तरह के होते हैं। तनख्वाह बढ़ा दी, उसके बाद दूसरी सुविधाएं बढ़ा दीं, परिवार के लोगों की सुविधाएं बढ़ा दीं और अगर टैटल कीजिएगा तो 92 हजार नहीं, 2 लाख से ऊपर हो जाती है। फिर दूसरे अधिकारी चाहते हैं, फिर कर्मचारियों के मन में आता है। कर्मचारियों को जब भरपेट नहीं मिलता, तो उसके बच्चे छटपटाने लगते हैं। गांवों के किसानों में क्या हो रहा है? पुराने जमाने में जब किसान की फसल मारी जाती थी, तो वह आत्महत्या करता था। आज के किसान का बेटा, किसान की जब फसल मारी जाती है और साहूकार उससे कर्जा लेने आता है, तो आज के किसान का बेटा उसको जान से मार देता है और तब कहा जाता है कि वामपंथी हिंसा बढ़ गई है। ये दोनों एक साथ चलेंगे, हम खुदकुशी करेंगे और हमारा बेटा बंदूक उठाएगा। यह लड़ाई कहीं तो बंद करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गल्ला कम हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि हिन्दुस्तान के बाजार में सामान कम हो गया है। सामान है, सजा-सजाया है, मॉल में तो बहुत ही सजा है। माल सजा है, लेकिन खरीदने की ताकत

जेब में नहीं रही और हमारे बाप की जेब में खरीदने की ताकत नहीं है, हम क्या करेंगे? हम उन दुकानों को लूट लेंगे और तब आप हमको कहेंगे कि वमापंथी हिंसा, नक्सलपंथ मत किया कीजिए। कई जगह से रिपोर्ट आई है कि आपके मॉल्स में ऐसे लोगों ने भी पूंजी लगाई है, जो आतंकवादी चरित्र के हैं। गृह मंत्रालय की एक सलाहकार ने भी यह बयान दिया है। अगर इस तरह की पूंजी लग रही है और उस पूंजी से आदमी का पेट नहीं भरता, सामान बाजार में है, तो यह क्यों नहीं सोचते कि उसका नतीजा निकलेगा और बूढ़ा तो लूटने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन नौजवान उन दूकानों को लूट लेगा। इसलिए या तो वहां पुलिस का इंतजाम करो और नहीं तो इस तरह की बकवास की दुकानें बंद करो। खोमचे वाले या फुटपाथ पर जो दुकानें लगा करती थीं, वे बंद हो गईं। सब्जी खरीदने के लिए साज-सजावट का खर्चा क्यों बढ़ाया जा रहा है? यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है। कभी-कभी सड़क पर, फुटपाथ पर दुकान बनी होती है तो लगता है कि पर्यावरण का मामला फंस गया, तो उसकी निगाह में किरकिरी आती है। उसके आदेश का पालन करो, लेकिन बहुत बड़े और बूढ़े लोग जब बुढ़ापे का आदेश देते हैं तो सम्मान से सर झुकाकर बगल से निकल जाना चाहिए। कानून और आदेश के पालन करने का एक तरीका यह भी है, सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। लेकिन कई जगहों पर दुकानें टूटने लगीं, दिल्ली के हलवाई और दूसरे दुकानदार हल्ला करने लगे कि दस पुश्तों से हम काम कर रहे हैं। बाजार गरम हो गए, जगह-जगह बाजार गरम हो गए और उपभोक्ता अगर बाजार की तरफ चला गया तो वह बहुत बुरा हो गया। उपभोक्ता अगर आपके यहां सड़क पर आ जाता है लड़ने के लिए तो हम लोग उसके बीच में खड़े होकर कायदे का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता बाजार की तरफ चला जाता है, तो वह पुलिस की गोली के अलावा रुकता नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता, चिदम्बरम साहब कि हिन्दुस्तान का उपभोक्ता, जो अधखाए पड़ा है जो एक जून खाता है, वह बाजार की तरफ चला जाए, सड़कों पर निकल जाए। वह राजनीतिक पार्टी के लोगों के बूते के बाहर जा रहा है, क्योंकि उसका पेट जला है। उसके बच्चे का मुंह सूखा हुआ है और वह गुस्से में निकल गया, हमारे पास नहीं आया। हम विरोधी तो मार खाकर भी आपको बचाते हैं, लेकिन वह अगर उधर चला गया तो आपको गोली चलानी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको ही मार खानी पड़े, हम लोग एक तरफ खड़े रहेंगे।

उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने की इजाज़त दी, लेकिन इस सरकार से कहिए कि थोड़ा शऊर से रहें ये लोग शऊर खो चुके हैं और अगर ये शऊर से नहीं रहेंगे, बाजार इस तरह से बिगाड़ते रहेंगे तो इस देश को चलाना मुश्किल होगा। तब यह देश अफरा-तफरी का हो जाएगा, लूट-मार का देश हो जाएगा। यह देश गांधी जी का देश कहा जाता है और कांग्रेस पार्टी तो गांधी जी को अपना पुरखा मानती है। इसलिए अगर ये शऊर से नहीं रहेंगे, तो देश में अफरा-तफरी हो जाएगी, देश में मॉल संस्कृति आ जाएगी और वायदा कारोबार में जैसे वाल मार्ट वगैरह अमरीकन आया है, वे सब आने लगेंगे। कहां हम लोगों ने विदेशियों को भगाया था और कहां आप उनको लाने लगे हैं। आपके ही नेता लोगों ने तिरंगा लेकर हम लोगों को सिखाया था कि विदेशियों को भगाओ, हम लोगों ने भगाया था, लेकिन आप खुद विदेशियों को बुलाने लगे! कुछ लोग शादी-ब्याह करके बुलाते थे, हमने ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन अब बुला रहे हैं, हम ऐतराज़ करेंगे। हमारे रोजगार में मत बुलाइए। धन्यवाद।

श्री सीताराम येचुरी: उपसभापति महोदय, जैसा कि अभी कहा गया, इस सदन में कई बार महंगाई के ऊपर चर्चाएं हुईं, लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है, यह इस तरीके की महंगाई के बारे में चर्चा हो रही है, जो हम समझते हैं कि सिर्फ आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि एक तरीके से दो भारतों की सृष्टि कर रही है–एक तरफ है एक चमकता भारत और दूसरी तरफ है एक तड़पता भारत और ये दोनों भारतों की सृष्टि जो आज हो रही है, उसका बहुत ही गहरा संबंध इस महंगाई के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि आज Wholesale Price Index के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह 7 और 8 के बीच में है, लेकिन जरूरी चीजों के दाम अगर आप देखें, ये आंकड़े मुझसे पहले अभी बोले गए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तेल ऐसे हैं, जिनके दाम 6 गुना बढ़ चुके हैं और अनाज का दाम करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुका है, जो vegetables and fruits हैं, उनके दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यह जो महंगाई हो रही है, यह इस संदर्भ में हो रही है, मैं इस ओर आपकी दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगा कि जब अपने देश के अंदर इसी सरकार ने बड़े गर्व के साथ और हमने भी आलोचना के साथ इसका समर्थन किया था कि आप mid-day meal scheme के लिए खर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन आज इस महंगाई के चलते हमारे बच्चों को इस mid-day meal scheme

के अंतर्गत जो खाना मिलेगा, आपने जो plan किया था, उसके मुकाबले उसकी nutritional value आधी हो जाएगी। आज तकरीबन 78 प्रतिशत गर्भवती माएं ऐसी हैं, जो anaemic हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, आज तकरीबन हमारे देश के आधे बच्चे ऐसे हैं जो mal-nutritioned हैं या जो stunted हैं। अब इन लोगों को nutrition देना है और ऐसे दाम पर देना है, जिसे वे afford कर सकें, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह हमारे लिए एक चुनौती है कि हम इस चमकते भारत को सबके लिए चमकता हुआ भारत बनाएं या चंद लोगों के लिए चमकता और बाकी सब लोगों के लिए तड़पते भारत के रूप में हम इसको उतारकर ले आएं। इस महंगाई के सवाल को आप एक हल्के रूप में न लें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर हमारे समाज पर पड़ रहा है और ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिसका परिणाम बड़े लंबे समय तक हमारे ऊपर रहेगा।

उपसभापति जी, दूसरी बात यह है कि inflation is also an income redistribution mechamism. When prices rise, inflation redistributes income away from the working population towards those who earn profits. So, in this process, through inflation, you are actually subsidising the rich and you are taxing the poor; and it is again dividing the society and widening the hiatus between the 'shining India' and the 'suffering India'. So, on both these counts, I think, tackling this inflation is a very important challenge before this Government, and if it fails to do that, I am afraid that all the hopes with which we have supported this Government will also have to be rethought. And that is something which we do not want them to force us to rethink about because we think that this can be tackled and how this can be tackled is what I would like to propose.

Sir, my friend, Shahid Siddiqui, is bemoaning. He is saying that this position has come a little too late. ...(*Interruptions*)... No; no; but the point is that ...(*Interruptions*)... I will come to it; I will come to it. My interest is to reduce the prices. My interest is not to provide my shoulder for somebody else to fire his guns. As has been stated here by our hon. Professor, yes, inflation, all of us know, always happens because of a mismatch between demand and supply. The question is, why does this mismatch occur? One obvious thing, to correct this mismatch, is to increase your production. There is no doubt about it and that is why we have always emphasised it. In fact, if you recollect, Sir, the Common Mimum Programme of this UPA Government talks in terms of doubling public investment in agriculture. Now, what have you done in the last four years? How much of new irrigated land has been added?

How much have we actually invested in new, high-yielding varieties of seeds? Now, these are serious questions and this is something which is a very serious matter, which has to be addressed. But there has to be a long-term solution. Yes, we have to think about it now. So, only to say that our production has not been increasing and, therefore, the mismatch, is only an excuse. Actually the basic question is of how we can today tackle the situation. The second trend that has been stated here is that this is a global phenomenon. Now, this is nothing new. We have heard this since the days of Shrimati Indira Gandhi, 'corruption is a global phenomenon', 'unemployment is a global phenomenon' and, now, 'inflation is a global phenomenon'. Now, I do not discount the fact of the global impact. Yes, the rise in the prices of oil products has had a very big impact on food prices because oil is a very important input in agriculture and, therefore, the costs of production have risen. That is a fact. It is also a fact that the shift that is being made towards bio-fuels is also impacting the availability of foodgrains for the consumption of human beings. Here, Sir, we must remember that one fact dramatically tells you what this impact would be, that, for instance, 20 per cent of the production of maize in the United States of America is today earmarked for biofuels, and the amount of maize that is required to fill the tank of an average car is equivalent to the annual consumption of maize of a well-bodied African male today. What he consumes the whole

3.00 P.M.

year is what is required to fill the tank of a car on an average. Yes, that is danger that we will have to take care of. The third factor is that there has been a crisis in agriculture globaly and that global crisis has also brought down production of foodgrains. And economists will tell you, there is a famous curve called the Phillips Curve; that you encounter this whenever production goes up; it is met with the wall of inflation. Now, that is also a fact that is operating. Yes, nobody is denying these three factors. But why is it that in the last one year the prices of foodgrains have shot up so dramatically? In the last one year, if you look at the prices of wheat globally, it has gone up by 92 per cent till February 2008. The prices of Soyabean have gone up by 65 per cent till February 2008. Why this sudden spurt now? The other three global factors have always been there. That is where you are failing to put your finger on the actual cause and, that is, that all this has been happening in the last year because of a severe crisis in the world financial markets and system that has been triggered by the sub-prime crisis in the United States of America. All these financial players, to cut their losses from the sub-prime crisis and the recession in the United States of America, are shifting into newer areas, and the area that they have chosen and where they are playing havoc today globally, the global speculators, is the futures trading and forward trading of foodgrains. And it is in this area where they have concentrated upon to cut their losses and we have to pay the price for that. And how do we, therefore, insulate ourselves from this? The only way to insulate ourselves is not merely to put a break on this process of reckless liberalisation that has been taking place but actually to reverse this process in order to protect ourselves and insulate ourselves from this global trend. That is where we want this Government to state that there are global factors that are at play leading to the rising prices, but there are many measures that we can take to insulate ourselves from this and if we do not do that, I am afraid—our senior Shri Janeshwar Mishra has talked only of some countries where the prices have risen, नहीं साहब, आप बहुत सारे देशों में food riots हो रहे हैं। अफ्रीकन देशों में, जहां पर उनको अनाज नहीं मिल रहा है, वहां food riots हो रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी हालत यहां पर आए। अगर इसको रोकना है, तो पहले जो हमारे पास procurement और distribution mechamism हुआ करता था, जिसके चलते हम international speculations से अपने आप को बचा लेते थे, अब आपने इसको भी abandon कर दिया है। We have abandoned the entire system of a security net for our own people through the procurement and distribution mechanism that we had in place, howsoever inefficient. We had it in place in the past and, instead, you are now prostrating before the god of liberalised markets. Now, what happened in the year 2006? In the year 2006, Cargil India, the Australian Wheat Board, and two Indian based companies with a log of foreign hold too in them, the ITC and the Adani Export, procured 30 lakh tonnes of wheat and that process has been going on. There is a reasons why I am using 2006 as a benchmark. But that process has been going on and the net result has been that the procurement by the Government has been constantly and dangerously falling. What was it? In 2003-04, you had procured 16.8 million tonnes, in 2004-05, this came down to 14.8 million tonnes and now it has come down from 11.1 million tonnes to 9.2 million tonnes. This reduction in procurement is reaching such a drastic level that it is now estimated that on the 1st October, 2008 the rice stock in our country will be 5.49 million tonnes as against a buffer norm of 5.20 million tonnes and the wheat stock will only be 10.12 million tonnes as against a buffer norm of 11 million tonnes that is required. So, as a result, you have created a situation of food insecurity in our country by allowing these huge multinational corporations to move in agro business. You have allowed our procurement to drastically reduce and this has resulted in a serious situation that is looming before us, that is, food insecurity. Further, here, we have to understand how do these people make their killings.

How do these corporations actually make their killings? There are three particular steps that they would require in order to make super profits out of rising prices of foodgrains and essential commodities in our country. The first is that the Government must be made so helpless or so weakened that it should not have large stocks to dempen the spot prices as a moment in this speculative trading. So, reduction in Government stocks is imperative for them to speculate on prices of foodgrains and that is what they have achieved over the last few years of having gained entry into this market. Secondly, the private trade must have adequate stocks and that they can intervene in the market whenever it is required in order to keep prices at a higher level. Thirdly, no institutional mechanism for distribution of foodgrains must exist in the country and that is why we see this fall in procurement accompanied by the dismantling of the Public Distribution System and it is this that has brought this about. Here, I am just quoting the London Economist. He says, "That Multi-commodity Exchange in India averages volumes of over 3 billion dollars a day." Three billion dollars a day is the speculation that is taking place in the commodity exchange market of futures and forward trading and in this we now have over the last few years three national level electronic exchanges, twenty-one regional exchanges and eighty commodities have been allowed to participate in this derivative trading and the list is continuously growing. Last fortnight, from 17th March to the 31st March, the total value of trading at these commodity exchanges was Rs. 2,12,465.17 crores in two weeks. This is the volume that has been transacted in the market and the cumulative value of trade in the last financial year, from 2nd April, 2007 to 31st March, 2008, was to the tune of Rs. 40,65,989 crores. Look at the size. The Finance Minister is here. How many times of our Annual Budget is this? The cumulative value of trade that is happening in these commodity exchanges is Rs.40,65,989 crores, and this has been growing from Rs. 36 lakh crores in 2006-07 to Rs. 40 lakh crores whthin the span of these twelve months. This is the dimension that we are talking of, and if this is the dimension of speculation that is taking place in the foodgrains market in the futures and forward trading, how is it impacting on prices? I told you earlier, how they require to keep the price levels high, how they will dismantle your procurement system and your buffer stocks, how they will dismantle your Public Distribution System and how they will keep stocks with themselves in order to enter the market and this is the process through which they are manipulating this entire price situation, and unless we guard against it, it will be impossible for us to actually contain this price rise. Why do I say this? You look at some of the starting figures. You take the production of grams in 2005-06. We produced 57.8 lakh tonnes. We imported between 3-4 lakh tonnes. If you add that, a little over 60 lakh tonnes is what the stocks we have. And what was the volume of future trades in the commodity exchange, at that time, against this 60 lakh tonnes? The trade took place for 742 lakh tonnes because in futures trading, there is no actual exchange; there is no real exchange. It only takes place as a transaction. That is the speculation. And, what was the value in rupees? It was Rs. 1,39,864 crores. Now, your production is 60 lakh tonnes including imports and you are speculating for 750 lakh tonnes already and I have these fugures for all these things—for guar seed, for soya oil, for arhar dal, for castor seed and—everywhere, you find speculation is taking place at 100, 200 and sometimes, 300 times the physical stock that you have. If the speculation is taking place at this scale, does it not impact prices? Does it require more than common sense to acually see that unless were are able to stop this sort of speculation, we are not going to release the pressure on an upward movement of prices? In spite of all this, you have, on the 18th of March, 2008, permitted trade in 32 additional commodities. You have permitted them to go up till December, 2009. What are these commodities? These are coconut oil cotton seed, cotton yarn, castor seed, castor oil, coconut cake. Including all these items, you have included

32 of them further. The point that we are making is that this speculation in foodgrains; trade, which is one of the major causes for this rise in prices, have to be contained. This is a fact now towards which I want to draw the attention of the House and of this Government. This is nothing new that the Left parties have been saying or the CPI (M) has been saying. We have been saying right from the time this Government was formed. In 2006, there had been a very big debate on this issue. Very often, the UPA Chairperson is invoked, I think, I will also invoke from a different point of view. This is what Mrs. Sonia Gandhi said in the Congress Parliamentary Party meeting in August, 2006. I quote, "The Prime Minister and I had a meeting with our Chief Ministers. They were unanimous that forward trading, particularly in wheat, has had an adverse impact and called for a more effective framework to deal with speculation." This is not what I am saying. This is the Chairperson of the UPA who was saying that. So, when she says, "to deal with speculation, effective framework", our question is: why is it that you have not done it? It is not only betraying us; it is not betrarying the people of this country; it is betraying your own leadership that you have not undertaken this; and this is what you have to understand that there is a betrayal down the line that is taking place here, and this is all happening only for the super profits of few corporations. And, are we to hold ourselves and Indian people as hostages, there are 1.1 billion of them? When we talk of 70 crores of Indians below the age of 40 today, that youth to whom if we can give proper health and nutrition, you give them education, you give them employment. They will build a better India, Sir. And, that is what you are denying. That is why, this price rise is not only an issue of containing prices, but this is actually a blueprint of disaster for the future of our India. If we want to build a better India, then what do we have to do, this is something they have to seriously consider. Therefore, we demand an immediate ban on the future trading of 25 commodities listed by the Parliamentary Standing Committee, and this is necessary to untie the apron strings to liberalisation that this Government has got itself in tangles. And, they will have to get out of this crisis by doing that. Further, I think the entire analysis of why this inflation is taking place is also being grossly misplaced by the Government. The argument we are hearing is that inflation is taking place because there is greater liquidity in the market, which means there is greater money supply in the market. Now, this is a cruel joke. Yes, you may have 36 billionaries in our country according to the Forbes. But, at the same time, Mr. Arjun Sengupta's Committee has told us that 78 per cent of Indians live on less than Rs. 20 a day. So, 78 per cent of India is living on less than Rs. 20 a day, and they are the ones demanding foodgrains, not your billionaires. You billionaires have enough food to eat. The demand for foodgrains is coming from this 78 per cent people who have less than Rs. 20 a day, and who have no liquidity? Where is the greater liquidity with them? this is the cruel joke. What is happening as a reslt of it? As a result of it, the opposite effect is happening. In order to reduce the liquidity, interest rates have gone up, which means the manufacturing sector has been adversely hit hard because the cost of capital has gone up. As a result of it, the sale of consumer durables has dropped drastrically, meaning thereby that the production in the manufacturing sector has declined, which results in greater unemployment and more people being added to starving or suffering India.

Secondly, because of this whole philosophy of greater liquidity, you have not allowd to marshal, or, let us say the pegging down the appreciation of the Indian rupee. And, when the appreciation of the Indian rupee has not been pegged down, what is the result? I has grown thirteen per cent in the last one year. All export industries have suffered. Our friends from Tamil Nadu will tell you about Tirupur, which is in Coimbatore District—we were there for a week for the Party conference---where they have lost 60,000 jobs in the last one year

because of this rupee—appreciation and because your exports are not longer competitive in the international markets. So, this is the net result of the wrong diagnosis. Not only are we not containing prices but also we are pushing the economy into such a crisis that it will be very difficult for us to get out from. In addition, you are widening the hiatus between 'Shining India' and 'suffering India'.

Sir, we have heard enough of the fact that increase in fuel prices has contributed to inflation. Yes, I have already accepted that. But there is another aspect to it. Through the direct taxes in Central duties, the Central Government has earned roughly around Rs. 90,000 crores. Hon. Finance Minister is here and it I am wrong, he can correct me while giving reply. In addition to this, the State Governments have earned Rs. 60,000 crores in terms of State taxes. So, putting together, the Governmental revenue comes to Rs. 150,000 crores. Now, why do we import oil, Sir? We import oil because we do not produce enough and because we do not produce enough oil without oil, our economy will starve, we cannot economically grow. So, oil is a essential commodity. When there is a famine in the country, when people are dying, we import foodgrains becuase we want our people to survive. We import oil because we want our economy to survive. When you import foodgrains to make you people survive, do you put taxes on the foodgrains? You are importing foodgrains because your people are starving. Similarly, you are importing oil because your economy is starving, and, here, you put taxes on it and turn that as revenue. This being an essential import, these taxes have to be reconsidered and the *ad-valorem* tax structure that is being imposed on the petroleum products should be converted into volume-level taxes and the burden of this tax-revenue earning by the Government cannot be and should not be passed on to the people in terms of higher prices. Therefore, Sir, in order to reduce the burden of this tax structure on the people, we demand that the Government should reverse this tax pattern that we currently have.

Further, as I said earlier, how do we combat this inflation? Only by strengthening procurement and strengthening Public Distribution System! Instead, what do we see here now? What has happened in the last one year? (*Time-bell*) I am concluding, Sir.

Sir, in the last 2 $^{1}/_{2}$ years, the foodgrains that are supplied to the States for the Public Distribution System as been reduced by a wopping 140-lakh tonnes. This is the amount that as been cut. In some of the Left-Parties' rules States, for example, in west Bengal, as far as wheat is concerned, from 1.22 lakh tonne, it has been cut down to 0.62 lakh tonnes. In Kerala, 1.33 lakh tonnes of rice has been cut down to 0.28 lakh tonnes. This week, again, it has been cut down from 0.28 lakh tonnes to 0.21 lakh tonnes, which means another 5,000 odd tonnes have been cut down.

Now, instead of strengthening the public distribution system, you are weakening it, and, further playing into the machinations of your multinational corporations and big business houses, which I mentioned earlier. That is the method how they rake in super profits. So, what we are now demanding of this Government is to restore the supply of foodgrains to what it was earlier, with immediate effect. And, you have virtually, in the name of targeting the public distribution system for the BPL, dismantled it. So, we are saying to do away with this APL, BPL for the time being, strengthen the public distribution system, and distribute all your essential commodities through that. That is the only way we can actually tackle this thing.

Finally, Sir, on this entire question of hoarding and black marketing that has been raised here earlier and we think stringent steps must be taken, I would like to point out—our hon. Member who initiated the discussion is not here—during the time of the NDA rule, there was an official order dated 15th February, 2002 which was followed up with an amendment dated 16th June, 2003 for removal of licensing requirements, stock limits and movement restrictions on specified foodstuffs. According to this order, what did the NDA Government do Sir? The order says, "Any dealer can freely buy, stock sell, transport, distribute, dispose, acquire, use or consume any quantity of wheat, paddy/rice, coarse grains, sugar, edible oils, edible oilseeds, pulses, gur, wheat, hydrogenated vegetable oil or *vanaspati* and shall not require any license or permit therefor.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.]

All the prices that we are talking of, you have given them the liberty. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: For a moment only. That was surplus. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir ...*(Interruptions)*... No, Sir. This is for everthing. I am reading out your order. ...*(Interruptions)*... Mr. Vice-Chairman, I require your protection. ...*(Interruptions)*... This is for no buffer stock. This is for nothing surplus. What they have done, I am reading out of that. What the NDA Government has done is to facilitate free trade of foodgrains. The Central order titled, 'Removal of Licence Requirement, Stock Limits and Movement Restrictions' of 2002. What does it say? "Any dealer can freely buy, stock sell, transport, distrbute, dispose, acquire, use or consume any quantity of wheat, paddy/rice ...*(Interruptions)*... of wheat, paddy/rice ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: He should not give half interpretation. ...*(Interruptions)*... He should give the complete data. At that time, how much foodgrains was available in the stocks. ...*(Interruptions)*... What is this? ...*(Interruptions)*... Kisan union came from Punjab and demanded that the farmers of Punjab ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Ahluwalia you can reply when your chance comes. ...*(Interruptions)*... There are many speakers from BJP, they can also react on this. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I repeat, I underline, what I am reading is the official order that they have passed and I am reading again that "Any dealer can freely buy, stock, sell transport, dispose ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes, this is our order. We were in surplus. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply when your turn comes. ...*(Interruptions)*... Please, Mr. Ahluwalia ...*(Interruptions)*... Don't be impatient. ...*(Interruptions)*... Please, Mr. Ahluwalia, I will give you a chance. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding Mr. Ahluwalia. Please take your seat. *(Interruptions)* No, no. *(Interruptions)* Don't argue. *(Interruptions)* Respect the Chair. *(Interruptions)* No, Ahluwaliaji, you are not permitted to speak. *(Interruptions)*. You can reply when your chance comes. Why do you dispute now?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, what was this order for? It was for any quantity—Sir, please underline the word 'any' of wheat, paddy, rice, coarse grains, sugar, edible oils, edible oilseeds, etc. *(Interruptions)* They had freed the entire movement of those commodities whose prices are rising today. They said, "No need of any licence, no need of any restrictions, you hoard as much as you want, you buy as much as you want, etc." That is the order that has been given. *(Interruptions)* Sir, that is the order which I read just now. Sir, let me proceed further. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes. जल्दी-2, your time is over. आप जल्दी खत्म करिए।

श्री सीताराम येचुरी: सर, यह बहुत गंभीर सवाल है। सर, इतना तो आप भी मानते हैं कि हमारी पार्टी disciplined है। हम कभी भी टाइम की पाबंदी से आगे नहीं गए हैं, लेकिन आज अगर मैं जाऊंगा तो आप इसकी इजाजत दे दीजिए, क्योंकि यह हमारे देश की जनता के लिए बहुत गहरी समस्या है। The point is, Sir, it is the same thing that is continuing with the UPA Government. That is where, Sir, I want to make this point very clear that if the country's future has to be secured, you will not require an alternative like a ping-pong ball between here and there, but, you will require an alternative set of policies, and that alternative set of policies is what we require right now concretely. As far as this price rise is concerned, we think these four steps must be undertaken immediately by the Government. First, strengthen the Public Distribution System by universalising it, restore the cut in foodgrains allocations to the States under the Public Distribution System and include 15 essential commodities including pulses, edible oil and sugar in the Public Distribution System. That is the first set of measures to be taken. Second, ban the futures and forward trade in 25 agricultural commodities, as proposed unanimously—I underline this word 'unanimously' — by the Parliamentary Standing Committee on Food, 'Consumer Affairs and Public Distribution, which includes all of us. Representatives of all the political parties have unanimously said that. That must be implemented. Third, the duty structure on the imported petroleum products must be restructured and rationalised, and the retail prices of petrol and diesel must be reduced. Fourth, take stringent action against hoarders of essential commodities. For this, if there is any amendment to the order that I read out just now, which exercised my hon. friend so much, that this Government wants to bring forward to strengthen the process of the Essential Commodities Act and empower the State Governments to deal with hoarding and black-marketing, we will support the Government on any changes that they would want to bring about. But, give more teeth to the State Governments and give more legislative teeth to the law so that we can check this price rise.

Sir, finally, I think, this is an issue on which we cannot afford to lose any further time. I think a lot of time has been lost. A lot of hope was there is the people of the country, when this alternative secular Government came. A lot more hope was aroused when—all of us traditionally know in our strongholds that the main political battle is between us and them—we, in the interest of the country, supported the UPA Government. We agreed to a Common Minimum Programme which contains many of these aspects which I had enumerated earlier, of greater public investment in agriculture, etc. But, now, confronted with this price rise, we think that the people expect and we want and demand of this Government, immediate, strict action to be taken. Therefore, Sir, we will not be satisfied with anything less than the four points which I have raised here today. We think, it will be a gesture of great magnanimity and, in fact, a gesture of sincerity of their duty towards the livelihood of the Indian people that they immediately ban these essential commodities from the futures market, strenghen

the Public Distribution System and tighten all the legislative authority that is required for tackling hoarding and black-marketing. Sir, the future of this Government—not only of this Government, but also the future of India—depends on how this is going to be tackled. Therefore, I want the Government, and I request our Ministers here, to address, in right earnest, these issues and give us and the august House and, through the august House, the people of the country, the assurance that these demands will be accepted by this Government. And I hope that the Government will rise to the occasion. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Mr. Yechury. Now, hon. Members, I see a big list of 18 hon. Members who want to speak and the decision is that this discussion should be concluded today. Only the reply, if it is necessary, will be the next day. Since there are 18 speakers, I make an earnest request that everybody will speak for 7 minutes, or, if it is so essential, one or two minutes more. After 7 minutes, I will ring the first bell.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, you should have more liberal attitude like what you had for the previous speaker.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The list is with me. There is no party having more that 7 minutes. That is why I fixed 7 minutes. AIADMK is having 7 minutes and I will give you all the 7 minutes. Don't worry. Now, Dr. Bimal Jalan.

DR. BIMAL JALAN (Nominated): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Earlier, I was not planning to speak, but when I heard a lot of debate, I thought, I perhaps, should intervene, and share some thoughts with you. I shall be brief and make just some few core points, critical points, which appear to me to be important to keep in mind. The first important issue is that this is a non-political issue. If you take a secret vote here, I think, all of us will agree that it is a serious problem, and the problem needs to be dealt with very urgently, irrespective of which side of the specturm you are on. I am non-political, I am non-partisan. But I cannot imagine that anybody disagrees with the importance that this House has attached to this problem. This is the first point that I would like you to bear in mind, and I plead with the hon. Members not to politicise the issue because it is too important, it is too immediate, and whatever action you take, is not going to please all. So, you have to take action, but it has to be something on which there is a political consensus, across party lines, if it helps to control inflation.

The second point is, it is extremely important that we should not be panicky. If we are panicky, if we seem to be panicky, and if we seem not be be able to tackle the problem, then you would lose. Why? Because more important than the inflation numbers for the behaviour of all the agents of the economy, is inflationary expectations. If you take panicky action, and if it is believed that this particular. action is because you have lost the ground, because you have become panicky, then inflationary expectations would certainly be fuelled, and you will not be able to cope with the problem. We have countries with 1,000 per cent inflation like Zimbabwe, you have countries with 100 per cent inflation. Nobody wants it. But they keep on flittering from here to there. This is the third point which I would like you to bear in mind in respect of importance or inflationary expectations, Many of the policies that we have talked about have been there for quite some time. What has happened to make a difference today, *vis-a-vis*, what was the position two months ago or two-and-a-half months ago? Two-and-a-half months ago we had the rate of inflation of 4 per cent. Today, we have 7.5 per cent. The inflation has nearby doubled. Why has it happend? There was a global oil problem. There was 3 months ago. There was a food problem. Yes, maybe, we had miscalculated the food problem, and we should have imported earlier. But all these problems were already

there. So, my fourth point for your consideration is that we have to deliberate on what is the issue and how can we tackle it. Here, I would make a point about what Mr. Yechury said about the liquidity or the demand side. It is that you cannot neglect the demand side. If there is a demand-supply imbalance, then, something has happened to increase demand. He mentioned a few things, that is, forward trading, so much speculation, hoarding, consumers demand, and so on, the simple point is that it inflationary expectations are there prices would rise. You can take it for granted that they will rise even though 68 per cent of your people may be poor. Simply for all the reasons you said, why has the future demand increased in certain countries? Why is the demand for commodities increasing? Why are people buying more grain than they need when 70 per cent of the people cannot afford to buy the grain that they need? It is only because they expect the prices to rise. Why is it so? Here, I would like to emphasise on the importance of demand. And 'this demand', Mr. Yechury, is 'demand by those who can afford'. And if you have a reality boom, if you have a housing boom and if you have a stock-market bubble, where is the money going? When you start pricking this particular bubble, the money has to go somewhere. The liquidity remains the same. Therefore, let us not undermine the importance of demand; don't underestimate the importance of demand, Sir. And my suggestion about what you should do is this. If you agree to the prescription, there can be many differences of views. But let us sit together and decide; cutting across party lines, all of you can sit together and decide that as the problem is important, we have to do something; we have to change inflationary expectations. Then, the only way in which you can change inflationary expectations in the short run is to move from soft measures to hard measures. And from the demand side, I would say, it is not the interest rate that matters--you can try if you want--because interest rates can affect things only over a period of time. But you have to take action to reduce the sources of demand. Every time, we are sterilising the capital flows by issuer bonds. Sterilisation does not necessaily reduce the demand. Sterilisation replaces one piece of paper with another piece of paper, and that other piece of paper can raise the demand because you can always borrow against that. What I am saying is, you have to do something for short-term capital flows. That is the liquidity issue. Mr. Yechury, you have to do something about the total availability of money in our country, just now, for purposes of buying, speculative trading. How does speculative trading work? Somebody has to pay; somebody has to borrow; somebody has to give money. You will only do this if you expect to earn profits on that particular thing. So, you have to move from soft measures to hard measures. Some to things that my friend, Mr. Yechury, has suggested are worth considering. But that will not solve the problem. Those four measures, even if you take then, will not solve the problem unless you are able to reverse inflationary expectations, unless you are able to show that you have reduced total demand *vis-a-vis* total supply. It is an elementary truth that if you multiply total supply. by prices, it would give you a higher quantum of mony than was the case four or three months ago. It is that simple. You have to take an effective set of measures, and move from soft measures to hardmeasures. These measures must attack the demand side strongly, and they have to be effective in the short-run. Interest rates are not effective in the short run; I will not go into the specifics of it because Finance Minister of India knows all that. But if he decides to do something on the demand side, if he decides to do something for increasing the supply -- it is not that nothing is being done--then, I think, we can tackle the problem. But approach has to be a non-political one. There has to be a consensus on that. It has to be non-panicky and it has to be straight, which people expect that yes, you are reversing inflationary expectations and that you will succeed. if they believe that you will succeed, then you will succeed; if they believe that you are going to fail, you will fail. Thank you very much, Sir.

श्री शरद यादव (बिहार): मान्यवर, जो बहस चली है, उसमें बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। आजकल सारी दुनिया एक है। चारों तरफ का बाजार, सभ्यता, तहज़ीब सब गड्डमगड्ड है। उसे रोक नहीं सकते हैं। मैं अपनी बात कुछ निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अभी सीताराम येचुरी जी बोल रहे थे। उन्होने एक सवाल पर ठीक हाथ रखा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि हिंदुस्तान को रहना है, आगे ठीक और दुरूस्त रखना है तो महंगाई को रोकना होगा। यह एक पार्टी से नहीं होगा। इस देश का जो फूड मैनेजमेंट हैं, चाहे यूनाइटेट फ्रंट गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस या एन॰डी॰ए॰ की सरकार रही हो, शांता कुमार जी यहां हैं, जब से यह सरकार आई है, जो फूड सिक्योरिटी स्टेब्लाइज हो गई थी, स्थिर हो गई थी, वह पूरी तरह से ऐसी जगह पहुंचा दी गई है, खड़ी कर दी गई कि अस्थिरता है। जब हमारी सरकार गई थी, सीताराम येचुरी जी यहां नहीं हैं, वे आएंगे तो उनके सामने बात होगी। आपको बैठना चाहिए, हमने आपको गौर से सुना ...(व्यवधान)... आप बहुत हलचल वाले आदमी हैं। जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनके बीच में ज्यादा रहते हैं। मैं निवेदन करूं कि सीताराम येचुरी जी ने जो बात रखी है, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां शांता कुमार जी बैठे हैं, 2002 में 64.5 मिलियन टन फूड प्रोक्योरमेंट हुआ था। जब हम छोड़ कर गए, तो 220 लाख टन छोड़ कर गए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एनडीए सरकार की उपलब्धि हैं। यह इस देश की उपलब्धि है, जिसने यह नीति बनाई कि एफसीआई जैसी संस्था को create किया। मैं यह भी मानता हूं कि एफसीआई में करप्शन का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उसका करप्शन होता है दो करोड़ का, तीन करोड़ का पांच करोड़ का। इस देश में जब डिफेंस डील होती है, तो यह अरबों, खरबों में होता है। लेकिन इसको लोग बहुत गाली देते हैं। मेरे एक मित्र बहुत गाली दे रहे थे। लेकिन जो छोटा-छोटा पीडीएस सिस्टम चलाता है, उस दुकानदार को बहुत गाली दी जाती है इसी तरह एफसीआई भी एक ऐसा हथियार बनाया, जिसने भी बनाया, इस देश ने बनाया, इस देश की सब सरकारों ने इसको बनाया। जो बाजार है, उस बाजार को रोक नहीं सकते, ठीक बात है, दुरुस्त बात है। दुनिया में कट कर नहीं रह सकते, segregate होकर नहीं रह सकते, लेकिन यदि इस देश को बचना है, ठहरना है, आगे जाना है, तो इस देश को बाजार से, देश की खेती को और फूड सिक्योरिटी को आपको बचाना पड़ेगा, जिस पर यहां लोगों ने बहस चलाई, उसको मैं segregate करता हूं, separate करता हूं कि जो यहां की फूड सिक्योरिटी है, जिसको हमारे पुरखों ने stabilise किया है, कितने ही तरह के भ्रष्टाचार के चलते, तो हमारा जो फूड मैनेजमेंट है, वह stabilise हो गया था। सात सूबों में अकाल पड़ा था। अटल जी को या हमको श्रेय मत दो, यह परम्परा थी कि इस देश में जो फूड मैनेजमेंट, फूड प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम, जो तरीका बना हुआ है, उसके चलते सात सूबों में सूखा पड़ा था, राजस्थान तो पूरी तरह चौपट था, 100 लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त में मैंने बँटवाया था। यह एनडीए की सरकार में सात सूबों में बँटा था, लेकिन महंगाई का कोई असर नहीं हुआ था। उसका कारण यह नहीं था कि हमारी economic policy बहुत bright थी। हमको जो चीज परम्परागत मिली थी, उसमें ताकत थी, strength थी, उसको हमने disturb नहीं किया। उसको कायम रखा। जो दाम थे, वे स्थिर क्यों रहते थे। Food & Civil Supplies and Consumer Affairs, दोनों को साथ रखा हुआ है। महंगाई के लिए प्रधान मंत्री के मंत्रालय में एक सेल है और उस सेल को feed करने वाला कोई है, तो Consumer Affairs और Food Ministry है। वह लगातार बताती है कि कितनी कमी है। तीन चीजों के मामले में हमारे पास शक्ति थी, ताकत थी - शक्कर में गेहूँ में और चावल में। जब से आप आए हैं, अब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री हैं, अभी आफत में पड़ गए हैं। लेकिन आफत इनकी अकेले नहीं, पूरी सरकार ने मिल कर लाई है। अभी यहां शरद पवार जी नहीं हैं। मैं मानता हूं कि वे होते, तो मैं जरूर बोलता। मैं बाहर उनके बारे में बोल चुका हूं। लेकिन आपने ऐसा इंतजाम किया है कि हिन्दुस्तान की खेती को आपने बाजार के हाथ सौंप दिया। मेरी चुनौती है कि जहां बाजार गया है, वहीं आत्महत्या हो रही है। यह जो आपने एक्सपर्ट बुलाया है, जो हमसे ज्यादा ठीक अंग्रेजी बोलते हैं, जिसके बारे में जनेश्वर मिश्र जी बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा, "मैं बोलू हूं आखिन देखी, तू बोले है पोथी देखी"।

मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोग जमीन को जानते हैं, उपसभाध्यक्ष जी, महंगाई के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 23 बार बाजार में गेहूं, चावल और शक्कर को रिलीज़ किया। जिसे सप्लाई और डिमांड कहते हैं, उसे मैंने 23 बार रिलीज़ किया और रिलीज़ इसलिए किया कि हमारे पास फूड स्टॉक था। मेरे पास शक्कर वाले लोग आए और बोले कि बाज़ार खोल दो।

माननीय सदस्य: श्री शरद पवार जी भी आ गए।

श्री शरद यादव: शरद पवार जी भी आ गए हैं। मेरे पास सब लोग आए कि बाजार खोल दो, लेकिन मैंने उसे नहीं खोला। वह तो हमारे संस्कार भी हैं कि सरकार के हाथ में ताकत होनी चाहिए, तो उस समय भारत सरकार के हाथ में तीन चीज़ें थीं। मैं मानता हूँ कि किसान के बारे में हमारी जो चिंता है, वह मोनापली प्रोक्योरमेंट की नहीं है, जो एफसीआई का था। उसमें भी एक तथ्य है, एक बात है कि जब प्राइवेट ट्रेड के लोग उसे खरीदते हैं, उसी से पिछली बार भी उसके दाम बढ़े थे। इस बात को मैं भी मानता हूं। जब ओपन मार्किट किया है, खुला बाजार किया है तो भारत सरकार को व्यापार में, मार्किट में ठीक से इंटरवीन करना चाहिए। प्रोक्योरमैंट में इंटरवीन करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर मेरा निवेदन है कि यह जो सारी समस्याएं हैं, उनमें से बहुत सी समस्याएं तो आनी ही थीं। सीताराम येचुरी जी ने कहा कि पेट्रोल और ऑयल के दाम बढ़े हैं, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं। येचुरी जी यह कह रहे हैं कि उसके टैक्सेशन को थोड़ा घटा दिया जाए, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऑयल नहीं है और आज नहीं तो कल नहीं हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर नौएडा चले जाइए या गुड़गांव चले जाइए, वहां पर 80 फीसदी गाड़ियों में सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ होता है। अब हमारे फाइनांस मिनिस्टर ने चार पहिए की गाड़ी के ऊपर बड़ी सहूलियतें दे दी हैं। यह जो गाड़ियां आपने बढ़ाई हैं, इसके लिए हमको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसमें जो डीज़ल डलता है, उसके कारण ही सारे सामान की ढुलाई होती है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, इसलिए उसे ठीक करो। इस देश में एक तरह से यह जो बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सोचता हूं कि उस पर भी एक बहस होनी चाहिए, लेकिन इस समय मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अभी वह सब कहने का समय भी नहीं है। लेकिन मेरी व्यावहारिक बुद्धि यह कहती है कि इस देश के पास पेट्रोल या ऑयल नहीं है, इसलिए इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए और उसके लिए हमें पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को मजबूत करना चाहिए। हमें डीज़ल के साथ अन्य जो भी चीजें महंगाई बढ़ा रही हैं, उन सबके बारे में सोचना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि जो टैक्सेशन है, उसे कैसे ठीक किया जाए। मैं सीताराम येचुरी जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को पैसा भी चाहिए। हम मांग तो बहुत करें और कहें कि ऐसी गाय लाओ, जो चारा कम खाए, लेकिन गोबर और दूध ज्यादा दे, ऐसा नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)... मैं यह अरबपतियों को कह रहा हूं, लेकिन वे कभी नहीं करेंगे ...(व्यवधान)...मैं भी वही कह रहा हूं, लैकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको गाय से दूध और खाद लेना है तो उसे चारा भी देना पड़ेगा, लेकिन आपने फूड सेक्योरिटी और फूड मैनेजमेंट को बाजार के जिम्मे सौंप दिया, आपने हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर को बाजार के हाथों में सौंप दिया।

क्या आप जानते हैं कि SEZ के मामले में क्या-क्या तमाशा हो रहा है? दिल्ली के आस-पास की जमीन, जहां सबसे ज्यादा प्रोक्योरमैंट होता है, पंजाब और हरियाणा से 55% धान प्रोक्यौर होती है, 82% गेहूं प्रोक्योर होता है, लेकिन वहां की जो जमीन है, उसे आप SEZ में बांट रहे हैं। इस तरह तो देश कल भूखों मरेगा। हमारे नेताओं के हाथों में यह जो लोकतंत्र सौंपा गया है, वह बचेगा नहीं। लेकिन हम लोग निश्चिंत हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप नेताओं के चेहरों को देखिए, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर लिया है। वे सभी बिल्कुल निश्चिंत हैं, लेकिन बाकी पूरा देश आफत में है। जो 70 फीसदी आदमी हैं, उनका सबसे मुख्य भोजन है, चटनी और रोटी, दाल भी नहीं। हां, हमारे देश में एक रिवाज है कि जब हमारे जमाने में लोग आपस में किसी ठेले में, बारात में, गांव में या देहात में मिलते थे, तो पूछते थे कि भैया क्या हाल-चाल है, वह बोलता था कि दाल-रोटी चल रही है, नमक रोटी चल रही है। लेकिन अब तो आपने नमक में भी आग लगा दी है और रोटी में भी आग लगा दी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप रोटी पैदा करने वाले का खयाल नहीं रखेंगे तो अकेले रोटी का खयाल भी आप नहीं रख सकते हैं। इस देश का जो मध्य-वर्ग है, वह सिर्फ सस्ती रोटी चाहता है। सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो दर्द उसके पेट में होता है, अन्य किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो दर्द उसी को होता है। आज भी आनाज के दाम ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, जिसकी इतनी चर्चा की जा रही है। अनाज के दाम में गड़बड़ ही इसलिए हुई है कि आपने फूड मैनेजमेंट को नहीं किया है। हमने जब सरकार छोड़ी थी, तब आपके लिए 220 लाख टन प्रोक्योरमैंट छोड़ा था। आज आपके पास 75 लाख टन अनाज बचा है। इसके चलते

सबों ने यह बात ठीक ही उठाई थी कि आपने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का अनाज कम कर दिया। जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसके लिए एक मीटिंग बुलाकर आपने उसे ठीक नहीं किया। उस पर आपने जोर नहीं दिया। यह एक गरीब देश है। यदि गांव में, तहसील में अनाज जाता रहता, तो अगर वह काला बाजार में भी जाता, तो बाजार में तो रहता। आप उसकी दुकान को ठीक करिए। दक्षिण भारत में बहुत-से सूबों में वह अच्छा है, उत्तर भारत में भी इसे ठीक करिए। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इस सदन से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की जो लोकशाही है, आजादी है, उसको यदि हमने जो हमारी फूड सेक्योरिटी है, हमारा जो भोजन है--हिन्दुस्तान के आदमी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अधिकांश बहुसंख्यक लोग संतोषी लोग हैं। उनको सिर्फ पेट के लिए खाने को चाहिए। वे दाल-रोटी, चटनी-रोटी खाकर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौलत बनाते हैं। उनके लिए हमने संकट खड़ा कर दिया। वह संकट हमने अपने हाथ से खड़ा किया है, सरकार ने खड़ा किया है ....(समय की घंटी).....सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि यह कानून हमने बनाया है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): शरद जी, आप खत्म कीजिए ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। वे सामान के नाम गिना रहे थे। साहब, जो न्यूक्लियर डील है, उस पर तो आपने सरकार के घुटने टिका दिए। हमने भी विरोध किया है, लेकिन आपने चार साल में एक बार तबियत से विरोध किया है। याद रखिए, आपने एक साल में किया, तो उसमें यह सरकार रुकी कि नहीं रुकी। उसमें हम लोग भी डटे रहे हैं। आपका नाम ज्यादा है। लेकिन आप एक बार ही ठीक से डटे हैं। Commodities exchange को बन्द कराने के लिए हमने इस सदन में कहा था। हमसे Commodities exchange बनवा लिया। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारा ऑफिसर था, उसने हमारी बुद्धि को खराब किया कि किसानों को इससे बड़ा लाभ होगा। मैंने कहा कि हमको हटा के बाहर कर दिया, हमको निकाल दिया, आपको काहे के लिए लाए हैं? इसमें आपक सदस्य हैं, लायें। आप यह कह रहे हैं कि हम यह कानून लाए थे, हमारे यहां सरप्लस था। ... (व्यवधान)... आप सुन लीजिए। हम आपके कहते समय तो नहीं बोले थे। हम मान रहे हैं, हमारी राय यह है कि हमारे जमाने में सब चीजें, दुरुस्त थीं, सरप्लस था, हमने खोला था, इसलिए। हमने खोला था, हमने ओपन किया था। अब सरकार आपकी है। सरकार तो आपके कंधों पर है। अब Commodities exchange तथा इन सारे सामानों के बारे में, खरीदना, बेचना, ले जाना, जो हमने किया था, तो आपको राज में किसलिए बिठाना है, ... (समय की घंटी)... राज में इसलिए बिठाना है-- हम कह रहे हैं, आप न्यूक्लियर डील के बारे में आपने क्या कहा? आप तो अड़ गए। आपने तो उनके घुटने टिका दिए। इस पर आप नहीं अड़े ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): शरद जी, आप समाप्त कीजिए ...(व्यवधान)... आप समाप्त कीजिए... (व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: अगर आप लौट आते हैं, तो क्या आप इसे वापस लेंगे? ...(व्यवधान)... आप वापस आएंगे तो इसे विद्ड्रॉ करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: किस लिए?...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: आपने कहा कि लौटाएंगे...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: जरूर, जरूर ...(व्यवधान)... मैं सरकार में रहूंगा, तो वह जरूर वापस होगा ... (व्यवधान)... Commodities exchange ...(व्यवधान)... जरूर वापस होगा। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: तब मंत्री तो आप ही थे...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, No ...*(Interruptions)* No time for this ...*(Interruptions)*

श्री शरद यादव: मैं था, तो मैंने कहा ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... टाइम का सवाल है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): शरद जी, आप समाप्त कीजिए ...(**व्यवधान**)... आप समाप्त कीजिए ...(**व्यवधान**)... 18 लोग बोलने वाले हैं। मैं क्या करूं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, ...(**व्यवधान**)...यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों के पेट की बात हो रही है ...(**व्यवधान**)...

□□□ □□□□□□□□□□□□□ (□□□□. □.□. □□□□□□): □□; □□. □□□□□□□□□, □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□ □□ □□□ □□□□□□ वित 14 minutes...*(Interruptions)* यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इन्हें ज्यादा टाइम दिया, डबल टाइम दिया। ...(**व्यवधान**)... I have given him double the time. I know he is a senior leader. I respect him. Why do you create problems? I will decide...

श्री शरद यादव: सर, आप ठीक कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि सीताराम येचुरी जी ने ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): आपने 14 मिनट बोला है ...(**व्यवधान**)... It is my duty to remind him to conclude. इन्होंने 14 मिनट बोला है ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: सर, मेरा सरकार से कहना है कि बाजार में यह आँधी और तूफान चलेगा और बढ़ेगा। आप किसी तरह से किसान को कैसे मजबूत कर सकते हैं? फूड सिक्योरिटी का जो पहले से मैनेजमेंट है, एफसीआई, उसको आप बिल्कुल दुरुस्त करिए और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको साफ करिए। हमारा जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, यदि आप उसे प्राइवेट लोगों को देते हैं, तो उस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा सीताराम येचुरी जी ने कहा, उसके चलते बाजार में साइकी ही बिगड़ी है और इसलिए यह क्राइसेस है। उत्पादन कम नहीं हुआ, उत्पादन तो पिछले साल बराबर हुआ। इस बार आपने यह ठीक काम किया है, पहली बार मैंने आपका फोटो देखा कि आप हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठे हैं। चार साल में आपके प्रति मेरे मन में आपके फोटो से तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, जब मैंने देखा कि आप पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि आप खरीददारी के मामले में, प्रोक्योरमेंट के मामले में गंभीर हैं। निश्चित तौर पर आप खेत को, खलिहान को, एग्रीकल्चर को और जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, इन सारी चीजों को इस बाजार से बंद करें, मैं येचुरी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूं। ...(**व्यवधान**)... इसमें आप जरा ठीक से जोर लगाइए ताकि इस बार खरीददारी ठीक हो। आप इसको भी देखिए कि किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए...(**व्यवधान**)... इसमें सब्जी वाले जो दाम हैं, जो आपके गेहूं वाले दाम हैं, जो चावल वाले दाम हैं, इन सारी चीजों में किसान के साथ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र, लोकशाही को बचाना है। हिंदुस्तान में जो भोजन का इंतजाम है, वह इंतजाम तब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक आप बाजार को इससे अलग न करें। अगर इसमें बाजार जाएगा, तो इस देश में तबाही होगी, इसलिए बाजार को रोकने का काम करिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Sharadji. There is constraint of time; otherwise, I would have liked to hear you more. Now, Shri D. Raja.

DR. V. MAITREYAN: Sir....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is the problem. I looked to the right. I should have looked to the left.

DR. V. MAITREYAN: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. Today, the country has a Government but no governance. The UPA Government is ruling the country but it is not governing it. We saw glimpses of non-governance in the morning when during Question Hour a reply was given that there is no anti-migrants drive in spite of the fact that 336 cases were registered, more than 1,500 people were arrested and more than 5000 people had been taken into preventive custody. The Finance Minister spoke eloquently about inflation, growth,

GDP and other things. Now, he says that we have to definitely contain inflation even if it means sacrificing growth. I saw the Commerce Minister speaking on television yesterday. He was saying, "Where is inflation? There is no inflation". And I heard another Minister from Maharashtra, the 'flying Minister'—because he flies he does not feel the ground realities—saying that the food habits have changed and that is why there is inflation and price rise; people in the South have started eating more rotis and people in the North have started eating more rice and that is why this problem. Then, we have this lawyer Minister saying that he has no magic wand. Not only that, he went on to comment about the now friend-turned-foe, the Left parties, that they have not given any suggestions to the Government, that they are only criticising and not giving any suggestions to the Government. Sir, magic wand or no magic wand, Government has to do something and bring downs the prices. The common man wants prices to be brought down. We are not bothered about how you do it. आम से हमको मतलब है, गुठली से क्या लेना? I feel definitely, the hundred rupee note in my pocket may not hold the same worth tomorrow as it holds today. Of course, in terms of pure economics, tomorrow, for that hundred-rupee note, I may get two 50 rupee notes or a hundred one rupee coins. But I may not get the food grains in such a way that this remains the same hundred rupee even tomorrow. The UPA Government has lost its direction. It is pursuing unimaginative initiatives. It is pushing programmes with no vision. It is drifting and its counting its balance tenure. Of course, the Left Parties can definitely help get this UPA Government come out of this problem. But, despite their opposition to the Nuclear Deal, despite their opposition to the rising prices, somehow, for reasons best known to the Left Parties, they are not giving a helping hand to the UPA Government. The UPA Government has miserably failed to contain the skyrocketing prices of essential commodities. In fact, the prices of vegetables, fruits, pulses and edible oils have increased by more than 100 per cent in the last three to four years. The Government has definitely initiated, in the last one week, various measures to curb the demand, and push and augment the supply in the market, but that is not working. The prices are continuing to rise, whether it is essential commodities or steel or cement. What this Government, or, probably, in particular, the people in-charge of the economic affairs are doing is to go for short term solutions, populist solutions for problems which they meticulously cultivated and created over the last two to three years. The UPA Government's misplaced priorities in the economic management ever since it assumed office in 2004, have ruined the nation, and the comulative impact of these misplaced priorities is what the country is facing now. I understand that according to some sections in the Ruling Party, the inflation will come down on its own to five per cent by June. This non-interventionist policy, hoping that things will set themselves right, is highly sceptical path which the Government should not follow. That will endanger the food security of the downtrodden and the BPL families. I can only warn the Government that such a laidback approach in policy making will definitely not work.

Secondly, the remedial measures adopted by the Government are not enough. I agree with my Left party colleagues, particularly Mr. D. Raja that the decision of the Government. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He did not speak.

DR. V. MAITREYAN: No, no; I endorse his view that the decision to ban the export of non-Basmati...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): This is outside agreement.

4.00 P.M.

DR. V. MAITREYAN: The decision of the Government to ban the export of non-Basmati rice and cut the import duties on edible oils is too little, too late. It is unfortunate that the Government has allowed the situation to go out of hand. No one can deny; no one has any doubt that the overall policy thrust of the UPA Government has to be blamed for the present crisis. The economic policies of the UPA Government are supposed to be framed and implemented by the hon. Prime Minister; the hon. Union Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission. All the three are supposed to be financial wizards. But, then, what happened? Where did the mistake occur? The Government should have anticipated the rise in prices, at least, three months earlier. I wonder why they could not foresee this situation and planned in such a way to meet the crisis. The principal reason for this crisis in the food market is the opening up of the food sector, in particular the retail sector to the global economy and the big business houses. Is the UPA Government blind to the fact that the corporate houses and multinationals are stocking huge quantities of food commodities and they are virtually creating a monopoly?

Sir, the Central Government has systematically ruined the Public Distribution System. There is a total mismanagement of the PDS and this has led to the shortage of food commodities and rise in the prices of many essential commodities. What prompted this Government to cut the allocation of the rice to various States? The Targeted Public Distribution System was introduced in June, 1997. Most of the economists of the country are identical in their views that the TPDS was and is a complete disaster. The extent of increase in corruption because of the introduction of the TPDS has assumed enormous proportions with each passing year. The Government should immediately put in place corrective administrative measures to universalise PDS and improve the delivery system. The cuts imposed on the foodgrains allocations to various States should be restored immediately. The hoarders should be identified; their godowns raided, the articles confiscated and stringent punishment given. The Government also should immediately ban the future trading of 25 agricultural items. There is a news report that the five-member Committee appointed by the Finance Minister, headed by Prof. Abhijit Sen to examine the impact of future trading on the wholesale and retail prices of agricultural commodities has found a strong correlation between future trading and the prices. Allegedly, the Committee has stated that such trading introduces instability and further marginalisation of the small farmers. I also understand that one of the Members, Prof. Kabra has contested the claim that farmers can get protection against price movements through future markets, as they are considered instruments of price-risk management. The seed research operations in the country have fallen, and the multinational companies have taken control of this. So, the seed production in the country has also been affected, seriously. Is the Government really blind to the situation or is it seeming ignorance? The FICCI has suggested a three-pronged approach to curb inflation. My colleague, Sitaram, enumerated his four-pronged strategy. According to the FICCI, the three steps which they have suggested, meeting the domestic shortfall in primary products through imports and making them available at subsidised rates for domestic consumption; putting in place a concerted effort and a programme for agricultural reforms; focus on improving the farm productivity, improving the supply of agricultural products, removing the transport and other logistical constraints so that the food can be reached to various places; and, thirdly, lowering the interest rates in order to stimulate manufacturing sector. What will be the Government's response to this? We are waiting to see.

To sum up, the Government has to, definitely, take immediate steps to broad-base the PDS system and the delivery of the foodgrains to it; ban future trading of essential commodities

in the market; evolve, formulate and implement long-term production plans to improve foodgrains production. Let us admit that the Government has failed miserably in handling the fiscal situation in the country. If immediate and drastic corrective steps are not put in place to control the spiralling prices, I am afraid, the Government will have to face the ire of the very *aam admi*, riding on whose shoulders this Government assumed power.

Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you for the opportunity, Sir. The House is discussing a very important issue. The situation that prevails in the country is very grim, very alarming. The Government has to intervene in the situation to contain inflation, to control prices. In fact, the Left parties have been warning the Government. Despite giving very reasonable suggestions, the Left parties have been mobilising the people to come on streets, express their anger against the disastrous policies pursued by the Government which resulted in such a situation. It is not that the Left parties have not warned the Government. We have warned the Government about the impending catastrophe that we are witnessing today.

The UPA Government, in fact, has been lacking a long-term strategy and it has failed to take short-term measures also. In fact, my great friend, Minister Kapil, is sitting here. Everybody referred to his statement, "UPA Government does not have a magic wand". We do not believe in the magic wand and you too are not going to get a magic wand. But, you have the power and you could have intervened in the situation. You failed to intervene in the situation. That is our point.

As far as long-term strategy is concerned, since our Agriculture Minister is also sitting here, I must point out that the Government should have taken enough steps to increase the productivity in agriculture, to increase the production of foodgrains and pulses in our own country. Sir, even when you were speaking from the treasury benches, you referred to China also. As a country, we should draw certain lessons from the Chinese experience. China had a strategy. China went in for enhancement of productivity in small farms. China had a strategy for development of non-farming sector, particularly the township enterprises thereby China could draw more people from farming sector to non-farming sector. I think, the Government here did not have such a long-term strategy.

Coming to short-term measures, the Government could have strengthened the Public Distribution System which is a neglected one now. Here, we have been telling the Government, categorisation of the APL and BPL people is a big source of confusion and corruption also. This Public Distribution System needs to be universalised. And thereby the Government could have ensured the supply of essential commodities, particularly the food items, at very reasonable and subsidised prices to the common people. Now the prices of all essnetial commodities have gone up manifold. The prices of rice, wheat, edible oil, pulses, lifesaving drugs, steel, cement, everything have gone up mainfold and the Government pleads before the market forces. It is very sad to see that the UPA Government pleads before the market forces for its own failure, for its lack of long-term strategy and short-term measures. In fact, our Prime Minister himself is an economist, our Finance Minister is considered to be a person who has expertise in economic matters and the Deputy Chairperson of the Planning Commission is also an economist. But in spite of having all these economists, the Government has failed to control prices. This is where the Left parties are critical of this Government. We have been supporting this Government not only to prevent the communal forces to take advantage but we also have been supporting the Government to take certain pro-people

measures and particularly on the basis of the National Common Minimum Programme Since the Agriculture Minister is present here, I would like to pose a concrete issue. The National Common Minimum Programme speaks about doubling the public investment in agriculture but if you study the Budget figures, I do not think there is any substantial increase in the allocation for agriculture and the *status quo* remains. If the *status quo* continues, then where is the scope for a change and where is the scope for increasing the productivity in agriculture and increasing the production of our own pulses. Some newspapers have reported—I do not know,—if that is wrong I am happy—that you are going for biofuel. If you are going for biofuel it is a kind of diversion of land. Not only that, it is a method of land grabbing also. The experience of several other countries proved to be disastrous. The Government of India should not contemplate on such lines. That is one thing. The other thing is the short-term measures. I was talking about the Public Distribution System. Sir, when you were speaking from the other side, you mentioned that the State Governments have the responsibility. Yes, I agree that the State Governments have the responsibility but you cannot pass on the blame to the State Governments. It is not enough to blame it on the State Governments. The Centre has cut down the supply and quantum of foodgrains to States like Kerala and West Bengal and it is given to some other States. How can it be justified? So, the Public Distribution System needs to be strengthened at this point of time. It needs to be streamlined and the Government will have to ensure the supply of essential commodities at the affordable prices irrespective of the APL and BPL divisions. Then everybody has referred to the banning of forward trade. The forward trade has become a major source of speculation and increase in prices. The Government will have to actively consider banning forward trade or future trade or online trade particularly in the essential commodities. I would also like to request the Government for banning forward trade in iron and steel also. The Government has taken certain steps of late. That is why I said it is too late and too little. The Government could have done a lot more if the Government had assessed the situation properly. Here we also suggest that the Government should go for very stern measures against hoarding and black-marketing. Here I think there is a need to strengthen the Essential Commodities Act. There, there is a contention between the BJP-led NDA and us also because we think when BJP-led NDA Government was there, they weakened the Essential Commodities Act by issuing a circular, thereby encouraging private traders. Now, how can the Government nullify those instructions given through such a Central circular? UPA Government should take very concrete steps to strengthen the Essential Commodities Act and Government will have to go in for procurement of food grains directly from farmers, paying them the remunerative price and giving them minimum support price for paddy and wheat. Then, there is one issue which everybody mentioned. How can the Government give support price even for paddy? Agricultural Price Commission fixes one price and Government given Rs. 50 more than what the Price Commission has done and this is in no way justifying the position and agriculture should become remunerative in the given situation. On the last day of the last Session of Parliament, the agricultural policy was presented and there was no proper discussion. I do not know how agricultural policy can be put into practice, translated into relity because India needs a comprehensive agricultural policy, whereby agriculture should be made remunerative and profitable and farmers must have proper income. It is no use talking about yields only. What about the income of farming communities? Now the people are migrating from villages. Villages look as deserted villages. Everyone knows it. People are getting pauperised. The farming community is getting pauperised. The agricultural workers are getting pauperised. The vulnerable sections, people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are disadvantaged are getting pauperised. I don't go by the same statistics of

Rs. 20 per day or 78 per cent of our population are living below the poverty line. The point here is, vast majority of our people are semi-starved, starved. Whether one accepts it or not, that is the reality. That is the level of income of our people. How are we going to charge this situation? Now, with all this price rise, inflation, the common people are finding it difficult to survive.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI D. RAJA: I am concluding. It is a question of saving our people. It is a question of paving a road for building a new India. There, we will have to protect the interests of our people. We are passing through a ciritical period in which we have food crises. There may not be a food riot here. That is not taking place right now. I can't guarantee that tomorrow there may not be a food riot here in India. I can happen as it happens in other countries. Are we going to face such a situation? That is why the time has come now. UPA Government will have to make a strong introspection. There is a need to amend the policies. It is all the result of your neo-liberal economic policies. Whether you agree now after four years being in Government or not, it is a fact. It is the result of the neo-liberal economic policies which have brought the country to this stage where you have no food security. You have a food crisis and people are finding it hard to live in this country. That is why the Left Parties demand that you will have to go in for post correction of your policies. If you continue the same policies, you cannot change the situation and you will have to face the people. We have been supporting the Government. Don't try to question the position of the Left. Yes, Left has been supporting the Government, not for anything else. We are supporting the Government. This Government will perform on the basis of the Common Minimum Programme and try to pursue certain policies which are in the interest of the people. If you continue with the same neo-liberal economic policies, our position will become untenable. That is the point that the UPA Government should understand. The support of the Left cannot be taken for gra·.ted. The position of the Left and the support of the Left cannot be taken for granted. As a party, as a responsible force in the country, we urge upon the UPA Government to go in for course correction in your policies. You take immediate, urgent and short-term measures which have been listed by my previous speakers also. You strengthen the Public Distribution System, ban the forward trade, strengthen the Essential Commodities Act and go in for de-hoarding measures. Unless you take such short-tem measures, the situation cannot be changed. If you fail to address our concerns, then, we have to take our future course of action. Thank you.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Thank you. Mr. Vice-Chairman, Sir.

I rise only to make a few points.

First, the inflation problem today is too serious a problem to get into political bickering. We have to solve the problem. We don't have to talk about what the Government should have done earlier. Quite a few mistakes have been made and this or that should not have been done. All these questions are not so important now. They can be taken care of later. But, today, the problem is that something has to be done for the very simple reason—the hon. Finance Minister is not here—that the most difficult problem of inflation is that if this inflation is continued for some time at a high rate, it creates an inflationary expectation. It means, inflation will generate further inflation in which situation people lose confidence in their purchasing power or on the currency and they move away from rupee, domestic investors go aborad, foreign investors go back and then we are going to face an unprecedented crisis.

I want to put this point very clearly, because all of us are going on bickering about all sorts of things. But, a crisis situation, as it happened in East Asia or in Argentina or in some of the Lain American countries during this kind of inflationary situation, has arisen. If it happens to India, it would be absolutely disastrous, because, if I may also refer to a particular figure that we are talking about that 836 million people live below Rs. 20 per day and if they get up and rise, this country is going to completely disintegrate. I am making this point about the cirsis situation, as both the hon. Finance Minister and the hon. Minister of Food and Agriculture, who is sitting here, have to take the responsibility of doing something to prevent that. What the hon. Finance Minister should do is what Mr. Bimal Jalan has pointed out. There has to be a demand management. Whatever you do, if the demand is squeezed, it will have an effect on the general prices. It is not a question of relative prices but of general prices so the demand has to be cut. But, the demand cutting means, it will affect your rate of growth. If your rate of growth falls, it would generate the expectation it would fall further in the future then, again, the crisis situation that I am talking about will precipitate. So, the whole problem of monetary management is to fine tune this demand management. It is difficult problem. But, we know how to do it. I expect the hon. Finance Minister to come forward with appropriate measures. I must say that the Governor of RBI is particularly praiseworthy for his efforts, because he is trying his best to do this kind of demand management. But the problem with that kind of demand management through interest rate is, the rupee will appreciate at a particular point of time with more foreign exchange coming. You have to be ready to face this kind of a sitaution. If you want to intervene then you again raise liquidity. So, in that situation, rupee will appreciate. It will affect the exports. As a result, as Mr. Sitaram Yechury has said, many exporters would actually suffer. This is a particular problem we have to face.

The second problem, Mr. Vice-Chairman, Sir, I must mention is, whatever little measures—little price change, little import duty change, little export ban, etc.—we tried to do will not work. This will not work because of the nature of this inflation, basically our prices are being determined and governed by international prices. This is the effect of globalisation. We cannot get away from globalisation. It is a fact Particularly, when the world prices are higher than the domestic prices, there will be speculation, there will be hoarding, and there will be expectations that the prices will go up further. In this kind of a situation, it will not be possible to have much effect of this kind of tinkering. But, there is at least one effect of this tinkering. That effect is on inflationary expectation. As Mr. Jalan pointed out, in this situation there will be inflationary expectation, that is, you expect more inflation to come. That is a psychological case for which we must take immediate action. Therefore, I would suggest—our Agriculture Minister is here—that some steps should be taken immediately. It is not a question of State Governments or the Central Government. I beg to differ from you Mr. Vice-Chairman when you made this point. The primary responsibility is on the Central Government. The State Governments will act accordingly. But the Central Government must take immediate action. One of the first actions is, to have an ordinance banning for six months all forward trading. I do not say, forward trade banning will have immediately much of an effect on actual prices. But, it will have an effect on inflationary expectation.

The second point is very important. You can have an ordinance—even the Central Government can have it—against all kinds of hoarding and all kinds of stocking of specific limits of different essential products for a period of time. I do not agree that this will have a major effect. In fact, if we are growing, in terms of GDP we should get away from this kind of control. But, at a particular point of crisis, this message must go that the Government is now determined that no stocking and no hoarding will be done. This can be done only by a Central Government ordinance.

The third point is expansion of the Public Distribution System. This is the Agricultural and Food Minister's area. It is not only that the Public Distribution System should not be restrained. Examples were given by Shri Sitaram Yechury. It is a fact. In fact, again and again, these points have been made that APL releases have been cut down and the total amount has been cut. We cannot do that at this time. We have to have a substantial increase of releases to the poor people. Therefore, the PDS system must expand. But, in order to expand the Public Distribution System, we cannot use all the existing stocks, there are limits. I am not quite sure, but, once the Rabi crop of the Boro crop comes, there may be further procurement. But if there are no stocks available, we have to import.

Now, I must mention one thing. The Finance Minister comes and says, again and again, that where we can import from; there is nothing available. This is, unfortunately, not economics. Any tradable item is available in the world at a price. When you say that it is not available, it means that it is not available at a cheap price. You have to pay a high price. And, that, I am afraid, is the price this Government will have to pay for making mistakes or blundering on its imports earlier. In 2006, when our buffer stocks were coming down, there was a big difference between the norms in the buffer stock and the actual buffer stock. We should have gone in for imports. We did go in for imports for a limited amount. At that time, the cost was only $ 170. It went up to $ 214 in the middle of the year. Then, we started importing. When we finally imported, it is now much more than $ 300. I am not saying that imports should not have been done. Mistakes were made. There are some points on which we can, probably, give some explanations, like, why the contracts were turned down etc. But whatever the causes, this particular increase in cost is the result of the Government policy. And you cannot issue foodgrains at that import cost. You have to subside that. And that subsidy has to be borne by the Government. What I am trying to say, Sir, is that this is the cost that the Government will have to pay for taking a belated position and for taking a position which they should have taken 2-3 years back when already the buffer stock figures gave us a signal that there is going to be a major problem. You have to do that. We should have a substantial expansion of PDS. I agree with Shri Sitaram Yechury that this PDS system should now move to other essential commodities which may not be subsidised. You ask NAFED to import vegetables. State Governments should now get into the procurement of goods and selling in the domestic market when they are not available in the domestic market. This would be expensive and that is the cost that the Government will have to pay. So, Sir, to sum up, this is the signal that should be given. He talked about four or five policies but other polices would have no effect, if I may say so, except the PDS point. Universalise the Public Distribution System. This is the most important thing. Then, bring in those three ordinances to curb inflationary expectations. I think this is the short-term measure that the Government must take in order to get out of the present crisis. Thank you.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। महोदय, सरकार के बयान के अनुसार कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है और देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों के बढ़ने के बाद भी सरकार का भंडार खाली है। इसका क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता है। अगर सरकार का भंडार खाली है, तो इसका मतलब है कि व्यापारियों का भंडार भरा हुआ है और जिसके कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, जो सरकार के नियंत्रण के बाहर है। इसकी वजह से भी सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही साथ जो वितरण व्यवस्था सरकार की है, वह भी ठीक नहीं है। इसका असर भी महंगाई पर पड़ रहा है।

महोदय, आज भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, वे महंगी होनी चाहिए, लेकिन आज वे सस्ती होती जा रही हैं और आवश्यक उपभोग की चीजें, आवश्यक सुविधाओं की चीजें जो सस्ती होनी चाहिए, वे लगातार महंगी होती जा रही हैं। महोदय, मैं जब पहली बार एम०पी० बनकर आया, मैं नौकरी छोड़कर एम०पी० बना था, एक चतुर्थ श्रेणी की महिला उस समय मुझसे बोली की आप एम०पी० बन गये। आप हमारा एक अनुरोध सरकार को बताइयेगा। सरकार दाल सस्ती कर दे और शराब को महंगा कर दे। उसने यह इसलिए कहा था कि जब दाल सस्ती हो जाती है, तो दाल के जूस का पानी पी कर के गरीब का बच्चा भी जी लेता है और गरीब भी जी लेता है। लेकिन उल्टा हो रहा है, अब शराब सस्ती होती जा रही है और दाल महंगी होती जा रही है। उस महिला का कथन था कि शराब पीकर के पति लोग उदंडता करते हैं, निकम्मे निकलते हैं और साथ ही साथ गरीब महिलाओं पर डंडे बजाने का काम भी करते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दाल को तथा आवश्यक वस्तुओं को सस्ती करने के विषय में जरूर सोचे। इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कृषि के लिए सबसिडी देने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए सबसिडी भी दी जानी चाहिए। जब हमारी खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमारे देश से दूसरे देशों को निर्यात नहीं होना चाहिए। निर्यात पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जमाखोरी, मुनाफाखोरी को भी बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ खाद्यान्न के आयात को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम इस महंगाई पर नियंत्रण कर सकें। इस देश में अमीर-गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारा सभी पक्ष के लोगों को सुझाव है कि जो राजनैतिक दल चंदों के नाम पर पूंजीपतियों से आर्थिक सहयोग लिया करते हैं और चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाने का काम किया करते हैं, सरकार बनने पर लगता है कि पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन मेरी राय में पार्टी की नहीं, जो व्यापारी सहारा देता है, उसके इशारे पर सरकार चलती है। जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, इन बड़े-बड़े व्यापारियों ...(व्यवधान)...

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): क्या आप यू.पी. की बात कर रहे हैं?

श्री गांधी आज़ाद: मैं आपकी बात कर रहा हूं । बड़े-बड़े व्यापारियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं, इसीलिए महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है और आज़ादी के बाद अमीर-गरीब की खाई भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है और साथ ही साथ मैं सरकार को सचेत भी करना चाहता हूं कि महंगाई की बढ़ती रफ्तार रोक न पाए यह सरकार। मैं इस सरकार को इसलिए भी सचेत करना चाहता हूं कि प्याज की महंगाई पर हमारे ये साथी लोग जो उधर बैठे थे, इधर चले आए। जब सभी चीजों की महंगाई हो रही है, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी, आप कहां बैठना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए और रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। सरकार जनकल्याण के लिए होती है, जनहित के लिए होती है, लाभ-हानि के लिए नहीं होती है, यही मेरा सुझाव है। इसको मानते हुए, इस आशा से अगर आप इस महंगाई पर कंट्रोल करने का कोई कारगर उपाय निकालें, तो उचित होगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Mr. Gandhi Azad. You stuck to the time. Next is, Shri Tariq Anwar.

श्री तारिक अनवर: उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस महत्वपूर्ण बहस का स्वागत करता हूं। आज की इस बहस में कई अच्छे सुझाव भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यह बात बिल्कुल सही है कि जो महंगाई की मार है, इससे सभी लोग प्रभावित हैं। हमारे देश में कुछ ही ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, जिनके ऊपर इस महंगाई का असर नहीं हो सकता है। जो हमारी जनसंख्या है, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो डेलीवेज पर काम करते हैं। जो उनकी डेली की आमदनी होती है, उसी से उनकी रोजी-रोटी चलती है और उनके बच्चों का पालन-पोषण होता है। ऐसे लोगों का अपना मंथली बजट संतुलित करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस संकट से कैसे निकला जाए, इसके लिए केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है।

महोदय, यह संकट कोई पहली बार नहीं आया है। इस देश में पहले भी इस तरह का inflation हुआ है, इस तरह महंगाई की दर बढ़ी है। सन् 1977 और 1980 के बीच में 15 प्रतिशत inflation हुआ था, 1989 और

1991 में 13 प्रतिशत हुआ था, 2004 में 7 प्रतिशत हुआ था और अभी हमारी inflation की दर 7 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। यकीनन यह चिंता का विषय है और इस पर गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम इस बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगा सकते हैं। यह बात सही है और हमने कहा है कि विश्वव्यापी महंगाई बढ़ रही है। यह सच्चाई भी है कि आज हर चीज की कीमत विश्व में बढ़ रही है, खाने-पीने की चीजों से लेकर अन्य दूसरी चीजों तक की कीमत बढ़ रही है। यहां crude oil की बात भी कही गई कि crude oil की कीमत आज आसमान छू रही है। इस inflation से हमारा देश ही प्रभावित नहीं है, बल्कि चीन जैसा देश भी, जिसको हम मानते हैं कि उसकी GDP हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन आज वह भी inflation का शिकार है। आज वहां भी काफी बड़ी तादाद में लोग महंगाई से परेशान हैं।

महोदय, इस महंगाई को रोकने के लिए हम इस पर दो प्रकार से अंकुश लगा सकते हैं-एक तो short-term है और दूसरी long-term planning हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। जैसे गेहूं, चावल के निर्यात पर रोक लगाई है। आयात पर एक्साइज डयूटी खत्म की है। और भी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां होर्डिंग और काला बाजारी के खिलाफ की गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को भी बराबर यह निर्देश दिया जा रहा है कि वे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जहां तक लॉंग टर्म प्लानिंग का सवाल है, वह किसान, जो अनाज पैदा करता है, जब तक उसे वह कीमत नहीं मिलेगी, जो उसके लिए आकर्षक हो, तब तक यह संभव नहीं है। किसानों को उनकी सही कीमत मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उन्हें सही कीमत नहीं मिलेगी तो वे यकीनन कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे। यह दुनिया के बहुत सारे देशों में हो रहा है, यहां तक कि अमरीका जैसे देश में भी हो रहा है। आज वहां का किसान कॉर्न से अनाकर्षित होकर बायो फूड की तरफ जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम किस तरह से किसानों को आकर्षित करें, उन्हें इसका प्रलोभन दिया जाए, मौका दिया जाए ताकि उनमें अनाज की दिलचस्पी बनी रहे ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह के क्राइसेज़ फिर पैदा न हों। देश के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि हमारे देश में पचास प्रतिशत यील्ड बढ़ाने की संभावना है। हमारी नई टेक्नोलॉजी को यदि खेतों में इस्तेमाल करें तो पचास प्रतिशत तक अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। अगर हम चीन के मुकाबले में देखें तो हमारी पर हेक्टेयर यील्ड करीब-करीब आधी है। खेती के लिए जमीन दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहां औद्योगिकरण हो रहा है, हम अरबेनाइज की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से जमीन की कमी हो रही है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपनी प्रॉडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन और उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर उनके सुझावों पर ध्यान दें तो जो अभी सुझाव दिया है कि अपनी प्रॉडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसका लाभ उठा सकते हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि किसानों को सही मुआवजा मिलना चाहिए, इसके साथ ही साथ समय पर कर्ज और अच्छे ब्रीड के बीज भी मुहैया कराए जाएं। हमारे देश में सिंचाई का अभी भी उच्चतम प्रबंध नहीं है। हमारा किसान अभी भी प्रकृति पर निर्भर करता है, बारिश का इंतजार करता है। अगर बारिश आती है तो वह खेती कर पाता है, नहीं तो उसके सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह समझता हूं कि सरकार को दूरगामी कदम के साथ ही एक शॉर्ट टर्म कदम उठाने की भी जरूरत है। अभी जो संकट है, उस संकट से देश के लोगों, जनता, खास तौर पर गरीबों, आम आदमी को कैसे निकाला जाए, यह प्रश्न सामने है। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो उसमें वे तमाम लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं। जिनको अभी तक हमने जो आर्थिक उन्नति की है, उसका लाभ नहीं मिल पाया है, वैसे लोगों को इस संकट से निकालने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यह जो होर्डिंग और पी॰डी॰एस॰ सिस्टम है, उसको भी और दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें राज्य सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि पी॰डी॰एस॰ सिस्टम राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। अभी सीताराम येचुरी जी ने कहा कि राज्य सरकारों को जो अनाज दिया जाता था (समय की घंटी), गरीबी रेखा से नीचे के लिए और दूसरे लोगों के लिए, उसमें केन्द्र सरकार ने कटौती की है। मैं समझता हूं कि सिर्फ कोटा बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पीडीएस सिस्टम को ठीक करना होगा और उसका लाभ, वह गल्ला, वह अनाज, जिसके लिए केन्द्र सरकार दे रही है, वह वहीं तक पहुंचे। उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समन्वय आवश्यक है और इसमें केन्द्र सरकार पहल करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ उम्मीद

करता हूं कि आने वाले समय में केन्द्र सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी, जिससे हम इस संकट से बाहर आ सकेंगे। धन्यवाद।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, the situation of rising prices is quite alarming. But I don't think that it has been developed overnight. It was not developed overnight. Umpteen number of times this issue has been discussed in this august House cautioning the Government not to close eyes to the global economy. And, this nation has been totally misled by the Finance Minister of this country that the US-driven recession has the global impact, but will not have any impact on the economy of this country. But it has been proved differently. Subsequently, the Finance Minister has admitted it. Sir, the Government has totally closed its eyes to the stagnation in agricultural production, United States' impact on financial market and the US-driven recession at the global level. Virtually, the global shortage of foodgrains trend was not taken note of by the Government. A number of papers have been writing that the United States has changed its cropping pattern and 25 per cent of its maize production has been converted into bio-fuel and to that extent the production of wheat has gone down in the United States, and there was a shortage of production in rice-producing countries like Vietnam and Thailand. They have also imposed ban on exports, which has culminated into the total shortage at the global level. Unfortunately, the production in the country is not as per the pace of the growth of population and at the expected level. So, keeping in view all those things, the Government should have anticipated that there is going to be inflation. The Government cannot shirk its responsibility and it cannot search for scapegoat also and throw the blame on the State Governments. It has become a fashion, being a federal country, that the Central Government is blaming the States and the States are blaming the Centre. Ultimately, the victims are the people of the country. The role of the federal Government is quite clear. Till today, the Prime Minister of this country does not have time to interact with the Chief Ministers of the States to control this malady or situation.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Why are you saying that the Prime Minister does not have time? ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Why has he not called them? ...(*Interruptions*)... We cannot refer to the Prime Minister even when the public is facing a lot of difficulties at the ground level. ...(*Interruptions*)... How long can it continue? Even a farmer could have controlled this economy on a more perfect line than the Prime Minister of this country, being a renowned economist. ...(*Interruptions*)... Why do you bother? Every time, he claims innocence of all the events. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ramachandraiahji, please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I don't know why he is reacting. If you are loyal to him, show the loyalty to him, not to others. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Ramachandraiah, please, address the Chair.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Now, the Government acted belatedly after things went out of control. The small measures, which have been initiated by the Government to impose ban on exports, or impose more customs duty, will not be sufficient. I do not say that they are not needed. They are needed. But, I do not think they are sufficient. The inflation has been

caused not by demand push. If the Government is contemplating to initiate monetary measures by increasing CRR to suck the liquidity, it is thoroughly mistaken. It is a grave mistake it is going to commit. It will affect the growth rate. It will affect the interest rates. Virtually, it will squeeze the growth of industry. So that is not the solution. Solution lies with 'make available commodities which are in shortage to the ordinary man'. You import, whether it is cereals or edible oils, even if they are expensive. You say that global inflation is there which you cannot control. It is true. But, we cannot say that to the people. It is the duty of any civilised Government to make available all the foodgrains and edible oils at affordable prices to the common man in the country, and I think, this is a civilised Government. It is true that at global level, picture is very alarming. Yesterday, the World Bank President has made a statement. He has stated that majority of the population of developing countries will suffer from hunger and malnutrition due to lack of affordable foodstuffs. He further said that it might lead to international economic crisis unless we contain prices. Unless inflation is contained, it may lead to social unrest which may culminate into wars. He has gone to the extent of saying that this may lead to wars. Sir, the Government of India is aware that Australia, which is one of the principal producers of wheat, has suffered drought continuously for two years. The U.S. has converted maize into bio fuels. We should have anticipated it as there are prudent economists in this country. Everybody has mentioned about three eminent persons who have been monitoring the economy of this country-Dr. Manmohan Singh, Mr. Ahluwalia and Mr. Chidambaram. In spite of that, what is happening is that people are facing misery at the ground level. At this stage, I think I am not crossing my limits if I pay tributes to the NDA Government that inflation never exceeded 5 per cent during those 4-5 years and how do you justify it? This wholesale price index is not a true indicator of the prices prevailing at ground level. Consumer price index is different. Even today, the Government of India could not build up an effective tool of assess inflation in the country over a period of time. Sir, I was to restrain myself from blaming the Government, but I am constrained. It is the total mismanagement of the economy of this country. What have they done within a span of four years? You are in power. What exactly have you done to increase the productivity of the farming community? How many lakhs of acres have been brought under *ayacut*? Why has the capital formation in agriculture not gone up? And, you have been enjoying the buoyancy of the revenues. You have been enjoying the growth rate of 9.6 per cent. There are more than expected revenues to the exchequer of the country. Then, why are you not able to create capital assets which have a long effect on the economy of this country? That was the reason for foodgrains production not going up to the expected level, up to the requirements of the population, up to the nutrition requirements. Today, Sir, it has become a fashion for us to talk about agrarian distress every time. But, not even a single measure or constructive step has been taken to ameliorate the condition of farming community. We are not making the farmers live with comfort and dignity in the country. There is no incentive for them to continue to be farmers. They produce food for us and they are being penalised. Sir, there was the Oilseeds Mission in 1980, and later on, the Pulses Mission was also there. Sir, they decided to increase the productivity of oil seeds and the pulses. Subsequently, these two schemes have been shelved because of the thinking that we are accumulating more foreign exchange reserves, we can import. But, at what cost, Sir? Till today, we are more concentrating on the pulses, still, we continue to depend on Myanmar and other countries for importing pulses. Why has the Government not initiated measures to improve the production of pulses in this country?

Sir, at the time of closing of the first half of this present Session, we were rather depressed with the loan-waiver that has been announced. They are very happy as if the entire farming

community is with them, and, if the nation is going to polls, we are going to lose the elections. Now, let them announce the elections and face the people. Do you know the pulse of the public today? Whatever the scene you have created, whatever the hype you have created with the announcement of the Sixth Pay Commission and the loan-waiver of Rs. 60,000 crore, the negative fallout of the incease in prices has nullified it all. *(Time-bell)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I have some suggestions to make. Sir, some short term measures have to be taken. They will never take long-term measures. Sir, there is no alternative because this inflation has been caused by the shortages. So, the Government has to address this problem and try to import. I heard one of my colleagues saying that there was no non-availability. Availability is there but at an increased cost. You pay more because the Finance Minister has said that there is more headway of revenue deficit, he can borrow and he can increase the revenue deficit. On the floor of the House, he said so. So, even though it is expensive, import, and, distribute it through the Public Distribution System, not through the private operators. If you import through private operators, they enjoy customs relief and they will hoard it. So, only if you distribute it through Public Distribution System, the common man will get the benefit. This is one measure that I wanted to suggest.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIEN): Please conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: You have to take a decision immediately. Yesterday, there was a meeting. There was no cohesion among the Cabinet.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please give your suggestion and conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, there is no cohesion with the same party. The Finance Minister is differing with the Commerce Minister on the levies. Don't try to hesitate. Create harmony among your own Cabinet colleagues, come to a conclusion, and, formulate and announce schemes that are needed for the people.

So, as we cannot discuss now the long-term measures, my request to the Government is to immediately strengthen the Public Distribution System and make essential commodities available to the common man, through the effective Public Distribution System. Thank you

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज का विषय है-महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? बीमारी साफ है, इलाज का पता है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यूपीए सरकार के गठन के बाद कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से तो महंगाई ने नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई की दर 6 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है, जल्द ही यह 7 परसेंट का आंकड़ा पार कर लेगी और अगर सरकार का रवैया यही रहा, तो यह दहाई अंकों में भी पहुंच सकती है।

कीमतों में हो रही बढ़ोतरी उत्पादन या पैदावार में आई गिरावट या कमी का नतीजा नहीं है। सच तो यह है कि पिछले तीन वर्षों से मानसून आमतौर पर ठीक-ठाक रहा है। महंगाई की असली वजह सरकार का गलत फूड मैनेजमेंट है तथा अब तो लगता है कि इस मैनेजमेंट का मकसद ही कीमतें बढ़ाना है। सरकार कीमतें कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ रिजर्व बैंक से कह रही है कि वह अपनी मौद्रिक नीति सख्त करे, ताकि बाजार में पैसे का फैलाव कमजोर पड़े। रिजर्व बैंक बार-बार मौद्रिक नीति को कोस रहा है, लेकिन कीमतें घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। रिजर्व बैंक का तरीका इसलिए कारगर नहीं हो पा रहा है कि जिन चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, वे बैंकों से कर्ज लेकर नहीं खरीदी जातीं। वे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, जिनकी खरीद वे लोग भी करते हैं, जिन्होंने कभी बैंकों में कदम नहीं रखे।

5.00 P.M.

महोदय, सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने फुड सिक्युरिटी का बंटाधार कर दिया, एफसीआई को कमजोर कर दिया, किसानों से सीधे अनाज खरीदने का जिम्मा देशी और विदेशी प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द कर दिया। इसके चलते एफसीआई का स्टॉक प्रभावित हुआ और पिछले साल हमें आस्ट्रेलिया से अनाज इम्पोर्ट करना पड़ा। आज हमें एक अजीब विडंबना का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोई कंपनी हमारे किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीद कर उसका भंडारण करती है, दूसरी तरफ हम बहुत ज्यादा कीमत पर आस्ट्रेलिया से अनाज इम्पोर्ट करते हैं। यह किस तरह का आर्थिक सुधार है? जब हम मांग करते हैं कि हमारे किसानों को दिए जाने वाले मिनिमम सपोर्ट प्राइस को थोड़ा बढ़ा दो, तो उसकी अनसुनी कर दी जाती है, लेकिन कीमतें घटाने का संकल्प जताते हुए सरकार ज्यादा कीमत पर अनाज इम्पोर्ट करती है। हमें कहा जाता है कि किसानों को सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आस्ट्रेलिया से ज्यादा कीमत पर अनाज खरीदने के लिए कहां से पैसा आ जाता है? जाहिर है कि सरकार का फूड मैनेजमेंट गलत है, जिसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हमें बढ़ती कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है। हमारे पीडीएस का बुरा हाल है। इसे फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। खाद्यान्न की खरीद को लेकर उसका जो रवैया दिखाई पड़ रहा है और एफसीआई को लेकर उसकी जो उदासीनता है, उससे साफ लगता है कि वह पीडीएस को ही खत्म कर देना चाहती है।

महोदय, जरूरी चीजों के वायदा बाजार का अस्तित्व में आ जाना आज की महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है। एक आंकलन के मुताबिक इस कारोबार में 20 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इतनी बड़ी रकम लगाने वाले वायदा कारोबारी, जिंसों की कीमतें कम क्यों होने देंगे? वे अपनी धन शक्ति का इस्तेमाल कर कीमतें बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को अनाज खरीदने की इजाजत देकर सरकार ने जमाखोरियों का इंतजाम कर ही रखा है और वायदा कारोबार मुनाफाखोरी को पक्का करने के लिए वजूद में आ गया है। सरकार से कई बार मांग की कि कॉमोडिटी एक्सचेंज बंद कर दिया जाए और वायदा कारोबार को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए, लेकिन सरकार सट्टेबाजों को खुला खेल खेलने देने पर आमादा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यह महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है और महंगाई खत्म करने के लिए एक भी जरूरी कदम नहीं उठा रही है। वायदा कारोबार और कॉमोडिटी एक्सचेंज को एक झटके में बंद किया जा सकता है। इसका असर फौरन बाजार पर दिखाई पड़ेगा। एफसीआई को मजबूत बनाने और अनाज की सरकारी खरीद बढ़ाने के कदम उठाने से जमाखोर कीमतें कम होने के डर से अपना माल बाजार में उतारेंगे। इससे भी बाजार पर अच्छा असर पड़ेगा। पीडीएस को दुरुस्त करने की कवायद आने वाले दिनों में हमारे देश के जरूरतमंद लोगों का भला करेगी।

बीमारी साफ दिख रही है, लेकिन सरकार उसका इलाज नहीं कर रही। इससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार में बैठे कुछ लोगों का इसमें निहित स्वार्थ तो नहीं है। फाइनेन्स मिनिस्टर रिजर्व बैंक से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन जिन मंत्रालयों पर महंगाई रोकने का जिम्मा है, उनसे कुछ करवाने में अगर पी॰ चिदम्बरम साहब कामयाब हो जाएं, तो बात बने। महंगाई रोकने या बढ़ाने में कृषि, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालयों का अहम रोल होता है। एफसीआई, सपोर्ट प्राइस, किसानों से अनाज खरीद, पीडीएस और कॉमोडिटी एक्सचेंज इन्हीं मंत्रालयों के जिम्मे है। आज इतने सारे मंत्रालयों का मुखिया एक ही व्यक्ति है। जब देश के लोग देश की महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, तब वे क्रिकेट की राजनीति करने में व्यस्त हैं। यह एक ऐसी विडंबना है, जो हमारे देश की एक बड़ी हकीकत बनी हुई है। जाहिर है, कीमतें बढ़ने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं, जिनके जिम्मे कीमतें कम करने का काम सौंपा गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डॉ॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, सदन में आज देश में महंगाई की जो ज्वलंत समस्या है और इसके कारण जिस दौर से आज पूरा देश गुजर रहा है, आम आदमी परेशान है, उस पर चर्चा हो रही है। सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है और पूरा सदन इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। हमारे कई सम्मानित साथियों ने इस विषय पर अपनी-अपनी बात कही है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर हो रही चर्चा में मुख्य मुद्दा जो होना चाहिए था, वह यह होना चाहिए था कि हम यह देखते कि इस महंगाई के कारण क्या हैं

और इस महंगाई को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा क्या कारगर उपाय किए जाने चाहिए और इसमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, लेकिन इस पर बहुत कम विचार सामने आए।

महोदय, मुझे तब बड़ा आश्चर्य और अफसोस हुआ जब बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेताओं ने मुद्दे की बात न करके इस विषय पर ज्यादातर सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए, आलोचना और राजनीति ही की।

महोदय, यह सही है कि यह समस्या जैसे भारत में है, वैसे पूरे विश्व में भी यह समस्या है और पूरे विश्व में गत एक वर्ष में कमरतोड़ महंगाई बढ़ी है और उसके असर से हम भी अछूते नहीं है। हमारे देश में इस महंगाई की मार ज्यादातर गृहणियों पर ही अधिक पड़ रही है। अच्छा होता यदि हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते, क्योंकि हम जब कभी भी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर इस सदन में चर्चा करते हैं तो मैंने देखा है कि कलेक्टिव रिस्पांसिब्लिटी की, सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती है और यह भी उसी तरह का मुद्दा है, जिस पर सभी दलों को वैसा ही रुख दिखाना चाहिए था।

महोदय, सभी इस बात को जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 113 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। जब पेट्रोलियम पदार्थ या तेल की कीमतें इतनी ऊंची हो जाती हैं तो जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और उस कारण से महंगाई बढ़ती है। तो इस बात की जानकारी भी आम जनता को देना, इस बात से अवगत कराना हमारा फर्ज़ है कि आखिर जो यह इतनी महंगाई बढ़ी है, इसके कारण क्या हैं।

हमारे कई बड़े-बड़े सम्माननीय नेताओं ने इस चर्चा में बोलते हुए अपने विचार रखे। अभी हमारे बी॰जे॰पी॰ के एक नेता इस सदन में कह रहे थे कि किसानों के 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज़, जो केन्द्र सरकार ने माफ किए हैं, यह महंगाई उसका परिणाम है, उसका नतीजा है, तो यह जो किसान विरोधी नज़रिया उन्होंने बताया, यह शायद उनका नज़रिया होगा, पर मेरे विचार से अधिकांश सदस्य इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। इस सदन के हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वे बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूं लेकिन आज उन्होंने बोलते हुए बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने महंगाई का कारण यह बताया कि जहां कांग्रेसी सरकारें हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में, वहां कालाबाजारियों और जमाखोरों पर सरकारों के प्रयास से छापे मारे गए। उन सरकारों की सराहना करने की बजाए उन्होंने यह कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में जो छापे मारे, यह कांग्रेस की एक मिलीभगत की राजनीति है और प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के सौजन्य से ऐसा हुआ है। महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जमाखोर हैं, जिनके यहां से हजारों-लाखों मीट्रिक टन अनाज और दालें बरामद हुई हैं, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों से और दिल्ली में भी कांग्रेस की मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित के प्रयासों से अगर कई जगह छापे मारकर हजारों क्विंटल की मात्रा में अनाज और दालें अगर पकड़ी गई हैं, तो उसकी सराहना करनी चाहिए या उसकी भी आलोचना करनी चाहिए?

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): उनका यह कहना था कि पूरे देश में ऐसे छापे पड़ने चाहिए, केवल दो प्रदेशों में नहीं।

डॉ॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): मैं भी यही कह रही हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूं कि सभी सरकारों का यह कलेक्टिव जिम्मा होना चाहिए केन्द्र सरकार के साथ कि वे भी, केवल मात्र एक ज़बानी संवेदना प्रकट करने की बजाए, अपने-अपने राज्यों में यह कार्रवाई करें कि एक तो खाद्य पदार्थों पर जो टैक्स या शुल्क लगे हैं, उनको उन शुल्कों से मुक्त किया जाए...। अपने रेवेन्यू को छोड़ा जाए और आम आदमी को कैसे राशन की सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध हो, इसकी कम से कम 50 फीसदी जिम्मेदारी राज्य सरकारें वहन करें। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकारों ने यह शुरुआत की है, यह शुरुआत और जगह भी होनी चाहिए, दूसरे राज्यों में भी जो जमाखोरी और कालाबाज़ारी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर समस्या राजस्थान में मेरी जानकारी में आई है कि अगर किसी राशन की दुकान से एक व्यक्ति को 35 किलो चावल मिलता है, तो व्यापारी उससे कहता है कि 20 किलो चावल तुम फ्री ले जाओ, हम तुम्हें नि:शुल्क देते हैं और बाकी 15 किलो चावल को वह 10 रुपए या 12 रुपए किलो के हिसाब

से बेच रहा है। इस तरह से कालाबाजारी हो रही है। इस पर कौन नजर रखेगा? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस राशन प्रणाली को नियंत्रित करें और इस पर नजर रखें।

महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब कांग्रेस का राज़ आता है, तो महंगाई आती है। ये कैसी विचित्र बात कही है? एक तरफ तो शरद यादव जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी NDA सरकार के जमाने में अनाज का इतना भंडार था कि उन्होंने उस भंडार को जनता के लिए खूब खोला। मैं पूछना चाहती हूं कि वह स्टॉक किसने जमा किया था? क्या NDA सरकार के समय में उस अनाज का भंडारण किया गया था? वह भंडारण श्री नरसिंह राव जी की कांग्रेस सरकार की देन थी, जब अनाज का इतना संग्रहण हुआ था, जिसका लाभ इन लोगों ने उठाया, लेकिन उतना ही अनाज वापस संग्रह करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तब जाकर इस तरह की स्थिति बनी।

महोदय, माननीय शरद यादव जी ने खुद पिछले वर्ष बजट पर चर्चा के समय अपने भाषण में यह कहा था कि अधिकारियों के गुमराह करने पर उन्होंने खाद्यान्नों की forward trading शुरू की और बाद में UPA के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी को उन्होंने सलाह दी कि इसको बंद किया जाना चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आया कि वे स्वयं इतने वरिष्ठ नेता हैं, वे कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो जब उन्हें यह लगा कि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें गुमराह कर सकते हैं, तो उन्होंने स्वयं यह प्रणाली समाप्त करनी उचित क्यों नहीं समझी? (समय की घंटी) मैं जानता हूं कि समय की कमी है, लेकिन अभी काफी बातें हैं, जो मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि आज ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): एक महिला बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए...(व्यवधान)...

डॉ. प्रभा ठाकुर: महोदय, ladies first का मुहावरा खाली एक मुहावरा बनकर रह गया है, only lip sympathy. मुझे यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन जहां मेरा नाम था, ठीक है, जो भी व्यवस्था है, उसे धकेलते हुए पहले तो वहां से पिछले नंबर पर भेजा गया, अब मुझे बोलने का मौका मिला है, आप समझ लीजिए कि मैं इस देश की महिलाओं की ओर से बोल रही हूं। आज महिलाओं पर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Madam, don't forget that you are the second speaker. There are a lot of other speakers.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: 5 मिनट दे दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But the previous speaker has taken more time. What can I do?

डॉ. प्रभा ठाकुर: मुझ आप से प्रोटेक्शन चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): What can I do? The Chair can't do anything if the previous speaker has taken more time.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, who is the previous speaker?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Not the Chair!

डॉ. प्रभा ठाकुर: सर, यह जो Essential Commodities Act था, जिसके माध्यम से हम जमाखोरों पर नियंत्रण रखते थे, इसे किसने समाप्त किया इसे NDA सरकार ने समाप्त किया, जमाखोरों को प्रोटेक्शन दिया, कालाबाज़ारियों को संरक्षण दिया, उस Act को खत्म किया और आज वे लोग यहां इस तरह की बातें करते हैं जैसे उन्हें जनता की बड़ी परवाह है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहती हूं कि चूंकि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव निकट हैं, उनको देखते हुए भी ऐसे लोगों को शायद शह मिली होगी और इसके कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो छापे मारे गए हैं, उनमें यह बात प्रमाणिक हुई है। मैं इस देश की आम जनता और महिलाओं की ओर से मांग करती हूं कि दूसरे राज्यों में भी जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं या कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां भी इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए।

इसके अलावा जो आम जरूरत के खाद्यान्न हैं, उन पर से शुल्क हटा लिए जाने चाहिए, उनके टैक्सेज़ हटाने चाहिए, राज्य सरकारों को अपनी रेवेन्यू का मोह छोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में किसान लोग कतार लगाकर 11-11 दिनों से खड़े हैं, उनका अनाज खरीदा नहीं जा रहा है, वहां पर किसानों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। यह व्यवस्था हो रही है। मैं तो यह कहती हूं, राजस्थान से मैं आती हूं, वहां गली-गली और मोहल्लों में जितनी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिनसे महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, कम से कम उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है, उसी से राज्य सरकार वहां की आम जनता और बहनों को अगर सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करा सके और यह जो राशन प्रणाली है, जिसमें भ्रष्टाचार घुस गया है, जिसमें काला बाजारी हावी हो गई है, उस पर वह नियंत्रण कर सके तो इस देश की महिलाओं को, हर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। यहां जो कुछ चर्चा हुई है, उसे देखते हुए मैं अपनी अंतिम पंक्तियों में इतना ही कहना चाहूंगी, "सिर्फ हंगामा खड़ा करना, अपना मकसद न हो, अपनी कोशिश हो कि यह सूरत बदलनी चाहिए।" खाली जबानी sympathy से नहीं होगा। यह globalisation, privatisation शब्द बड़े मनमोहक लगते हैं, मांग भी है और शायद वक्त की जरूरत भी होगी, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूं, वित्त मंत्री जी आप इसके लिए बड़े गंभीर भी हैं, आपने कहा भी है कि महीने भर में नियंत्रण पाया जाएगा मंहगाई पर, और आपने उपाय भी किए हैं। आज इस सरकार की देन है कि किसानों के इतने हजार रुपए की कर्ज माफी की है और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गांवों के लोगों को रोजगार देने जैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। ऐसा आम बजट दिया है, जिसमें आम आदमी को बड़ी रियायतें और सुविधाएं दी हैं, लेकिन इन शब्दों के, privatisation के कभी कुछ प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं, उन पर भी आप नजर रखें, क्योंकि विश्व के और देशों की परिस्थिति जैसी परिस्थिति भारत की नहीं है। हमारी अपनी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए हमारे यहां कई जगह अभी basic infrastructure नहीं है, उसे देखते हुए, इस पर भी अंकुश और प्रतिबंध रखना जरूरी है, ताकि सिर्फ प्राईवेट कंपनियां हर चीज का बाजार, चाहे वह खाद्यान्न संबंधी कृषि बाजार हो, चाहे वह शेयर बाजार हो, चाहे वह आम आदमी की जरूरत की चीजों का बाजार हो, उस पर प्राईवेट कंपनियां कहीं अपना नियंत्रण करके हावी न हो जाएं और आम आदमी मंहगाई से और अधिक त्रस्त न हो जाए, इसके बारे कठोर कानून बनाते हुए कड़े उपाय करने चाहिएं और इसमें केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, rising prices of essential commodities have invited concerns for the Government, and an emergency meeting of the Cabinet Committee on Prices, convened on March 31, has come out with some measures to dampen the prices. The hon. Finance Minister has also told very clearly, while replying to almost all the queries raised here by the Members belonging to the political parties, that the Government is determined to take all steps, fiscal and monetary, and also on the supply side, to moderate inflation, and if that means that we have to live with a slightly lesser growth, so be it. So, the hon. Finance Minister has made it very clear. Sir, before proposing a response to this situation, the Government has got some responsibility to analyse the situation. And this Parliament, with all its responsibility, is discussing it, at length, to arrive at a consensus. The inflation rose sharply even last year, but that was tackled by increasing the interest rates. That situation was entirely different from the situation which we are facing today. 'Reducing inflation by reducing growth' further cannot be the strategy has been established by our Finance Minister. Sir, we must take into account the just attributed factor, here, that inflation is a global phenomenon. But this realisation itself is not the solution. But we should have to think even further. It has come as a surprise that even after the Budget, this Government has not levied any further duty or tax on essential commodities, but, still, there is a further rise in their prices. When we go into the reasons, it is clear that there are two main reasons, which many Members have also observed over here. One is hoarding. Another is the responsibility of the State Governments. The Union Government, on its part, has taken some measures and the results are awaited. On my part-I belong to a regional party, the DMK, but a very responsible party, which is ruling the State of Tamil Nadu under the Chief Ministership of our leader,

Dr. Kalaignar—I am proud to say that the motto of our Government is "prevention is better than cure". Many Members, especially, the left Members, here suggested some remedial measures to control the rise in prices and inflation; and the foremost suggestion was universalisation of the PDS system. I am proud to say here that Tamil Nadu is the only State in India which has implemented universalisation of the PDS. Prior to the Union Government's waiver of farmers' loans in this year's Budget, the Tamil Nadu Government had, in 2006, waived the farmers' loans to the tune of Rs. 7,000 crores. Recently, when the State was flood stricken, a waiver to the tune of Rs. 177 crores was given to the farmers and a compensation of Rs. 7,500 per hectare was given to the farmers before any other help came. As a result of the steps we have taken, the situation is not alarming in our State. For example, during the poll we gave a promise that rice would be distributed through the PDS at Rs. 2 per kilogram and we are still maintaining it. This is the first of its kind in the whole country. In stead of appreciating it, when criticism was levelled against the Government about it implementation that rice alone was not sufficient, we started giving taur daal, black daal, Sooji, maida and edible oils at nominal prices through the PDS. So our Government is a forerunner in this country and we are already implementing many of the suggestions which were made here. When the cement prices soared high, the Government pressurised the cement industry and told them that either they should bring down the prices or all the cement industry would be nationalised. So, the industrialists came, they sat down and agreed to bring down the prices; and now cement is being supplied to the consumers at Rs. 200 in our State. We also give free power to the farmers and the weavers. These things are temporary. Though inflation is global and it has affected many countries and India is also a country which comes under the same category—we are confident of coming out of it because of the measures that we are taking.

I would like to get a clarification from the hon. Finance Minister. The appreciation of the rupee, some people say, will reduce the cost of imported goods, or import parity priced goods. That is the prices of the goods which are determined by the world prices, and that will help us to get goods, which are imported, at a lesser cost. At the same time, there is also a different view. I would like to have a clarification from the Finance Minister on the stand of the Government and which would be better for the future.

The buffer stock system should be maintained well. In China, the situation is well maintained because their stock now is 315 million tonnes. Comparitively to that, in India, it is only 120 million tonnes. The supply from the Union Government, it is believed, to the State Governments for the BPL people is maintained without any cut and whatever is their off-taking, it is being maintained by the Union Government. In these circumstances, this is not a situation to be faced by one political party or one Government. It is a national issue. It is grave concern which every Member has expressed here. I am very hopeful that the measures taken by this Government would settle this issue in a very short time and we are optimistic that India will come out of this crisis also, and our State Tamil Nadu, which is taking more care, especially, of the poorest of the poor, stands as a model to other States in the country. Thank you.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Sir, it is now widely accepted that price rise is one of the gravest problems that the country is facing. But I wonder as to how far the Government is aware of the gravity of the problem While presenting the Budget, the hon Finance Minister expressed his hope that very soon the Budget will have its effect and it will not only contain prices but also control inflation. But, unfortunately, after one and a half months of the presentation of his Budget, the situation has completely changed the other

way and the inflation is almost going to be doubled. It appears that the policy adopted by the hon. Finance Minister, till now, has not proved to be very effective, so far as price rise is concerned. It is a matter which affects the people directly. People are not so much concerned about how many bridges or flyovers have been constructed; but they want two square meals a day. Many of the people go without food in the night. We are facing a very grave situation. We heard Pt. Jawaharlal Nehru long time back, when he publicly announced that he would hang black-marketers and profiteers in public. But nothing had happened at that time. In the present regime, we don't find any such announcement from the Government side. Definitely, the black-marketers and hoarders are playing a very big role in the spiralling prices of essential commodities. The Government has not taken any effective measures to control the situation. It is absolutely necessary to taken stern measures against the hoarders and black-marketers. They are also responsible for the rise in prices. This constant rise in prices is taking place because of them. Another very important factor which is also responsible for the rise in prices is the dismal performance at the agriculture front. The Government has pushed the country to such a stage that we are now depending on import of foodgrains and foodgrains are being imported at very high prices. The agriculture growth has declined and it has gone below 2 per cent. It is very, very serious. Definitely, failure of agriculture is also one of the reasons for the rise in prices of essential commodities. As many of the earlier speakers have suggested, it is high time the Government took effective measures to strengthen the PDS and more and more essential commodities were supplied through PDS. If you claim that you are for the *aam admi,* then it is essential for the Government to give subsidised food to the common people, to the hungry millions. It is unfortunate that no stern action is being taken against the people who are responsible for the rise in prices of essential commodities. For instance, it has already been discussed that forward trading is also having a major effect on the prices.

So, in spite of repeated demands by the Left parties and other parties for banning of forward trading, still the Government does not come out with an outright banning of forward trading. The outcome of this kind of capitalist economy is that on the one hand, the Sensex goes up and there is a steady flow of foreign capital, that is, FII, and the Government is very happy to declare that there is a high rate of growth of GDP, but, unfortunately, it has a very little effect on the fate of the common people, the poor people. So whatever be the high GDP growth rate,—the Government also claims that very soon they can reach a double-digit figure—unfortunately, it is absolutely not having any effect on the poor people, the common people, of the country. So, unless, the total attitude towards the whole problem is not changes, it is apprehended that this price situation will go beyond the control of the Government, and that will be a disastrous situation. So, we hope that all the measures that have been suggested here—this had been widely discussed even earlier in the House—would be taken in all seriousness. So, controlling the price rise must be the priority item of the Government if they are to move along with the *aam aadmi.* I again hope that the Government will come forward to take effective measures against the hoarders, ban future trading and go in for expansion of the PDS. If these things are not done, then, the problem of price rise will go beyond the control of the Government.

श्री प्रकाश केशव आवड़ेकर (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यहां महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। जनता परेशान है, महंगाई आसमान को छू रही है। जो परिवार एक दिन में दो बार सब्जी खाते थे अब उनको दो दिन में एक बार भी नसीब नहीं हो रही है। महंगाई का मतलब है आम आदमी का सही वेतन कम होना, जिससे उसकी जिंदगी पर कुप्रभाव पड़ता है। On a more serious note, inflation in our country is a process of

transfer of assets from poor class to rich class. And, this is a confirmed study. लोग तो ऐसे बेहाल हैं, ऐसे में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार संवेदनशील हो। पहले कहते थे कि जब प्रजा के पांव में अगर कांटा भी चुभ जाता था तो राजा की आंख में आंसू आते थे। लेकिन यह संवेदनशील सरकार नहीं है। जब जनता महंगाई से बेहाल है, तब यू॰पी॰ए॰ का विवाद और चर्चा चल रही है कि प्रधान मंत्री का अगला कैंडीडेट कौन होगा। जनता के सवाल पर इनको कोई सम्वेदना नहीं है। यह विडम्बना है.... (व्यवधान)

श्री शांताराम लक्ष्मण नायक: आपने तो कैंडीडेट डिक्लेयर कर दिया है।

श्री प्रकाश केशव जावड़ेकर: हमने तो कैंडीडेट दिया है और हम महंगाई भी कम करके दिखाएंगे, यह सम्वेदनशीलता का प्रतीक है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी महंगाई का यही आलम था। सरकार ने ऐसे ही घोषणाएं की थीं। लेकिन आज पता चला और एक साल के बाद देखने को मिला कि पिछले साल के सारे वित्तीय उपाय विफल रहे हैं और अब भी सरकार जब घोषणा करती है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के उपायों से काम नहीं होगा। क्योंकि यह महंगाई किसी सुनामी या नेचुरल कैलेमटी के कारण नहीं है, कोई भूचाल नहीं आया है। यह आसमानी नहीं, सुल्तानी है। यह यूपीए की करनी है। ये कैसे यूपीए की करनी है, यह मैं बचे हुए समय में बताना चाहूंगा। परिस्थितियां निर्माण होती हैं। मैंने रेसपांस की बात कही कि संवेदनशील सरकार का रेसपांस कैसे होता है, लेकिन यह सरकार ऐसी है जो जनता को ही महंगाई के लिए जिम्मेदार बता रही है। परसों एक मंत्री जी ने बयान दिया, मंत्री महोदय ने कहा कि क्या करें, लोगों की आदतें बदल गयीं, साउथ के लोग चावल के बजाय रोटी खाने लगे हैं और नार्थ के लोग रोटी के बदले चावल खाने लगे हैं। इसके कारण महंगाई हो रही है। एक मंत्री जी ने कहा कि चीन में ओलम्पिक गेम्स हो रहे हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। अब हमारे समय में Athens में हुआ था, सिडनी में हुआ था, तब महंगाई नहीं हुई थी। आज देश में चावल और गेहूँ की क्या स्थिति है, इसको कोई नहीं बता रहा है। इनकी आदतें बदली हैं, ये जहां मिले, खा रहे हैं, और इसलिए वे लोगों की आदतों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है। एक मंत्री ने कहा, एक्चुअली तीन मंत्रियों ने कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। इस पर डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि जनता की छड़ी क्या होती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जादू की छड़ी नहीं है, तो आपको जाने की घड़ी आई है, यह भी समझ लेना। क्योंकि आज ही बैतूल का रिजल्ट आया है, समझ लेना क्या हो रहा है। एक मंत्री महोदय ने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। अब आईपीएल में फायदा है, इसका ज्योतिष सबको पता है, लेकिन, महंगाई कब कम होगी, इसका ज्योतिष वह नहीं बता सकते। ऐसे-ऐसे बेकार कारण दे रहे हैं कि जिनका कोई सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि यूपीए सरकार की निर्मित महंगाई है, यह टोटल मिस-मैनेजमेंट की कहानी है। खाद्य सुरक्षा बाजार के हवाले कर दी है। अब प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है। मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट के गोदाम में माल जमा होगा, गेहूं और चावल जमा होगा, तब प्राइसेज स्टेबिलाइज होना शुरू होगा। अब प्रोक्योरमेंट का सीजन आ रहा है, तो मंत्री महोदय ने कल-परसों दो बयान दिये हैं। कृषि मंत्री जी का पहला बयान यह है कि हम देश के किसान को एक हजार रुपया अभी दाम घोषित किया है, उसके आगे एक पैसा भी नहीं देंगे। देश के किसान को आप बोनस नहीं देंगे, देश के किसान को एक हजार रुपये से ज्यादा दाम नहीं देंगे। आप प्रोक्योरमेंट करना चाहते हो, तो इस तरह के बयान क्यों देते हो। गवर्नमेंट के पास लोग तभी आयेंगे, वे अपना अनाज गवर्नमेंट को तभी देंगे, जब उनको लगेगा कि उन्हें ज्यादा दाम मिलेगा। साथ ही मंत्री जी ने दूसरे भाषण में कहा कि जरूरत पड़ेगी, तो हम फिर से इम्पोर्ट करेंगे। मैंने विश्व बाजार का जायजा लिया, तो आज दो हजार रुपये गेहूं की कीमत पड़ेगी। विदेशी किसान, आस्ट्रेलियन किसान, अमेरिकी किसान को कृषि मंत्री जी दो हजार रुपये का भाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के किसान को एक हजार रुपये से एक पैसा भी ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हैं, यह नीति है। कैसे प्रोक्योरमेंट होगा? कैसे स्टॉक जमा होगा? कैसे खाद्यान्न सुरक्षा की तैयारी होगी? कैसे आगे जाकर स्टेट्स को पीडीएस के लिए सामान मिलेगा? आज स्टेट का कोटा कम किया है, गरीब को 35 किलो मिलता था, वह कम किया है। आज जब गरीब बाजार में आता है, तो मांग बढ़ती है और फिर खाद्य असुरक्षा का माहौल तैयार होता है। यह सब पीडीएस को ध्वस्त करने की कोशिश है, गेहूं और चावल की यह कहानी है।

सर, एनडीए गवर्नमेंट के समय में बुकिंग के बाद 24 घंटे में कुकिंग गैस का सिलेंडर मिलता था, आज यह 24 दिन में नहीं मिल रहा है। अगर यह वास्तविकता है, तो 300 रुपये के गैस सिलेंडर को लोग आज कालाबाजारी

में 500 रुपये में खरीद रहे हैं। सीमेंट और स्टील के भाव बढ़े हैं। यह कार्टलाइजेशन नहीं है, तो क्या है? यह सब कार्टलाइजेशन के कारण हो रहा है और इसमें पैसे का कितना लेनदेन हुआ है, यह चर्चा भी लोग बाजार में खुलेआम करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। आप WPI के 6 महीने के हर सप्ताह के आंकड़ों को देखिए, Steel prices, for their weightage calculations, have been shown dormant. यानी स्टील के बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, जो स्टील के प्राइस लेने चाहिए, वह डॉरमेंट रखा है। आप ऐसी हेराफेरी करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि प्राइसेज़ नहीं बढ़े हैं। यह 7.41 परसेंट की महंगाई नहीं है, यह 10 परसेंट का आंकड़ा पार कर चुकी है, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आप इसके लिए चाहे कितनी भी चर्चा करना चाहें, हम तैयार हैं। आप यह बार-बार कहते हैं कि हमने MSP बढ़ाया है। आपने MSP बढ़ाकर कोई एहसान नहीं किया है। पिछले तीन-चार साल में बीज के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, और उपलब्धता भी कम हुई है। बिजली के दाम बढ़े हैं, दवा के दाम बढ़े हैं, जब फर्टिलाइजर और हर एग्रिकल्चरल इन्पुट के दाम बढ़े हैं, तो फिर एग्रिकल्चर के MSP बढ़ाए, तो कोई एहसान नहीं होता। महंगाई के बारे में यह जो खेल चल रहा है, इस महंगाई की सारी कहानी यूपीए सरकार द्वारा निर्मित है। सरकार केवल demand management करना चाहती है, केवल fiscal उपाय करना चाहती है, केवल CRR बढ़ाएगी, सप्लाई साइड को कौन देखेगा, वस्तुओं की आपूर्ति कैसे होगी। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि राशन में पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल और शक्कर मिले, इसके साथ-साथ वाज़िब दामों पर खाद्य तेल और दालें भी मिलनी चाहिए। अगर ये चीजें राशन में नहीं मिलेंगी, तो आम आदमी को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलेगी, इसलिए राशन में ये पांच चीजें मिलनी चाहिए। यह हमारा पहला सुझाव है। दूसरी बात यह है कि जो दाम बढ़े हैं, जहां मनोहर जोशी जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे हैं, जब हम 1995 में वहां सत्ता में थे, हमने जनता को पहले ही दिन वचन दिया और कहा था कि जो आज दाम हैं, जब हमने शपथ ली है, वही दाम पांच सालों तक कायम रखेंगे। मुझे यह बात कहने में खुशी है, क्योंकि मैं वहां पर प्लनिंग का काम देखता था, हर साल हमने हजार करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में एक चीज के दाम भी नहीं बढ़ने दिए और वहां पर पांच चीजें उपलब्ध कराई। हमने वहां पर यह करके दिखाया था। आपको भी यह करना चाहिए। आप लाओ फिर से 2004 की प्राइसेज हम दे देंगे, यह कहो। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे आज उत्तर में यह एलान करें कि 2004 के दाम, प्रमुख पांच-सात जीवनावश्यक वस्तुओं के, वे राशन की दुकान में पर्याप्त मात्रा में और 2004 के भाव में मिलेंगे, यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए, तभी थोड़ी सी राहत मिलेगी। हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जब हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पूरे agricultural collapse यह अपने सभागृह की शान है कि यहां स्वामीनाथन जी हमारे सदस्य हैं, स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि We are heading towards total agricultural collapse. सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह तेल की समस्या, दाल की समस्या कोई आज की निर्मित समस्या नहीं है। इसकी स्थिति पिछले तीन साल से बिगड़ रही थी और सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। सरकार ने एक तरफ Technology Mission चलाती है, लेकिन किसान के दस साल के लिए दाम सुनिश्चित नहीं करती। वहां पर irrigation facility नहीं देती है और □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ नहीं देती है। अगर आप किसान को ऐसे मारोगे, तो फिर वह तिलहन नहीं लगाएगा। आपको जिन चीजों की जरूरत है और उसको यदि उन पर मुनाफा नहीं है तो, वह उनको नहीं लगाएगा। he will go in for cash crops. मैं यह कहना चाहता हूं कि यह Technology Mission केवल पेपर पर रहने वाला नहीं चाहिए, वह खेत में सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी सूरत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सरकार का प्राथमिक दायित्व है। यह सरकार आज उसमें फेल हुई है। मेरा यह मानना है कि सरकार दो चीजें सुनिश्चित करती है। यह अंतर्विरोध नहीं है, किसान को लाभकारी मूल्य मिले। यहां पर शरद जोशी जी बैठे हुए हैं, हम बीस साल पहले उनके मूवमेंट में शामिल हुए थे। किसान को लाभकारी मूल्य भी चाहिए, लेकिन ग्राहक को भी तो सही और वाज़िब दामों में चीजें मिलनी चाहिए। यही तो वेलफेयर, डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, यही तो संवेदनशील सरकार की प्रतिभा होती है। लेकिन आज किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और ग्राहक भी लूटा जा रहा है। यह देखना आपका काम है। ऐसा फारवर्ड एक्सचेंज से नहीं, बल्कि बाकी सब कारणों से चल रहा है। डीजल और पेट्रोल के बारे में एक-एक वाक्य में कहना चाहता हूं। डीजल और पेट्रोल के बारे में आप क्यों नहीं स्पष्ट घोषणा करते हैं? अटल जी ने 2004 में यह तय किया था, निर्णय लिया था, जो दफ्तर की फाइलों में मौजूद है कि रेवेन्यू न्यूट्रालाइजेशन की पॉलिसी लानी चाहिए, हम इसे स्वीकार करते

हैं, लेकिन आप रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। विश्व के बाजार में अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो यहां दुगुना असर हो रहा है। सरकार का भी उससे व्युत्पन्न बढ़ रहा है। ग्राहक को दोनों तरफ से मार पड़ रही है।

Why are you not restructuring duties and adopting the revenue neutralisation policies? That is the question I want to raise. Last, but not the least, हमारे समय में कुछ अच्छी चीजें चल रही थीं, उन्हें तो फोलो अप कीजिए। वहां एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, an empowered group of very senior Ministers was appointed. It was monitoring day-to-day price situation. It was meeting every fortnight. It was monitoring 50 items of essential daily needs of the common man and they were constantly monitoring and taking course correction measures and action against any spiralling trends in any of the commodities. That is the mechanism which should be followed. लेकिन यहां किसको फुर्सत है, समय है, आम आदमी महंगाई से कैसे पिसा जा रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। यहां केवल जो चापलूसी की राजनीति चल रही है, लोग उसी में लग रहे हैं। हमारे कुछ मित्र लेफ्ट के हैं। सीताराम येचुरी जी यहां नहीं हैं, हमने उनका भाषण सुना, उन्होंने बार-बार कहा यह सर्कुलर एन॰डी॰ए॰ के जमाने में निकला था। ए॰डी॰ए॰ के जमाने में सर्कुलर निकला, यह क्यों दिखाते हो, वह तो सरप्लस सेस का राज था। सरप्लस सेस भी, किसान के हित के लिए जो करना था, वह अटल जी की सरकार ने किया। सवाल यह है कि अगर आपके काल में स्केयरसिटी पैदा हुई है तो सर्कुलर और कानून बदलना आपका काम है। चार साल पहले के लिए सरकार को दोष दोगे और चार साल चलने वाली सरकार को दोष नहीं दोगे, तो आप जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? जनता पागल नहीं है, जनता देखती है कि इनकी नूरा कुश्ती कैसे चल रही है। यह लेफ्ट का शो नहीं है। कल मुझसे किसी ने कहा कि लेफ्ट का रोड शो हो गया, मैंने कहा कि यह लेफ्ट का शो नहीं है, यह तो एक लॉफ्टर शो है, क्योंकि इसमें जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। एक नूरा कुश्ती का नमूना लोगों ने देखा है। मैं अंत में दो ही बातें कहूंगा, मेरे लेफ्ट के मित्रों को भी एक बार तय करना पड़ेगा कि क्या आप जनता के साथ हैं या सत्ता के साथ हैं। अगर सत्ता के साथ रहना है तो आप भी पाप के भागीदार हैं। अगर यह महंगाई यूपीए का पाप है तो वाम दल उससे बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। पाप के लिए वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह जनता का आक्रोश है, उस आक्रोश को आप सुनिए। यह जनता का आक्रोश है, महंगाई मूल मुद्दा है। अगर महंगाई से राहत नहीं दे पाओगे तो आपका छठा वेतन आयोग भी कुछ काम नहीं आएगा। जो भी कारगर उपाय करना चाहते हैं, वे भी काम नहीं आएंगे। एन॰आर॰ई॰जी॰एस॰ में, जिसमें अठारह, बीस दिन काम मिल रहा है, वह वैसे ही महंगाई में जा रहा है। आपकी सारी फ्लैगशिप्स स्कीम्स का कोई अर्थ नहीं रहेगा जब महंगाई आसमान छुएगी। मुझे लगता है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अब तो हरकत में आइए, अब तो निर्णय कीजिए, अब तो फारवर्ड एक्सचेंज बंद कीजिए, अब तो खाद्य सुरक्षा निश्चित कीजिए, अब तो पांच-दस साल की पॉलिसी निश्चित कीजिए, अब तो जीवन की आवश्यक पांच चीजें, वाजिब दाम में, पर्याप्त मात्रा में राशन की दुकान में उपलब्ध कराइए। इतना ही कहते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Javadekar. I was not stopping you because you were making a maiden speech. You made a very good speech. Thank you. Now, Mr. Shantaram Laxman Naik.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Mr. Vice-Chairman, Sir, we are all concerned about the price rise and there is no denial about that. I remember a line from a Hindi film which I saw many years back, it said, हाय महंगाई, महंगाई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई, महंगाई, तुझे क्यों मौत न आई। Everybody wishes that *mahengai* dies. But it does not die; it is reborn in some form or the other. We are all concerned. But I am wondering how a Rightist party is concerned about *mehengai*. You are branded as a Rightist party right from the Freedom Struggle days. Your earlier predecessor Jan Sangh was known as a capitalist party. You are no way concerned with price rise; you are no way concerned with poor. You represent an elite class. You represent big traders not small because small traders have got their own problems. You represent the big traders who are hoarding grains, who are hoarding food articles. Please use your good offices with them, ask them to open the godowns and the prices will fall. This is our humble request to you. They are your strong supporters. In the

price rise, you have got a vested interest. एक तो आप कहेंगे कि कांग्रेस को हिला दिया, price rise हो गया, Congress is embrassed. दूसरी बात कि आपके जो supporters हैं, उनको बहुत फायदा हो गया। दोनों तरह से आप खुश हैं। इसलिए इस price rise में आपका बहुत बड़ा vested interest है। कांग्रेस पार्टी किसी राजनीति के लिए नहीं जन्मी। The Congress Party was born to face poverty, to face hunger, to face disease, and all other parties were born out of some political necessity to fight elections. The Congress Party is the only party, which was born because of these social issues. आप कहते हैं कि हमारे लिए छड़ी है। हम सह लेंगे। कुछ price increase हुआ है, तो छड़ी सहन करना हमारा भी कर्त्तव्य है। पर आपके लिए लोगों ने डंडा रखा है। जो अराजकता आपने फैलाई है गए दो-चार सालों में, इसके लिए छड़ी नहीं, डंडा रखा है। उसे सहन करने के लिए आपमें ताकत होनी चाहिए। जरा wait कर लिजिए। The second thing I would like to point out here is that by raising price rise issue in this manner, one thing the BJP has indicated is that they are not going to come to power in the near future because any sensible party knows how prices rise. If they know that they are going to come to power, their approach will be a big different because they know they may also have to face this situation. From the manner they are raising, it appears that they have ruled out totally that they are going to come to power. Secondly, Sir, Price rise, inflation, basically किसकी देन है। This *dein* we got from them. In 2004, it was 7 per cent and a bit earlier it was a little lower. But in 2004, as you have pointed out, Sir, it was 7 per cent which we got in inheritance. Our addition is only 0.4 per cent. So, you take blame for the entire 7 per cent. Even during our regime, we maintained for three continuous years price level at 4.5 per cent. This is a commendable thing, which you never appreciated. If you had guts to say so today you could have also appreciated that aspect. Secondly, you also cannot deny I do not know whether you have said it worldwide prices have increased. There are 36 countries where the situation is very bad and even according to a UNO report they even sought external financial assistance and the FAO has-given certain reasons for it. FAO gives three reasons, lower level of stocks in wheat, rice, maize following two years of below average harvest in Europe and Australia in 2006-07; two, an unusual hike in the mineral oil prices, hovering around $110 per barrel resulting in higher transport cost and increasing significantly demand for foodgrains based on biofuel... Third, increased demand in key emerging market like China and India as a result of changing consumption and increased disposable income. These are the reasons given. The rise in prices of many of the food articles in the domestic market has been much lower compared to international prices. It should also be borne in mind that India is dependent on imports of edible oils and pulses. It imports around 40 per cent of its edible oil requirements. It also imports about 15 per cent of its pulses requirements, though it is the largest producer of pulses in the entire world. The prices of edible oil have increased very substantially in the international sphere. India imports primarily palm oil. The increase in prices of these two oils in the international market is in excess of 75 per cent. However, by timely intervention by way of duty reduction, the price rise of soya bean in India was restricted to about 16.5 per cent and that of RBD Palmoline at 17.7 per cent. This proves that the UPA Government has been able to manage prices on the front of edible oil very successfully. Similar is the case with wheat and rice. The price of wheat in the international market has risen from 60 per cent to 115 per cent. However, the corresponding increase in India has been only 7.21 per cent. Similarly, for rice, the international increase has been 131.39 per cent whereas the domestic increase has been 17.65 per cent. For maize, its price increased by about 16 per cent internationally whereas its price in India has actually declined by about 0.3 per cent over the last year. The UPA Government has also been very successful in managing inflation rates over the past year as compared to some of the neighbouring countries including developed world. Inflation in China went up from 2.7 per cent to 8.7 per cent. It is reported

that food inflation in China is as high as 23 per cent. Even countries like Singapore, which had an inflation of 0.6 per cent in February 2007, is witnessing today, in February 2008, ten times that inflation, at 6.5 per cent. Another developed country like South Korea saw its inflation increase from 2.2 per cent to 3.6 per cent. Russia is today at an inflation rate of 12.7 per cent, Pakistan is at an inflation rate of 11.3 per cent, both substantially higher than the last year showing an increase of around 7.5 per cent.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I will summarise in two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Not two minutes, you can take only one minute.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Again, Sir, I would like to point out certain price structure.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, no, that is already here. There is no need of repeating. All these things are said here.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, you are disturbing me unnecessarily.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I am helping you.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: I was No. 2 in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You were not No. 2 but No. 3 in the list.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Then, I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, you complete your speech.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: I will sit down. Unnecessarily, it creates problems.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, Shri Manohar Joshi.

श्री मनोहर जोशी (महाराष्ट्र): वाइस चेयरमैन सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंहगाई के विषय पर मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मैं यह जानता हूं कि मंहगाई का प्रश्न बहुत गंभीर है। मैं यह भी जानता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिस प्रश्न का कोई हल नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में जो चर्चा हो रही है, वह अच्छी तरह से हो रही है। मंहगाई जैसे विषय पर जैसी चर्चा होनी चाहिए, उसी तरीके से आज यहां पर चर्चा हो रही है। यह भी सौभाग्य की बात है कि वित्त मंत्री स्वयं यहां पर उपस्थित हैं। मैं और सदन के सभी सदस्य यह जानते हैं कि चर्चा ठीक तरीके से हो रही है, लेकिन बाहर जनता में बहुत असंतोष है। बाहर जनता नाराज है, संतप्त है और मुझे विश्वास है के पूरे भारत की जनता इस विषय पर ध्यान दे रही है कि सदन की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से अंतिम क्या निर्णय आता है। केवल चर्चा से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं यह भी जानता हूं कि केवल निर्णय करने से भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जनता अभी यह चाहती है कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई हो। इसीलिए मेरी पहली विनती मंत्री महोदय से यही है कि चर्चा तो पूरे दिन आपने सुनी है। अभी इस चर्चा पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, इसमें जनता को इंटरेस्ट है। जनता चाहती है कि इस विषय में तुंत कार्रवाई हो।

सर, एक बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मंहगाई का प्रश्न एक विश्वव्यापी प्रश्न है। अनेक लोगों ने, मेरे से पहले के वक्ताओं ने उदाहरण दिए हैं कि पूरे विश्व में मंहगाई हो रही है। भारत में भी मंहगाई हो रही है, लेकिन लोगों की जो कम्प्लेंट है, वह यही है कि मंहगाई न हो, इसलिए

6.00 P.M.

जो कार्रवाई पिछले 3-4 सालों में करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। हर बार जब कभी प्रश्न-निर्माण होता है, तो मैं यही सोचता हूं कि क्या यह प्रश्न मानव-निर्मित है, क्या यह प्रश्न हमारे हाथ के बाहर का है, क्या इस प्रश्न का कोई इलाज नहीं हो सकता है? जब मंहगाई के प्रश्न की तरफ देखता हूं, तो मैं जानता हूं कि सबसे अच्छा इलाज यहां का उत्पादन बढ़ाना ही था। देश में हरित क्रांति में अग्रणी प्रदेश पंजाब और हरियाणा हैं, लेकिन वहां का उत्पादन भी कम हो रहा है। मुझे याद है कि इसी सदन में पिछले साल जब मंहगाई पर चर्चा हुई, तब भी यह विषय उठा था और यह मांग की गई थी। लोगों ने कहा था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कार्रवाई करे, लेकिन बाद में कभी भी अखबारों में उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा और न मंत्रियों ने निवेदन किया कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं।

सर, एक तरफ से आबादी बढ़ती है और दूसरी तरफ से उत्पादन कम हो जाता है, तो मैं सोचता हूं कि मंहगाई के सिवा दूसरी कोई भी बात नहीं हो सकती है। मेरी दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से यह बार-बार कहा जाता है कि हमारे विकास की गति 9 प्रतिशत तक बढ़ गई। सर, मैं नहीं समझता हूं कि यह गति इतनी अच्छी होने के बावजूद मंहगाई कम नहीं हुई। सभी को शायद मालूम होगा कि विकास की गति जो बढ़ रही है, वह सेवा क्षेत्र में बढ़ रही है और सेवा के क्षेत्र में गति बढ़ने से मंहगाई को नियंत्रित करना मुश्किल है। यदि मंहगाई को नियंत्रित करना है, तो उद्योग और उसी के साथ खेती के बारे में विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता है और इस पर हम ज़ोर नहीं देते हैं, यही सीधी बात है।

एक और कारण जो कहा जाता है, वह उदारीकरण का कारण है, ग्लोबलाइजेशन का कारण है। अनेक बड़ी-बड़ी कम्पनियां अनाज खरीद कर जमाखोरी कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं और अपने जवाब में वह उत्तर दे सकते हैं कि ऐसी कौन सी कम्पनी है, चाहे वह मल्टी-नेशनल हो या कॉरपोरेट, जिन कम्पनियों ने अनाज के व्यवसाय में जमाखोरी की है, क्या गवर्नमेंट को यह नाम मालूम है, क्या सदन के जानकारी के लिए यह सब सदन के सामने रखा जा सकता है? उसके साथ ही क्या गवर्नमेंट की यह भी तैयारी है कि ऐसी जो कम्पनीज़ हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें? ऐसी जमाखोरी न हो, इसके लिए इस कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

सर, मैंने अभी तक आंकड़े तो बहुत सुने। मैं सभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी दृष्टि से ये आंकड़े आवश्यक हैं क्योंकि इसकी बार-बार चर्चा होती है, इसलिए मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त इन चीजों के रेट्स क्या थे और उसके बाद अब कितने रेट्स बढ़े हैं? मैं आपको पहले गेहूं के रेट बताऊंगा, एनडीए के जमाने में रेट 9/-रुपया kg था और अब यह 14/-रुपए से 16/- रुपए तक हुआ है। चावल का रेट जो 10/-रुपए था, अब 22 से 28 रुपए तक हो गया है, ब्रेड जो गरीबों के लिए हर दिन के खाने की चीज़ है, वह 8/-रुपए की थी, अब 15/- रुपए हो गई है। चीनी का रेट तो पहले भी सदन में बताया गया है, यह 14/-रुपए पहले था, अब 18/- रुपए से 24/-रुपए तक हो गया है और चाय का रेट जो 80/- रुपए था, वह बढ़कर अब 150/-रुपए से 180/- रुपए तक हो गया है। मेरे पास यह पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट से मालूम पड़ता है कि जो पहले गवर्नमेंट थी उसके जमाने में इन चीजों के जो रेट्स थे, वे सभी रेट्स अब डबल हुए हैं और कई जगहों पर तो डबल रेट से भी ज्यादा रेट हुए हैं।

महोदय, मंहगाई कितनी, क्यों बढ़ी और कितनी बढ़ सकती है? इनको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? अर्थशास्त्री इस विषय पर चर्चा करते हैं, इकोनोमिस्ट्स केन डिसकस दिस इस्यू, लेकिन मेरी दृष्टि से तो इन रेट्स में कमी लाने में जितनी गंभीरता चाहिए, उतनी गंभीरता मैं आज की सरकार में नहीं देख रहा हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि हमारे देश में यह पद्धति है कि पहले किसी विषय पर आंदोलन हो, लोग कोई विषय लेकर मोर्चा निकालें, केवल मोर्चा निकाल कर न रुकें, लोग इसके आगे जाकर रास्ते पर आकर मार-पीट करें और उसके बाद सरकार सोचने को बैठती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न आए, तो अच्छा है।

महोदय, मैं इस समय सभी आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, गवर्नमेंट को इतना ही कहूंगा कि आपने किसानों की आत्महत्या का विषय उठाया और बजट में 60 हजार करोड़ रुपए की एनाउन्समेंट की, लेकिन आप नहीं जानते कि

इसके पहले पूरे देश को इस विषय को लेकर आंदोलन करना पड़ा था। इसलिए मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि क्या आप यही चाहते हैं कि जैसा आंदोलन किसानों की आत्महत्या को लेकर हुआ, वैसा ही आंदोलन देश में हो? यही आपकी अपेक्षा है क्या? यही मेरा प्रश्न है। आंदोलन होने के बाद, कई लोगों के मारे जाने के बाद यदि आप महंगाई पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वह आज क्यों नहीं करते? यह मेरा प्रश्न है और यही जानने के लिए मैं यहां खड़ा हूँ।

महोदय, मैं अनेक वस्तुओं के दाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस राज में मृत्यु भी महंगी हुई है। आपकी मालूमात के लिए मैं कहूंगा कि हिन्दू धर्म के अनुसार मृतक को शमशान तक ले जाने वाले बांस, मटका, कपड़ा अगरबती सभी चीजों के भाव बढ़े हैं। यह वृद्धि कितनी हुई? पहले 1000/- रुपए खर्चा आता है, अब यह 1200/- रुपए खर्चा आता है। क्रिश्चिन लोगों की शव पेटी का मूल्य जो पहले 3000/- रुपए था, अब यह 5000/- रुपए हो गया है और कब्र खोदने के लिए जो पहले 150/- रुपए लगता था, अब यह 175/- रुपए हो गया है। इसका मतलब यही है कि सर्व धर्म सम्भाव यदि किसी में है, तो इसी में ही है कि सभी धर्मों के लोगों की मृत्यु के बाद जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके भाव सभी धर्मों के लोगों के लिए बढ़े हैं। लोगों को एक और बात पर गुस्सा आता है कि इस गंभीर विषय पर जो वक्तव्य दिए जाते हैं, जेसा मेरे मित्रों ने कहा है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो निवेदन आया है, उसमें कहा गया है कि विपक्ष की ओर से महंगाई पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन वे महंगाई रोकने का उपाय नहीं बताते, यह कांग्रेस का अधिकृत निवेदन है, तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि इस सदन में जो भाषण हुए और सभी पार्टियों की तरफ से जो उपाय दिए गए हैं, आपके साथ रहने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों ने भी उपाय दिए हैं और हमारी ओर से भी उपाय दिए गए, इन उपायों पर आप आगे क्या करना चाहते हैं? आज के दिन का यही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार का अंकुश नहीं है। एक तरफ तो कम्युनिस्ट यह कहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन देते हैं। ऐसे समर्थन देने का अर्थ जनता क्या समझे? इसलिए , मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है । श्री कपिल सिब्बल, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। श्री कपिल सिब्बल साहब, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए जादू की छड़ी नहीं चाहिए होती है, इस काम के लिए sincerity चाहिए होती है। हमें इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हमारे एक सम्माननीय सदस्य, श्री प्रकाश केशव जावड़ेकर जी जब यहां बोल रहे थे तो उन्होंने उदाहरण दिया, जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री था, उस समय की सभी वस्तुओं की लिस्ट मेरे पास है, तो गेहूं, चावल, शक्कर या चीनी, खाद्य तेल और दाल, इन सभी के रेट्स हमने पांच साल के लिए एक रखे थे, पूरे पांच साल और यदि महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट यह कर सकी, तो आपकी गवर्नमेंट क्यो नहीं करती। खर्चा कितना आया? 700 करोड़ रुपए का खर्चा हर साल का आया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को हमने समझाया कि जो काम हमने किया है, वह गरीब लोगों के लिए किया गया काम है और लोगों ने इसे माना। तो मेरी गवर्नमेंट से यही विनती है कि पूरा आन्दोलन होने से पहले यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम इतना करें कि essential commodities के जो रेट्स हैं, उनको कंट्रोल में रखें और जो below poverty line के लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करें, यही मेरी विनती है।

सर, मैं एक वार्निंग देकर अपना भाषण समाप्त करुंगा, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसे समझे, चाहे तो न समझे। महाराष्ट्र के बारे में, शिव सेना के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि इस विषय पर हमारे आंदोलन शुरू हुए हैं। लेकिन आप यह मत समझो कि जैसे सत्याग्रह या कोई फास्टिंग होता है या उपवास होता है, यह वैसा आन्दोलन है, बल्कि इस विषय पर हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। महंगाई यदि सदन में भाषण करने से नहीं रुकेगी तो हम रास्ते पर जाकर महंगाई कम करेंगे, यह हमारा निर्णय है और यही अनेक पार्टियों का निर्णय है, जिसे समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आप इसे समझेंगे और महंगाई रोकेंगे। इतनी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have been hearing all the Members with rapt attention, but I have not really understood what exactly they all

want to say. Everybody said that things were good. When I look back to the papers which are with me and all the reports of the Government, I find that all the suggestion that my friends have made have been implemented fully, and the intention of the Government is to implement the same plus to do some more too. Against such a scenario, I do not know as to exactly where we are leading to through this debate. Sir, I am not to be mistaken at all. I totally agree and there is no gainsaying the fact that all of us are concerned about the rising prices. But let Shri Rahul Bajaj tell us about this. Because, the other day, the CPM said that if the Congress people speak, it will not have any credibility. He is a Harvard expert, let him say about this. In a developing scenario, where the growth rate is nine per cent, doesn't the increase expand demand base along with the price rise which has to be controlled through the supply line? What exactly has gone wrong? This is not the first time that we are seeing this kind of inflation. This is not the first time we are seeing this kind of a rise in prices. We saw this during late 80's, early 90's, then, later, in 2006 also, right within our Government, we had one year with seven per cent inflation. All these things are there. A Government which has been providing you with a growth rate of nine per cent containing the inflation at 4-4.5 per cent and if it has reached seven per cent now does not call for scare screaming, nor pressing panic buttons nor knee-jerk reactions. Sir, what all it requires is a strategy because something had gone wrong in the last one year. During the last twelve months, something had gone wrong. We had to look into it. Sir I don't want to repeat what the other hon. Memebrs have said. Mr. Yechury has made improtant four points. Then three other points were added to it. That is related to the supply side. Dr. Bimal Jalan has made us to look to the demand side too. Now I match these two phenomena and say that these two things should answer all our points. But my question, Mr. Vice-Chairman, Sir, is not related to that at all. Where exactly is the crisis is my question. Do we really face food crisis today? Or, are we facing a price crisis today? There is no food crisis there are no starvation deaths. The production in this country, as it should be, is on the increase. We are reaching a target of something like 220 million tonnes which is supposed to be the highest. We have a buffer stock of five billion tonees as it should be. Instead of 5.6 million, we have a buffer stock of five million tonnes today. Even the rice production is 90 million tonnes as against the consumption level of 82 million tonnes. Looking at this surplus, perhaps, the traders are trying to export it, and, therefore, we have put a ban on that. But what exactly has gone wrong? Let us think about it. Why we are all getting worried is because it is not a sudden development. It was in the making. We have been seeing this for the last two-three years when the signs of these inflationary trends were visible or discernible. But whatever steps were required to be taken, we did take those steps but we anchored them in the developmental and fiscal policies. Sir, what I am trying to say is that I do agree that there is price rise. It is not that I am differing and saying that there is no crisis at all. I know our concern arises mainly because we are all bothered about the food prices. Around forty-seven to fifty per cent consumption of our family budget goes to groceries and that is why we are really getting worried, although the rising prices of cement, steel, etc., are really affecting economy. But why did it all come up? As I said, Sir, it is not a new phenomenon. As my other friends said, it is a world phenomenon. I am not trying to blame it. I am not trying to say that because it is a world phenomenon so you should also suffer from it. I don't want you to suffer from it because of that. But the question today is, can we insulate ourselves? In a global economy, can we totally cut ourselves off from the effects of global markets, from the world happenings? Sir, we need to get into some kind of policies or strategies that will help us to tackle it in the domestic market. That is why we have looked into the PDS. All the Members have said that the PDS has to be restored. Sir, I am trying to conclude within five minutes. Mr. Joshi was saying that the

Congress always finds faults with the Opposition and he had quoted from some documents that we have always complained that Opposition, though it speaks, never suggests anything to us, blah, blah, blah. But let me tell you that all the suggestions that the Opposition has made have found place in the policies of this Government, in the decisions that this Government has taken during the last four months. Sir, the import duty on rice has been abolished; the Minimum Support Price has been fixed; vegetable exports are banned; wheat import duty has been abolished; and sugar DEPB bids are put off. All these suggestions have been made from the Left and other parties. Then, Sir, see what other things are coming. The ban on Basmati which you have asked for has already come. You have asked for further cut in the import duties on edible oils. That is also coming. You have also asked for the open purchase of wheat. That has also come in. So, all the suggestions that the Opposition has been making are taken into consideration, and, therefore, we are in a good position. Then, I come to inflation. My friend, Mr. Shantaram Naik, was trying to tell you about inflation trends in other countries. I am only talking about US, UK and China but he was trying to mention almost all the South-East Asian and West Asian countries where inflation rates have gone up. I am not trying to be happy about the inflation rates going up there. What I am trying to ask you is this. As compared to that, are we not insulated from the price rise? Inflation trend is different from a price rise of food articles. Isn't our rise, as against the world record of 161 and 192 per cent which Mr. Yechury has quoted, only 7 per cent as far as wheat is concerned, and one per cent as far as rice is concernd better? Well, if they are able to maintain this kind of comparison, I do not see the reason why people should find fault with measures that this Government has taken. Then, Members asked why it has come in the last one year. According to me, it is not only one year; it has been coming for the last few years. To put it precisely, ever since the Iraq War, when oil prices have gone up and those prices never looked back since then, we have had this problem. All of us understand that there is a direct link between the power and the commodity market. It is good that this Government has not passed on the energy cost to the people; so much so, today, there is an increase in industrial production. Thus, the supply line is well-oiled. I will make just one point more. Mr. Yechury has asked when everbody has been able to manage it, why not we; I totally agree with all the points that Mr. Yechury made. And I think the Government is seriously concerned about implementing or trying to formulate the same things, the futures trading also. I am one of those who totally agree with it. But let me tell you, the world economics which were concerned about these escalating prices had resorted to some kind of classic macro-economic mechanisms which had failed during the last one year for the simple reason that the US dollar had gone down, as also the US recession had affected the commodity market and...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): please conclude now.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, with all that, I would only make one suggestion here. Let us think of two things. Wherever we have a debate on price rise, let us not think of only supply line. You know you would talk about PDS, you would talk about import duty, you would talk about exports, all the trading and all the supply line. But what exactly has gone wrong is production agriculture. Agriculture remains the Achilles' Heel of the Indian economy. What we need is long-term measures. It is right that we need to get seriously into agriculture, see to it that the productivity goes up, see that the yield increase. Unfortunately, we have reached stagnation where 141 million acres still remain the same for the last 20 years. Although we talk about a second Green Revolution, there is not a single technology, which has been forthcoming ever since the first Green Revolution wherein the yield had gone up, usage of water, usage of seeds, soil conservation, all these things, need attention.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I shall make one last point. It is the States which should have taken up the responsibility. Sitting here, all of us have been blaming the Government, the Central Government all these years. Which is top sided. I will give the example of my own State. I don't say this because I hail from Andhra Pradesh. When we talked of free power, all of you had raised your eyebrows. We have successfully implemented. Again, today we are now giving rice at two rupees a kilo in Andhra Pradesh at a cost of Rs. 2000 crores subsidy. Why? It is because we know it is a temporary phase and Government has to come to rescue. Shri Ramachandraiah is here; they despised the Government. Now, why did we do it? Even DMK is doing it. In any temporary phase like this, State Government intervention becomes necessary and that necessity should be at the market level and that is what we are trying to do.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, there are six speakers including Rahulji. My request is, not to take more than five minutes each.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharasthra): Thank you, Mr. Vice-Chairman. This is a good example of democracy. All the parties speak forty minutes, thirty minutes or twenty minutes, but we independent get not even ten minutes. That is the Indian democracy. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Independents have got more time. They have already exhausted their due time ...(*Interruptions*)... This is all grace.

SHRI RAHUL BAJAJ: Sir, I don't envy your Chair. But there is an advantage of being independent, that is, I am not governed by the whip or the policy of any political party. I don't have to be partisan. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN(PROF. P.J. KURIEN): So, you can freely speak.

SHRI RAHUL BAJAJ: I always speak freely. I am concerned for the interest of the nation and in the interest of *amm adami.* I have heard about the fiscal measures; I have heard about the monetary measures and I have heard about the supply side measures. Sir, I would first refer to the three balance that we have to maintain in life and in business, and which this Finance Minister like every other Finance Minister has to maintain to solve this problem, to help the problem of inflation without hurting some other problem. What are these three things, which have come out from today's discussion? The short-term, which is required to be done, *versus* the longer-term. This short-term should not continue forever. Solve the problem, at least, in two, three or five years down the line. Today, elections are coming. We know, what happened in UP. Second is, the farmer *versus* the consumer. In short-term, I have to solve the consumer problem and in long-term I have to solve the farmer problem. Otherwise, the consumer problem will remain forever as farmer won't produce, and if there is shortage abroad you cannot import wheat. And the third thing, of course, is growth versus inflation. In short-term, I have to solve inflation and in long-term, I have to solve growth. I have heard the Finance Minister saying, and hope I am right, that he will be happy with four per cent inflation and eight per cent growth in the current circumstances. So, will I. But the inflation is remaining at 5,6, or 7.4 per cent and the growth is going below from 8 per cent to 7 per cent in the current fiscal year. So, that is the balance which is required to be maintained between the short-term and long-term, farmer and consumer interest and growth and inflation. But it is not at all easy to maintain this balance. It is very difficult. I support the measures to bring the import duty down to zero or very low,

wherever required, to reduce the prices. Whether it will help a little or much, it is a matter of debate. I support discouraging the export of terms which are in short-supply here like iron ore, steel, etc. I don't like banning. I am not the banning type. Though non-basmati rice has been banned, understandably. But where local domestic availability is weak or not available, we have to even ban. We have to take care of Indians first, not the rest of the world. Not even farmers or somebody else. I support these measures. But still, Sir, I don't know where is the nexus. I know, there are people employed in iron ore mines; I know our mines policy needs a review and public-private sector has to come in though my friend, Shri Raja, won't like public-private partnership. But I love the private sector and I am proud to say that. But, Sir, there is some nexus. I should discourage iron ore export, a steel production is the problem. I don't do that. Why? But don't put export duty on stainless steel, which is not a shortage item. Forty per cent price in the last twelve months has reduced and seventy-five per cent is being exported. Don't hurt the industry. It hurts growth. Similarly, Sir, I come to loans. Here, I am interested. Don't give credit to profiteers. How will you make distinction is a different matter and I don't have time to go into that. Nobody here has ever gone to jail; no politician, no bureaucrat, no industrialist. But, apart from that, the crooked person gains. This is the system here. Let's forget that. But, those items for which demand is more than supply there also, I think Shri Bimal Jalan said about demand. But, as I said, I am interested in some consumer durables, say vehicles today, for which there is excess capacity. I do not want the credit or loan. My customers wants it. You don't give him the loan. You are hurting growth. You are hurting rate of growth of GDP. You are not controlling inflation by that. So, we are mentioning about liquidity, increasing SLR, increasing CRR, and we are waiting for the policy of RBI. This is a balancing situation. You must, by all means, control inflation. Otherwise, industry gets hurt, *aam admi* gets hurt, fixed income *wala* gets hurt, the person who gets hurt maximum is the below poverty line guy. Of course, you should control inflation. But, as we say, you cannot distribute poverty by a smaller and smaller cake, and you will distribute poverty not growth, you have to grow the cake whichever way you want to grow. So, there is a global recession, including recession in the U.S. (*Time-bell*). I hope prices of some commodities, including steel and oil may, to some extent, moderate in the coming few months, I am not so sure, but in my part of the country, while prices of wheat, rice and everything are going through the roof, I do not go to buy that, but somebody who goes to buy those items told me that prices of onion and potato are stabilising. So, let us not also have a knee-jerk reaction and go overboard. In Maharashtra I wish Shri Sharad Pawar would have been here this water guzzling sugarcane is grown there. Please, correct that, Sir. Transfer that area, transfer that farmer to grains, to edible oils, to dal. It may take two or three years. But, in the long run, it will benefit. There is no water there; there is no power in Maharashtra and still you want to grow sugarcane. Let U.P. or some other States grow that. But, I do not know that are the political compulsions. If everything is going to be governed by political compulsions, then one day, those, who believe in those, who believe in those kinds of political compulsions, will be thrown out by the public. The public need their *roti, kapda, makaan.* They need *sadak, bijli and paani.* So, I am for curtailing inflation, but don't curb growth. I am for immediate short-term measures. But, don't hurt long-term interests which will become short-term tomorrow. Don't hurt the farmer; otherwise, you will have to pay the price tomorrow. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, Shri Kumar Deepak Das, You have five minutes.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Thank you, Sir, i will not take more time because we have already discussed the issue in an elaborate manner. Sir, nowadays, inflation has

gone up to 40 month high of 7.41 per cent. Prices of vegetables have gone up by 4.1 per cent; pulses and spices by 1.8 per cent and 1.2 per cent respectively. Similarly, steel prices registered a sharp increase of 5.6 per cent. That of *masoor dal* and *arhar dal* went up by 3 per cent. Prices of wheat and marine products went up by 1 per cent. Prices of milk and maize went up by 1 per cent. On the other hand, limestone prices went up by 14 per cent. Sir, this is the situation in the country. But, in our North-Eastern States, it is horrible. Most particularly, in hilly regions, it is vulnerable. Sir, prices of most food items have been increasing, as there is shortage of those commodities in the domestic market. By buying costlier commodities in the overseas market, India has been importing inflation. So, the Government has to adopt a specific policy on this issue. Sir, the best way to deal with international price rise effectively is to have a strong Indian rupee. Sir, the UPA Government in the last five years prevented the Indian consumer from benefiting from a strong rupee. This is a serious policy mistake done by the UPA Government.

Government should make efforts to increase the production of foodgrains and pulses in the country. India's productivity is one of the lowest and its irigation potentiality is the most neglected one. The way the UPA Government is fighting with this problem is anti-*aam aadmi.*

Sir, after all, it is the poor who suffers the most because his income is not inflation-indexed. Sir, inflation is regressive and the answer to this is to subsidise the poor and not everybody. The Government should take this sort of policy to fight against this problem. Without saying much, I conclude my speech with these suggestions. Thank you.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, on the 29th February, 2008, the Finance Minister made an announcement about the loan waiver scheme, which rung down the curtain on a horrific drama. Sir, as Mr. Raja's patron Marx said, "History repeats itself, first time as a farce and second time as a tragedy". I do not know whether first time it was a tragedy and second time it was going to be a farce.

Even before the ink on his statement started drying, he started taking measures that will put the farmers, once again, deep into debts. Going by the knee-jerk reaction that were taken, for example, as the Commerce Minister said, the customs duty were brought down on pulses and edible oils.

Whom does it affect? It affects principally the Indian farmers. It has not affected any exporting country because those countries immediately took measures to increase the export duties on farm produce, and, therefore, the entire burden has come on the indian farmers.

At the same time, the non-Basmati rice export was banned, and, even worse, the ban on the taking of positions on wheat and paddy, which was imposed last year, has still not been lifted. Further, the Finance Minister in the Budget Speech has imposed a tax of 0.017 per cent on the transactions in the commodity markets, which is really going to kill the market.

Now, each of these steps-even though it might look a knee-jerk reaction-actually means a concerted anti-farmer policy. These are the kinds of policies which were adopted in 1955 and ultimately resulted in negative subsidy for the farmers and their incapacity to repay the debts, and, therefore, the requirement to have a loan waiver. What is guaranteed now is that soon after this, within four or five years, there would be a turn for another loan waiver because you are going to ensure for the farmers will be put in debts.

Sir, the second point that I would like to make is that the suggestions that were made by Shri Sitaram Yechury bring out exactly what was done in 1950s. They had a system. We had the Agriculture Prices Commission; we had the CACP, then, we had the Food Corporation of India, and, we also had the PDS. Now, each of these constituted a straightjacket for the farmers, which resulted in bringing down of the prices, and, therefore, the poverty and indebtedness of the farmers. This is exactly what is being repeated now fifty years later.

Sir, the third point that I would like to make is about the future market. Sir, I am a Member of the Abhijit Sen Committee that has been referred to twice or thrice. I have not come across a single document that shows any connection between any inflationary trend and the future market transactions. I have not seen any document which shown any connection between the operation of the futures market and the volatility of the market. The principle is very simple. The futures markets give the farmers advance knowledge of the price he can expect at the time of harvesting which is something the CACP tries to do, put never successfully. Now, this permits the farmer even to lock at a price. Given the fact that there are purchasers who would like to purchase not immediately but three months or six months hence, and farmers would generally likes to get a price that would be prevailing three months or six months hence, there is a matching of the demand and the supply. But, if there were only farmers and the purchasers in the futures market, there would not be enough liquidity or depth in the market and, therefore, there is a legitimate role that has to be played by speculators. I think, Sitaram Yechury has an impression, and he actually used the words 'the den of dacoits' or something like that. Speculators are not dacoits; speculators are not gamblers; speculators are people who imagine that they have a more sophisticated knowledge of the market and, therefore, can take certain risks on the futures market. The position being that, I don't see why any restriction should be imposed on the futures market. The farmes have seen at the futures market from this point of view. After 30 years of struggle against the Government ...(*Interruption*)... After 30 years of struggle against the Government, what the Government did not give us, a completely free market, is being offered by technology. As it so often happens, the *aam aadmi* is supported more by the technology than by the political institutions.

I would now come to the last point, Sir. the reason why the Government has been taking immediate action is very simple. In a situation of inflation what is required to be done is to provide incentives to the producers on the supply side and restrict the purchasing power on the demand side. What is happening in the theory of inclusive growth is exactly the opposite. We have had the flagship programmes which are putting money into the hands of the sociely. We have recently had the Sixth Pay Commission which had already affected the market on the anticipation itself, even though a *paisa* has not been paid. But, the fact remains that is this is the *aam aadmi* economics, putting money in the hands of non-producers, putting the money in the hands of the consumers, then, I would say that inflation is an inevitable consequence of this so-called inclusive growth theory, and that is exactly what we are facing. The inclusive growth economics worked for sometime because in 2004 we got a fairly healthy and sound economy had and it continued till recently, till we got the phenomenon of climate change, the phenomenon of shortage of petrol which required the shift from food crops to the fuel crops. Now, that this has happened, I don't think the policies which we put unnecessarily prime the pump and put the money in the hands of the consumers and discourage the producers at the same time will work. The days of the inclusive growth theory are over. Think you

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to intervene now?

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: आपको भी समय देंगे फाइनेंस मिनिस्टर इंटरलीन कर रहे हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, this has been an interesting and instructive debate. I don't find Dr. Murli Manohar Joshi here. Be that as it may, I expected, of course, ablistering attack on the Government from all sides. But, I am happy to note that all the statements made in this House have been extremely reasonable, constructive. And, although the number of suggestions was precious few, the few suggestions are important suggestions and the Government will certainly bear in mind those suggestions while taking decisons. I may begin on a lighter note. We just heard Mr. Sharad Joshi. His position is a position which contradicts entirely what the Left says. Nothing that the Left says is acceptable to Mr. Sharad Joshi and nothing that Mr. Sharad Joshi says is acceptable to the Left. The point I am making is, not only a light-hearted point, it is also a serious point, there are fundamental diffrences in approach as to how inflation should be contained, how the current situation had developed and what are the responses to the curent situation. You also heard Dr. Bimal Jalan and Mr. Sitaram Yechury. Mr. Yechury said the bogey of liquidity and money supply is being raised to explain inflation. Dr. Jalan said it is liquidity and money supply which is driving inflation. Unfortunately, the Government cannot take these extreme positions. The Governemnt must adopt a position. Even if it is the position of Mr. Yechury, the Government has to adopt the position and reject the position of Dr. Jalan or accept the position of Dr. Jalan and reject the position of Mr. Yechury.There can't be any balances in these matters. What we try to do is balance inflation and growth. As correctly pointed out by everyone, no one wants to give up growth. Everybody wants growth but inflation should be moderate. That is what we have tried over the last four years and I am reasonably certain that everybody will agree that we have, to a large extent, succeeded in the last four years. We have growth averaging 8.8 per cent and we had inflation in the last four years averaging 6.5 per cent in the year we came to office, 4.4 per cent, 5.4 per cent and in the year that just came to an end at 4.5 per cent. So, the average for 2007-08 has been 4.5 per cent. What has queered the pitch is, after January, inflation has moved rather rapidly to the current level of 7.41 per cent. Sir, one must, therefore, I submit with respect, look into the causes as to why inflation sharply moved from under four per cent in January to 7.41 per cent by the end of March.

Sir, let me begin by saying, whether we like it or not, we are impacted by global trends. Without getting into all the reasons why we are impacted, the short point is, we are an importer of many goods and commodities. We import nearly 70 to 75 per cent of crude oil. We are a marginal importer of wheat because demand has picked up while production is more or less stagnant for the last ten years. We are a significant importer of palm oil. We are a significant importer of pulses. We are a large importer of fertilisers. Now, it can be nobody's case that we should not import crude oil or palm oil or pulses or fertilisers. And if we are a significant importer of these goods and commodities, necessarily, we have to be an exporter because how do we pay for these commodities? So, we have to be an exporter which is why India's trade policy has been liberalised to facilitate imports of essential goods and commodities as well as to pay for them through exports. So, we are, whether we like it or not, integrated with the global economy and impacted by global prices. Let us look at just a few commodities. I am only giving three figures. First, the figure of 2004, when the Government came into office or when the NDA Government left office. The figures earlier are even more benign, but, I am taking 2004 as a reference. Then, I take March 2007, one year ago. Then, I take March 2008. Crude oil was 37.7 dollars a barrel. Last year, it rose to 60.6 dollar a barrel in March, it was 102 dollars a barrel, and this morning, it is 112 dollars a barrel. I ask most respectfully one thing. Is there anything that you or I can do to reverse

this trend? Let us look at palm oil. In 2004, it was 471 dollars a metric tonne, in March 2007, it was 622 dollars a metric tonne, in March 2008, it was 1248 dollars a metric tonne. I ask again respectfully. Is there anything that you or I can do to turn this price back? Let us look at urea. In 2004, it was 175 dollars a metric tonne, in March 2007, it was 318 dollars a metric tonne, and in March 2008, it was 378 dollars a metric tonne. Shall we import urea, or shall we not import urea? And if we import urea, we have to import at this price, and we are importing inflation.

Last item, let us take wheat. We are a marginal importer of wheat. In 2004, it was 144 dollars a metric tonne, in March 2007, it was 168 dollars a metric tonne, and in March 2008, it was 440 dollars a metric tonne. The point I am making is, we are impacted by global prices. I am not taking shelter under global prices. Equally, you cannot dismiss it saying that the Government is putting forward an excuse of global prices. Global prices are neither a shelter nor an excuse. It is a fact. And we have been impacted by these prices. We have no way of rolling back these prices. We have to import at these prices to the extent that we require. But we have to take other steps so that overall inflation is moderate. Dr. Bimal Jalan is right. The single driver of inflation is money supply or liquidity. I am not a trained economist, and I am not trying to deliver a lecture on Economics. But that is, as I say, 101 Economics. The driver of inflation is liquidity. Now, as Mr. Rahul Bajaj said, one has to be careful about managing money supply because that is required to drive growth also. We provide credit, we put money in peoples' hands. I think, Shri Sharad Joshi criticised the Pay Commission. He said that you are putting money in peoples' hands. Now, shall we put money in the Government servants' hands or shall we not put money in their hands? After 10 years, is it possible to say that don't give any increase to the Government servants? We cut income-tax, we have put money into the pockets of tax-payers. Should we do that or should we not do that? We have got an NREG. Rs. twelve thousand crore has been pumped into the rural economy, into the hands of poor people, who otherwise did not have that kind of money. Shall we do that or shall we not do that? I have heard, at least, one or two thinkers/writers with the B.J.P., who questined the NREG. It is a good argument for me on a political platform. I will go to town saying if the BJP comes to power, it will withdraw the NREG. Perhaps, you will. I don't know. But shall we put money in the hands of the landless labourer? Shall we put money in the hands of the tax-payer? Shall we put money in the hands of the Government servant? If you do that, it increases money supply, it increases the expenditure, it will increase demand, and if supply does not catch up with demand, there will be inflation. The answer is not to put money in the hands of the purchaser, suppress demand, and then suppress inflation. do you want to do that? We can't do that, either. Therefore, Sir, the long-term answer, as everybody is agreed, is to take supply side measures. In the short-term, fiscal measures would work, in the short-term, monetary measures would work, but in the long-term, the only answer is to increase the supply side. Sir, the Agriculture Minister will come and give a detailed reply. But, as all of you know, we have put aside Rs. 25,000 crore and Rs. 4,882 crore on the two ambitious plans.The Rashitra Krishi Vikas Yojana and the National Food Security Mission, in order to increase rice production by 10 million tonnes, wheat production by 8 million tonnes and pulses production by 2 million tonnes. Why? Look at the figures. For the last 12 years, the production has flattened. I have got figures of 1995-96 to 2007-08. It includes the United Front Government, the NDA Government and the UPA Government. Now, what does it show? Rice production, the highest in the NDA, was 93.34 million tonnes. This year, we expect 94.08 million tonnes. The lowest in the NDA Government was 71.82 million tonnes. Wheat production, the highest in the NDA Government, was 76.37 million tonnes.

This year, we expect 75 million tonnes. The lowest, in the NDA Government, was 65.76 million tonnes. Pulses production, the highest in the NDA Government, was 14.91 million tonnes; the lowest was 11.07 million tonnes. This year, we expect 15 million tonnes. It clearly shows that over a ten-year period, we have not been able to break through this glass barrier, this glass shield. Rice at about 94 million tonnes is the ceiling. Wheat is at about 75-76 million tonnes, and pulses, at about 14.915 million tonnes. If supply does not increase, but demand increases because we are spending more; people are earning more, per capita income is increasing by about seven per cent a year, for the last five years. We are putting more money in the hands of people who, otherwise, did not have purchasing power, as, I think, Mr. Siva or one of you said. There is bound to be a supply-demand mismatch, and this is also afffecting prices. Therefore, Sir, to conclude this part, one is international prices; the second is liquidity or money supply, and the third is the supply-demand mismatch. We are addressing them seriously and sincerely. We have taken supply-side measures, which I have described. But supply-side measures take a little time to bear fruit. Fiscal measures; I have taken fiscal measures. I have not been adamant that I presented the Budget on the 29th of February and I should not sacrifice revenues immediately thereafter. In the Budget (paragraph 5, 6 and 7 of my speech). I anticipated inflationary pressures. I cautioned this House that there would be inflationary presssures. I took anticipatory steps by cutting the excise duty from 16 per cent to 14 per cent across the board. I cut the excise duty on a number of items; I reduced the excise duty to zero on a number of food items; I cut customs duties, and I cut income tax because I anticipated these pressures. But I have not been adamant. Even after the Budget, we have out customs duties; we have taken fiscal measures, which has already cost me almost Rs.6,000 crores. And I have said "I will not hesitate to take more fiscal measures even if it means sacrificing some revenue if that will tame inflation." Fiscal measures are measures which we have taken; these measures are well known, and we will continue to take whatever fiscal meaures are required to be taken.

The next is monetary measures. Sir, the RBI has already taken a number of measures on the monetary side. They have increased CRR eight times since December, 2006. CRR stands at 7.5 per cent. The repo rate was increased. It now stands at 7.75 per cent, and I am sure, the Governor is listening to this debate or he will read the debate tomorrow and he will take appropriate monetary measures when he feels it is appropriate to do so.

There was some reference, I think, in the other House or this House; I cannot say, that the food credit has expanded and that is credit to the hoarders and traders! Completely wrong. Where did you get this figure? In 2007-08, food credit has declined. Year-on-year, it has declined 5.1 per cent. In the financial year, it has declined 6.5 per cent. So, the food credit i not being increased. We have kept a tight leash on food credit. If anyone tells you that the food credit has been increased, banks are lending money to traders and hoarders to hoard food, it is completely wrong. Please do not believe in all that. It is a complete false propaganda. The food credit has actually declined. So, we will take monetary measures. I have described the supply side measures. Sir apart from this, the time has come not merely to talk tough, but to take some tough adminstrative measures. Here I seek the cooperation of all the sections of the House. In my Budget Speech, I had pointed out that there are indications of cartelisation and I have specifically mentioned steel and cement. Now, Shri Siva said that the cement industry, which did not heed my appeals, I am glad, heeded the appeal or threat of the Chief Minister of Tamil Nadu. But it is unfortunate that an industry will not heed the appeals but will only succumb to threats. If stronger measures are the only way that the indsutry will behave, I am sorry for the indsutry. Last year, the cement price was Rs. 158. Today, it is

7.00 P.M.

Rs. 258. Why? Is there any justification for the cement price to go up except that there is demand? There is demand for cement. There are construction of house buildings and roads and, therefore, the prices are going up. Therefore, either the industry must behave or we have to take tough administrative measures, or, we have to suppress the demand or contain the demand. The same is the story with steel. Thre same is the story with iron ore. Therefore, with a sense of responsibility, I appeal to the industry to realise the gravity of the situation and behave. If some sectors of the industry do not behave responsibly, the Government will have no option except to take tough, strong administrative measures to control the price. There is, or course, a role for the State Government. I am sorry, Shri Manohar Joshi is not here. I was impressed when he said that he spent only Rs. 700 crores for five years his State Government could keep the prices stable.

SHRI PRAKASH KESHAV JAVADEKAR: It is Rs. 700 crores per annum.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is right spend Rs. 700 crores pe annum and kept the prices stable for five years. Why didn't he share that magic formula with other Chief Ministers? Why don't they do that? It a State Chief Minister can say that, and he has the poweful endorsement and support of Shri Javadekar--we believe that his maiden speech would not be given to exaggeration--why do not all State Governments do that? The point is that the State Government has a role to play.

There were some exchanges between Shri Sitaram Yechury and the BJP Members. Let us get the facts clear. The notification issued by the NDA Government required the State Governments to seek prior approval of the Central Government before imposing any control. When this was pointed out, the UPA Government reversed the notification and gave the power to the State Government. The power is now entirely with the State Government. But are the State Governments exercising that power? Please let us search our hearts and ask ourselves a few questions. Are the State Governments exercising that power? I have got a list of actions taken by the State Governments. Some State Governments--mark my words--have imposed licensing requirements. That is all. Take a licence, do whatever you like. It is a licence to kill. Some State Governments have imposed stock limits. But when it comes to action, there have been 348 convictions under the Essential Commodities Act in the year 2007; 251 have been in the State of UP, 76 in Chhattisgarh, one, two and three in a few States and nil in many States. Now, what is the difficulty? If you have a stock limit, what is the difficulty in raiding a person and finding out whether he has got more than the stock limit? Once you find something more than the stock limit, what is the difficulty in prosecuting him? What is the difficulty in proving that prosecution? What is the difficulty in getting him convicted? Yes, the State Government can point a finger at the Central Government. I am not indulging in finger pointing. All that I am saying is that the Central Government takes fiscal steps, monetary steps and supply side steps and as I just said, we promise to take administrative measures, we should impress upon the State Governments to take action under the Essential Commodities Act. The Delhi Government did it recently. You have seen the results. I would urge all the State Governments to take action. I do not want to get into a long debate with anyone. I have noted the four suggestions of Shri Sitaram Yechury. In fact, he is no longer here. He has already written an article and I have noted it even earlier. His suggestion is, contain speculation and ban forward trading; the contra point of view is of Shri Sharad Joshi. I have already spoken to the Minister of Agriculture. Please remember the Abhijit Sen Committee was appointed on 29th February, 2007. I would only request Shri Sharad Joshi to please give us the report soon. Whatever your findings are, give us the report soon. I have already impressed upon the Minister of Agriculture—he is perhaps replying in the other

House at this moment—that this Abhijit Sen Committee report should be obtained and whatever decision the Government has to take should be taken. This is a matter under consideration. On money supply and liquidity, with great respect, if I have to choose between Dr. Jalan's position and Shri Yechury's position, all my instruction and information tells me, it is Dr. Jalan who is right. We have to contain liquidity, moderate liquidity because liquidity is a driver of inflation. It is not an excuse we are using, but it is well known that liquidity is a driver of inflation. The third one is reduce taxes on petroleum products. This again is a myth. In the Budget Estimates, we assume a certain economic growth; we assume certain excise duties on petrol and diesel. At the end of the year, I find I get less than what is assumed in the Budget Estimates. I am not getting any windfall. On the contrary, volumes have declined or prices have been so adjusted that we are not getting a windfall in petroleum taxes and diesel taxes. The last suggestion is strengthen the PDS. Why is it that people say that we are not strengthening the PDS? Why is it being stated that we are starving the PDS? Sir, I have got figures with me of the off-take of wheat and rice in the PDS. The real test is how much is the off-take from the PDS. Don't get excited. These are number, which are all there on the record. In 1998-99, wheat and rice together, 186 lakh tonnes was the off-take; in 1999-2000—170 lakh tonnes; 2000-01—120 lakh tonnes; 2001-02-138 lakh tonnes; 2002-03—200 lakh tonnes; 2003-04—239 lakh tonnes. The highest off-take in the NDA period was 239 lakh tonnes. In the UPA period, in 2004-05, it was 293 lakh tonnes; 2005-06—310 lakh tonnes; 2006-07—313 lakh tonnes; 007-08, up to December alone, 244 lakh tonnes. We don't have the figures yet for the last three months. We are not starving the PDS. Whatever we are procuring we are putting into the PDS and we have kept the prices constant. But the PDS itself is a leaking PDS. Thirty-six per cent of foograins given to the PDS do not reach the beneficiary. I have mentioned those figures in my Budget reply that 36 per cent do not reach the beneficiary. Now I again ask humbly and respectfully, "Who is in charge of the PDS?" Is the Central Government in charge of the PDS? Our responsibility lies in giving foodgrains to the PDS. Yes, there are some complaints from Kerala. I am sure Shri Sharad Pawar will address those complaints. I will tell him to address those complaints.To the best of my ability, I will impress upon him to address those complaints. That is not the issue today. But whatever is given, does that go to the beneficiary? (*Interruptions*). West Bengal also. Whichever State requires, they have to be given. I am not sure he is being partisan. He is trying to do what best he can. But I will tell him to do better than his best. But the point is not that. The point is, whatever is given, does it reach the beneficiary? The finding is, 36 per cent is leaked into the open market. Then why does not the State Government take action? Who can take action? Can I take action against the ration shops? Can I take action against the Civil Supply Department of the State? Therefore, all I am asking is while we take measures, why don't the State Governments also take some measures. I am asking the State Governments only two things. One, invoke the Essential Commodities Act and take strong action against hoarders and profiteers. Is that too much to ask? The second thing, which I am asking is, make sure that the PDS works properly, that there is no leakage or only a minimum leakage, and the foodgrains actually reach the people.

With these words, let me conclude. I know there were some political statements here and there. My old friend, Shri Janeshwar Mishra, a colleague of mine in the United Front Government, made a number of political references. These were quite unnecessary. In fact, It was tempted to speak in Tamil, after he berated me for speaking in English. I would love to speak in Tamil at every opportunity. But since I cannot speak Hindi, I have to speak in English. But, I think, there is nothing wrong in speaking in English or Tamil. Next time if

you allow me to speak in Tamil, I will be happy to speak in Tamil. The point is, we must work together to tame inflation. when we say, inflation is a global phenomenon, let us not take it as a caricature of an issue. It is a genuine problem. Inflation is indeed a global phenomenon. Countries with systems different from ours, countries with systems similar to our systems, ountries with better governance structure, countries with worst governance structure, all of them are affected. We had the Finance Minister of South Africa, who told me that inflation is 9 per cent. We have the Finance Minister of Egypt, who told me that inflation is 12 per cent. Look at other countries. China's inflation was 8.7 per cent, and this morning, it was 8.9 per cent. In South Africa, it was 9.8 per cent; in Chile, it was 8.5 per cent; in Pakistan, it was 11.3 per cent. Even Singapore and Hong Kong, which are supposedly stable economies, have inflation of over 6 per cent. In Venezuela, it is 25.2 per cent...(*Interruptions*) We are not comparing with States which have failed. We are comparing with States which are governed well. The point is, we will do our best. We are impacted by the global factors. We are impacted by the liquidity. We will do our best. We will take fiscal measures; we will take monetary measures; and we will take the supply side measures. And, as I have just said, we will take administrative measures. Let the States take equal measures on the side of the Essential Commodities Act and the PDS. Let us works together to tame inflation. This is not unusual. We had periods of inflation, where it was over seven per cent. When this Government came into office, the inflation had already crossed 7 per cent. We tamed it; we brought it down to 3.11 per cent in November, 2007. In January, ...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: You are again and again blaming the State Government.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not blaming anybody. I am asking them to cooperate.

SHRI S.S. AHLUWALIA: After inflation crossed 7 per cent, did you call any meeting of the State Chief Ministers and discussed that matter?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will answer. No. 1: the Minister of Agriculture has spoken with every Chief Minister and requested them to take action. No. 2; the Prime Minister has written a letter to the Chief Ministers asking them to take action. Please understand that in this age of technology, you don't have to meet to convey each other's views. There is fax; there is telephone; there is video-conferencing. We will call a meeting...

SHRI S.S. AHLUWALIA: That would give a message to the market.

SHRI P. CHIDAMBARAM: We will call a meeting. I think the Prime Minister has contemplated a meeting; I cannot say for sure. In the meanwhile, he has written a letter to the Chief Ministers. The Minister of Agriculture speak to the Chief Minister virtually every day. All I am saying is that we will tame this inflation this time also. There are some factors beyond control, as I said in the beginning. But we will make every effort to contain this inflation. But the most important point is, as Mr. Bimal Jalan said, not to panic; not to politicise it; not to take panicky measures, but take measures on the fiscal, monetary and supply side, and contain inflation, even while not sacrificing too much growth. If I have to sacrifice some growth, let us sacrifice it. If we have to sacrifice some revenues, let us sacrifice it. Revenues are badly needed for social sector. But we will make some sacrifice. We will tame inflation. But let us work together in a spirit of co-operation.

श्री प्रकाश केशव जावडेकर: सर एक ही खुलासा चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं, यह तो इंटरवेंशन था। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश केशव जावडेकर: सर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, जो अभी हमने सुना। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: कल रिप्लाई होगा, कल पूछ लेना। श्री राजनीति प्रसाद।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभापति महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं और उनके बाद मुझे बोलने का चांस मिला है, तो यह परम्परा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना है।

श्री उपसभापति: उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, इंटरवीन किया है, परम्परा है।

श्री राजनीति प्रसाद: प्वाइंट यह नहीं है, प्वाइंट यह है कि हमारी बात को भी सुनकर ये जवाब देते।

श्री उपसभापति: कल देंगे।

श्री राजनीति प्रसाद: इन्होंने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। इन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। जब हम सुन रहे थे तो हम खुद भी कन्वींस हो रहे थे कि मंत्री जी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, वे सही हैं और इन्होंने यह भी बताया कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ी और कैसे इसका निवारण किया जाए। जब हम लोग कोर्ट में खड़े होते हैं, तो अपोजीशन पार्टी के लोग जब बोलते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं और हम जब बोलते हैं तो वे भी हमारी बात सुनते हैं। जब वे बोलते हैं तो लगता है कि उनकी बात सच है और फिर जब हम बोलते हैं तो लगता है कि हमारी बात सच है। सर, इन्होंने वकील की तरह जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, वे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हैं या गलत हैं, उनके बारे में हम जानना नहीं चाहते और न ही जानते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि यह महंगाई आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है और जो गरीब लोग हैं, उनको कैसे राशन मिलता है, कैसे सब्जी मिलती है और उनका कैसे दिन गुजरता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है और कैसे हम इम्पोर्ट करते हैं, कैसे हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन, एक बात जरूर है और वह मैं कहना चाहूंगा कि एक काम हमारी इस सरकार ने जरूर किया है कि जब महंगाई का रेश्यो बढ़ा, तो इन्होंने केबिनट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि महंगाई पर कैसे रोक लगाई जाए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसकी चिंता सरकार को थी और वह चाहती थी कि किसी भी तरह से महंगाई को रोका जाए। महंगाई रोकने का काम जब शुरू हुआ, तो उससे थोड़ी-बहुत तो महंगाई जरूर रुकी है, इसमें कोई शक नहीं है।

सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उसे कई लोगों ने भी कहा है। श्री शरद जोशी जी यहां बैठे थे, उन्होंने कहा था कि फारवर्ड मार्किटिंग पेनिक नहीं है, लेकिन फूड सप्लाई में जब हम लोग वहां बैठते हैं, श्री मतिलाल सरकार जी भी उसमें हैं, हम लोगों ने कहा कि 30-40 साल पहले फारवर्ड मार्किट, वायदा बाजार में टेलिफोन पर लोग माल खरीदते थे, टेलिफोन पर माल खरीदकर उसका वितरण करते थे और वहीं बात फिर यहां आ गई है। मेरा यह कहना था कि फारवर्ड मार्किटिंग को निश्चित रूप से बंद करना चाहिए और यदि आप इसको बंद करेंगे तो महंगाई पर रोक लगेगी। अभी लगभग एक साल पहले हमने यू॰पी॰ए॰ चेयरपरसन, मैडम सोनिया गांधी जी से मुलाकात की थी। हमारे डेलिगेशन में श्री लालू यादव जी भी थे और हम लोग भी थे। उन्होंने कहा कि जो फारवर्ड मार्किटिंग, वायदा बाजार है, उसमें से गेहूं को, चावल को आप निकालिए। जैसे ही उसको निकालने का काम हुआ, वैसे ही चावल और गेहूं का दाम कम हो गया। उसी तरह से फारवर्ड मार्किट को अगर हम लोग कम्प्लीटली क्लोज़ कर देंगे तो जो बहुत ज्यादा होल्डिंग करने की परम्परा चली है, वह परम्परा खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारी गोदाम में माल कम रहता है ओर प्राइवेट ट्रेडर्स के यहां माल ज्यादा रहता है और जब उनके पास माल ज्यादा रहता है तो दाम उनके मुताबिक तय होता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस देश के आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हमें चिंता करनी चाहिए और यह जो यू॰पी॰ए॰ की सरकार है, इसे उनकी चिंता है।

अभी हमारे बी॰जे॰पी॰ के भाइयों ने कहा कि आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। सर, हम किसानों के लिए कर रहे हैं, यू॰पी॰ए॰ की सरकार ने किसानों के 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया है। यू॰पी॰ए॰ की सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ किया है। उपसभापति जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)... आप मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापतिः आप बोलिए, हम भी सुन रहे हैं, मंत्री जी भी सुन रहे हैं।

श्री राजनीति प्रसादः मैं भूल जाता हूं, मेरा लिंक टूट जाता है। मैं कह रहा था कि BJP की सरकार ने जो परंपरा चलाई थी, अगर उसी परंपरा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यह महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि उनकी परंपरा, होर्डिंग करने वाली परंपरा थी। आज जहां-जहां माल पकड़ा गया है, उसकी आप जरा इंक्वायरी करिए कि कहां से पकड़ा गया, कौन लोग ये सब काम कर रहे हैं? जब आप इसकी इंक्वायरी करेंगे, तो पता लगेगा कि इनके लोग वहां बैठे हुए थे। श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी सरकार चली जाएगी। उनको महंगाई की चिंता नहीं है, महंगाई कैसे खत्म होगी, इसकी चिंता नहीं है, आपकी सरकार जाने वाली है, इसकी ज्यादा चिंता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई को बढ़ाने में इनकी जरूर कोई conspiracy है, अगर इनकी conspiracy नहीं होती,तो वे यह नहीं कहते कि आपकी सरकार जाएगी। जब प्याज के दाम बढ़ गए थे, तो सरकार इनकी भी गई थी, आपकी सरकार भी महंगाई के कारण गई थी, लेकिन उसमें हमारी कोई conspiracy नहीं थी। एक महीने के अंदर जो दाम बढ़े हैं, वे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जो होर्डिंग करने वाले लोग थे, वे आपके लोग थे, उन्होंने होर्डिंग करके, पूरे देश में होर्डिंग की परंपरा चलाई और इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। महंगाई को बढ़ाने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं।

SHRI TARLOCHAN SINGH (Haryana): Sir, I have been listening to the debate with great interest, and I have a few points to make. I hope, from both the sides, they will listen to it. Number one, we have not touched the main issue, *i.e.* population explosion. No political party is ready even to mention it in its manifesto. The whole problem revolves around the growth of population, and this issue has to be tackled somehow; otherwise, what we are doing will further add to the problem which we are facing today. What has China achieved? It has achieved population control. What has Europe achieved? Every country, except India, has now taken some measures and some checks on population growth.

Secondly, Sir, what has happened is that. The land under cultivation is going down and down. Rapid urbanisation is taking place. Sir, see Delhi. Is there any agricultural land left within 100 miles around Delhi? Is any vegetable garden left? Is any dairy farm left? Who has done it? Everyday, there is a demand for more and more colonies. All these colonisers are in collusion with the officers and the Government and they are doing this. Sir, here, I will give you two examples. Punjab and Haryana are the only States which produce the maximum foodgrains for the country. Sir, the previous Government of Punjab, there was Congress Government for the five years, I don't want to blame that Party, but what they did is this. During that time, no industry came to Punjab. What they did was, they invited all colonisers of Delhi to Punjab. See Ludhiana, where the agriculture revolution was born. Eighty miles around Ludhiana there are all colonies like Amritsar, Chandigarh,etc. So, the State Government took pride in it and said that they were brining more money in the State. Then, what happened? Every agriculturist started to sell his land, and the land prices went very high. The land prices near Ludhiana are about Rs. 1 crore per acre. So, what is the result? All agricultural land was sold. I represent the State of Haryana. We feel proud in representing our State. Our Chief Minister is saying everyday that the maximum SEZ are coming in Haryana. So, all agricultural land of Haryana will come under SEZ or under colonies. What will be produce there? If Punjab and Haryana are not going to have land, where will we produce our foodgrains? Secondly, if both these States, the water level is going down. In another 10-15 years, the land in these States will become barren.

Thirdly, there is no incentive for producing pulses. What are the prices of pulses today? Has the Government of India given at any time any incentive for producing pulses? We must give incentives to the farmers. Just now the Finance Minister said that the wheat price in the

world is above Rs. 2,000 a quintal. Here, you pay just Rs. 1,000! You are willing to import at the rate of Rs. 1,600 per quintal. But you do no want to give Rs. 200 as bonus to the farmer. So, no incentive to the farmer! Urbanisation, SEZ, and population growth, all are leading to a state where, for years to come, we will face this problem. This is not a temporary phenomenon. This will happen in future also if all political leaders do not sit together and try to solve the problem.

Sir, we are telling everyday that you are giving loan waiver of Rs. 60,000 crores. I doubt on what will happen. The farmers in future will get incentives and may no pay back the loan hoping that after five years again there would be a loan waiver. Secondly, even the banks may not be willing to give loans to the famrers. By this loan waiving you are trying to solve the problem; but you are not going to solve the real problem. The problem can be solved if the farmer feels that he earns money out of the land, if there is more income to him. Only giving loan and incentive on loan is not going to help the farmer, Unfortunately, Sir, the present Government leadership and senior leaders have never seen agriculture. They cannot differentiate between wheat and maize because nobody is coming from the rural areas except a few Ministers. But they have not the mainsay. The main authorities are those who do not know what agiruclture is. That is the biggest tragedy we are facing. Unless you get proper farmer leaders to sit together and then solve, it would be difficult.

We say 'Swaminathan'. Every political party is quoting him. But you are not going to implement it. My plea is, stop competing with the NDA. After all, why are we competing in certain issues which are national issues? Blaming what the NDA did is not going to solve the problem. Now, the people are laughing at the Sensex. People in the villages ask me, "कि भाई सेंसेक्स ही बना दो, हम वहीं खा लें।** Because everyday you say our achievement in Sensex is 4000, 5000..... लोग समझते हैं कि यह भी खाने की चीज है, वह हमें दे दो, तो सेंसेक्स लोगों को खाने को दे दें। And we are reading, "Car prices have come down with the new Budget." So, what is the benefit to *aam admis*? So, Sir, these are the measures that we are pursing. I request that the main policy of the Government should be to help the farmer, save the agricultural land, not to give land to these colonisers which will further kill the whole system and the whole system will get spoilt. India will suffer. All political parties, all leaders are the same, all States are the same. The policy of Tamil Nadu and Punjab Government is that they are subsidising on food. Wherefrom this money would come? It is again the taxpayer's money. Then every State would start this! They would subsidise food and that will not solve the problem. That will further complicate the problem. The States should not have this policy; the political parties should not have a slogan like this. We should go to the bottom of the problem and resolve the problem. Thank you for giving me this opportunity.

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): अभी महंगाई और जमाखोरी के प्रश्न पर बहुत चर्चा की गई है।

श्री उपसभापति: ये सिर्फ suggestion देंगे।

श्री बनवारी लाल कंछल: सर हां, suggestion दूंगा और पांच मिनट लूंगा। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार सालों में इस देश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? जमाखोरी और मुनाफाखोरी कारगिल कंपनी कर रही है, ITC जैसे बड़े कारपोरेट घराने, मुकेश अंबानी जैसे बड़े घराने कर रहे हैं। पिछले साल एक कारपोरेट घराने ने पूरे देश का सेब 15 रुपये किलो में खरीदा और 100 रुपए किलो की दर से पूरे देश में बिकवाने का काम किया। जो हमारे गरीब लोग ठेला वालों से बीस रुपए किलो खरीदते थे, वह सेब सौ रुपए किलो पर खरीदने को मजबूर कर दिया। डाबर कंपनी ने पूरे देश की लीची खरीद कर महंगी करा दी, एक कारपोरेट घराने ने पूरे देश का अंगूर खरीद करके मंहगा करा दिया और जब मंत्री महोदय

अखबारों में जमाखोरी का बयान देते हैं तो आम जनता की समझ में आता है कि यह जमाखोरी और महंगाई आम व्यापारी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जमाखोरी और महंगाई व्यापारी नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि कारपोरेट घराने बढ़ा रहे हैं। हम दो साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जंतर-मंतर पर धरना दिया, कितने question लगाए, जेल में धरना दिया, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना दिया, कि इन कारपोरेट घरानों पर अंकुश लगाया जाए। कारपोरेट घराने और चंद पूंजीपति किसानों को किलो में एक रुपया ज्यादा देकर पूरे देश का गेहूं खरीद लेते हैं और किसान सोचते हैं कि हमारा फायदा हो गया। बाद में 7 रुपए का गेहूं 8 रुपए में खरीदा और 16 रुपए में इन कॉरपोरेट घरानों ने गेंहू बेचने का काम किया है, चावल बेचने का काम किया है, इसलिए मैं मांग करता हूं। महंगाई के बारे में, अभी जैसे हमारे वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तमाम बातें उन्होंने बता दीं कि फलाने देश में महंगाई बढ़ी, फलाने देश में महंगाई बढ़ी। अस्सी करोड़ लोग जो 20 रुपए में गुजारा करते हैं, वे इस बात को नहीं जानते हैं कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी, रशिया में महंगाई बढ़ी है। वे यह जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो भुने हुए चने 18 रुपए किलो मिलते थे और आज वही भुने हुए चने 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। सरसों का तेल 40 रुपए किलो था, आज वह 75 और 80 रुपए में मिल रहा है। दाल के दाम बढ़ गए हैं। मकान बनाने के लिए लोहा पहले 25 रुपए किलो था और आज वह 51 रुपए किलो बिक रहा है। सीमेंट का दाम 120 रुपए था, आज वह 220-225 रुपए में बिक रहा है। आम अस्सी करोड़ जनता न तो आपके आंकड़ों पर विश्वास करती है और जो आप दुनिया भर का नक्शा दिखाते हैं, न उससे उनका कोई मतलब है। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर चना सस्ता हो गया, तो वे कहेंगे कि सरकार अच्छी है और अगर चना महंगा हो, तो वे कहेंगे कि सरकार खराब है और वहीं लोग वोट देने वाले हैं, वही लोग सरकार को बनाने वाले हैं। महादेय, महंगाई घटाने के लिए मैं केवल दस सुझाव दूंगा, क्योंकि हमारे साथियों ने कहा कि सुझाव नहीं देते। पहला सुझाव तो यह है कि वायदा व्यापार को समाप्त किया जाए। इसमें केवल पंद्रह-बीस चीजों को नहीं। मुझे पता लगा है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें केवल दस-पंद्रह खाद्य पदार्थों पर घटाने के लिए कहा है। लोहे पर यह क्यों नहीं समाप्त होना चाहिए? सीमेंट पर क्यों नहीं समाप्त होना चाहिए? सोना 13,000 रुपए तोला बिक रहा है, कोई ग्रामीण आज सोना-चांदी नहीं खरीद सकता, तो क्यों नहीं उस पर खत्म होना चाहिए? अल्युमिनियम पर क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? तांबा, जस्ता के दामों में चार गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई है, लोग बरतन नहीं खरीद पाते हैं, क्यों नहीं वायदा व्यापार उस पर खत्म होना चाहिए? सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वायदा व्यापार डाकुओं का अड्डा है, वायदा व्यापार पूरे देश से खत्म होना चाहिए और अगर यह सरकार वायदा व्यापार नहीं खत्म करती है, तो इसका सीधा संदेश जनता में यह जाएगा कि सरकार में बैठे हुए मंत्री भी वायदा व्यापार करने वाले लोगों से पैसा ले रहे हैं और महीना पा रहे हैं, इसलिए वायदा व्यापार को खत्म नहीं कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप प्वांइट्स बोल दीजिए। आप दस प्वाइंट्स को explain करेंगे, तो बीस मिनट लग जाएंगे।

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा प्वाइंट आ गया। पूरे देश में वैट लगाने से दस परसेंट महंगाई बढ़ी है। वैट मल्टीपल टैक्स है, अगर वैट लगाना है, तो आप सिंगल प्वाइंट टैक्स अगर कर दें, तो दस परसेंट महंगाई कम हो जाएगी। सर्विस टैक्स आपने हर चीज़ में बढ़ा दिया-बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, बस में जाओ, रेल में जाओ, हवाई जहाज़ में जाओ-सब जगह सर्विस टैक्स। अगर सर्विस टैक्स की दरें साढ़े बारह परसेंट से घटाकर पांच परसेंट कर दी जाएं, तो पांच परसेंट, सात परसेंट महंगाई इस देश में कम हो जाएगी। डीज़ल, पेट्रोल पर आपने कहा कि पूरे देश में महंगाई है, पूरे वर्ल्ड में दाम बढ़ गए हैं। आपने टैक्स का इतना रेट क्यों बढ़ा रखा है? वित्त मंत्री जी चले गए, वे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता। महाराष्ट्र में डीज़ल पर 45 परसेंट सेल्स टैक्स है वैट का, उत्तर प्रदेश में 32 परसेंट है, 26 परसेंट है कहीं पर, कहीं पर तीस परसेंट है, पूरे देश में डीज़ल, पेट्रोल पर टैक्स की वैट की दरें दस परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप वैट दस परसेंट कर दें, तो यह आपके हाथ में है। चिदम्बरम साहब उस कमेटी के सदस्य हैं, असीम दासगुप्ता उस कमेटी के सदस्य हैं। अगर आप इसे दस परसेंट कर दें, तो इस देश में दस रुपया लीटर डीज़ल कल सस्ता हो जाएगा।

महोदया, वैट में जितने खाद्यान्न हैं, उनको करमुक्त होना चाहिए, परंतु हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट में चार परसेंट टैक्स लगा रखा है, पंजाब सरकार ने वैट पर चार परसेंट टैक्स लगा रखा है। हम कहते है। कि केंद्र सरकार

को सख्ती से कदम उठाने चाहिए और मुख्य मंत्रियों को कहना चाहिए कि खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं होगा, वह करमुक्त होगा। बंगाल, बिहार-इन सबने करमुक्त कर रखा है, उसी तरीके से जिन प्रदेशों ने वैट पर टैक्स लगाया है, वह खत्म होना चाहिए।

इसके बाद कॉरपोरेट कृषि और कॉरपोरेट रीटेल पर टोटल अंकुश लगना चाहिए। इन्हीं लोगों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है, ज़मीनों के दाम बढ़ाने का काम किया है। अभी एक साहब बोल रहे थे कि कृषि की भूमि खत्म होती जा रही है। कृषि की भूमि कौन खत्म कर रहा है? कॉरपोरेट घराने खत्म कर रहे हैं, इसलिए कॉरपोरेट घरानों के लिए Shopping Mall Regulation Act बनाकर इनका नियमन किया जाना चाहिए और न ये खेती करें, न ये खुदरा व्यापार करें। खुदरा व्यापार को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। खेती, खुदरा व्यापार और लघु उद्योग में एफ.डी.आई. पर रोक लगाई जाए। चावल, चीनी, लोहा और खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी रोक लगाई जाए। लोहा अभी चीन जा रहा है, चीन ने महंगा कर दिया। हमसे चमड़ा खरीदते हैं। हमारे यहां के जूते बिकते नहीं हैं लेकिन चीन के जूते हमारे यहां बिक रहे हैं। हमारा चमड़ा निर्यात हो रहा है। चमड़े के निर्यात पर भी रोक लगायी जाए। इसी प्रकार मांस के निर्यात पर रोक लगायी जाए। मांस बहुत महंगा हो गया है। अभी मैं बंगाल गया था, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें मांस खाने को नहीं मिल रहा है, उसका निर्यात हो रहा है। इसके अतिरिक्त एमआरपी छापने के लिए कानून बनाया जाए। कोई चीज़ दस रुपए की है लेकिन उसका एमआरपी सौ रुपए छप रहा है सरकार का कोई कानून पूछने वाला नहीं है कि दस रुपए की चीज़ पर सौ रुपए एमआरपी क्यों छाप रहे हैं। पचास रुपए की चीज़ पर तीन सौ रुपए एमआरपी छप रहा है। एमआरपी छापने के संबंध में कानून होना चाहिए कि कितना परसेंट उद्योगपति लेगा, सामान बनाने वाला कितना परसेंट मुनाफा लेगा - चाहे दवा हो, चाहे लोहा हो, चाहे cosmetics की चीज़ें हों या दूसरी चीज़ें हों - एमआरपी का एक कानून बनना चाहिए। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। किसानों को अमेरिका की तरह सब्सिडी दी जानी चाहिए, दूसरे देशों की तरह सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि हमारी फसल बढ़ सके। किसानों को लाभ का एक मूल्य दिया जाना चाहिए। अगर ये दस उपाय कर लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि महंगाई तुरंत कम हो जाएगी। महंगाई पर आंकड़े न दीजिए, महंगाई को कम करने के लिए केबिनेट की मीटिंग बुलाइए, उसमें निर्णय लीजिए और वह निर्णय जनता के सामने रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate on price rise has concluded. Only the Leader of the Opposition will be speaking before the Minister replies. The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at thirty-one minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th April 2008.

GMGIPMRND—3799RS—27-5-2009.